सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

अग्रिम प्राधिकार योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

(राजस्व विभाग – अप्रत्यक्ष कर – सीमा शुल्क)

2021 की संख्या 10

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

अग्रिम प्राधिकार योजना
पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
(राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क)
2021 की संख्या 10

(लोकसभा/राज्यसभा के पटल पर.............. को प्रस्तुत किया गया)

विषय सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	i
2	कार्यकारी सार	iii से xv
3	शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली	xvii से xix
4	अध्याय I : अग्रिम प्राधिकार योजना का विहंगावलोकन	1-14
5	अध्याय II : अग्रिम प्राधिकार जारी करना	15-49
6	अध्याय III : योजना का कार्यान्वयन	51-99
7	अध्याय IV : आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन	101-112
8	परिशिष्ट और अनुलग्नक	113-125

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 'अग्रिम प्राधिकार योजना' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है जो 2019-20 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए और जिनमें अप्रैल 2015 से मार्च 2019 की अवधि के संव्यवहारों को शामिल किया गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखापरीक्षक दिशा-निर्देशों के अनुसार यह लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त हुए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में

अग्रिम प्राधिकार योजना (एएएस) का उद्देश्य मूल्य वर्धन की निर्दिष्ट प्रतिशतता के साथ विनिर्मित माल के निर्यात की शर्त के अधीन भारत में सीमा शुल्क के भुगतान के बिना अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर पंजीकृत निर्यातकों को उनकी मूल्य इनपुट/कच्ची सामग्री की आवश्यकता पूरी करना है। इस योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) और सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्राधिकार का जारी करना, उपयोग, मोचन और कार्यान्वयन एक फलोत्पादक और प्रभावी तरीके में किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में योजना के क्रियान्यवन में शामिल अन्तर-विभागीय समन्वयन की प्रभावकारिता तथा क्या राजस्व हानि, योजना के दुरूपयोग आदि को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण उपाय पर्याप्त हैं, की भी जांच की गयी । लेखापरीक्षा में डीजीएफटी, इसके क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) एवं सम्बन्धित सीमा शुल्क आयुक्तालयों के माध्यम से सम्बन्धित सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं को शामिल किया गया।

पूरे भारत में कुल 38 आरए हैं जिनमें लागत, बीमा और भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य को शामिल करते हुए ₹7,58,141 करोड़ के आयातों के लिए 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान कुल 88,157 अग्रिम प्राधिकार (एए) जारी किए गए जिन्हें निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल किया गया। यह लेखापरीक्षा दिसम्बर 2019 और मार्च 2020 के बीच की गयी। कुल 38 आरए में से 23 प्रमुख आरए (60.52 प्रतिशत) में 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए ₹2,08,126 करोड़ (29.56 प्रतिशत) के सीआईए मूल्य वाले 4,048 एए फाईलों (4.96 प्रतिशत) के नमूने का लेखापरीक्षा में चयन किया गया। लेखापरीक्षा में क्षेत्राधिकारिक सीमा शुल्क के उन क्षेत्रीय कार्यालयों का भी चयन किया गया जहां शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों को प्रभावित करने के लिए चयनित नमूने मामले पंजीकृत थे।

4,048 चयनित मामलों में से, सात आरए (मुख्यतः मुम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली) ₹9,906.73 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 405 एए फाईल आरए को बारंबार अनुरोध करने/अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवदेन में 66 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां और 17 सिफारिशें शामिल की गयी हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹1,386.80 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है, जिसमें से ₹1,291.93 करोड़ की राशि वाले 44 अभ्युक्तियां डीजीएफटी/राजस्व विभाग (डीओआर) द्वारा स्वीकार किए गए, ₹0.24 करोड़ की राशि वाले पांच पैराओं में कार्रवाई/वसूली की अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था और ₹94.61 करोड़ की राशि वाले 17 अभ्युक्तियां डीजीएफटी/डीओआर द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। अब तक आठ पैराओं के सम्बन्ध में ₹0.70 करोड़ की वसूली की गयी थी। इसी प्रकार, 17 सिफारिशों में से 11 को डीजीएफटी/डीओआर द्वारा स्वीकार किया गया है; पांच सिफारिशों (सिफारिश-1, 3, 6, 11 और 12) के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित था और एक सिफारिश (सिफारिश 7) को स्वीकार नहीं किया गया था।

अध्याय I : अग्रिम प्राधिकार योजना का विहंगावलोकन

योजना डीजीएफटी द्वारा क्रियान्यवित की जाती है जबकि आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से छूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन डीओआर द्वारा अनुमत की जाती है।

लाइसेंस के लिए आवेदन डीजीएफटी के अधीन क्षेत्राधिकारिक आरए को प्रस्तुत की जानी होती है, जैसा कि क्रियाविधि की पुस्तिका (एचबीपी) में निर्दिष्ट किया गया है। आरए आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन करता है और लाइसेंस जारी करता है, जिसे फिर लाइसेंस के अन्तर्गत माल के आयात और निर्यात को अनुमत करने के लिए निर्दिष्ट सीमा शुल्क पत्तन के साथ पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण सीमा शुल्क विभाग के पास बांड, और यदि आवश्यक हो तो बैंक गारंटी (बीजी) के कार्यान्वयन के अधीन होता है। निर्यात दायित्वों (ईओ) के निर्वहन पर, प्राधिकार धारक (एएच) आरए को मोचन का

एक आवेदन करता है, जो एएच को एक निर्यात दायित्व प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी करता है और यदि कोई बांड और बीजी हो, के मोचन के लिए सीमा शुल्क विभाग को उसकी एक प्रति भेजता है।

परिणामी उत्पाद के सम्बन्ध में इनपुट के लिए एए जारी किया जाता है जो कतिपय प्रतिमानों पर आधारित होता है जैसे मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अथवा स्वत: घोषणा पर आधारित, स्वत: संपुष्टि योजना या आवेदक विशिष्ट पूर्व नियत किया गए मानदंड, जहां एसआईओएन अधिसूचित नहीं किया गया हो।

(पैरा 1.1, 1.2)

निष्पादन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल की गयी अवधि के लिए एए योजना विश्लेषण से पता चला कि निर्यातों का पोतपर्यंत नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य 2015-16 में 25 प्रतिशत तक बढ़कर ₹3,03,539 करोड़ से 2018-19 में ₹3,78,808 करोड़ हो गया।

सीआईएफ के तहत एए के खंडीय विश्लेषण में 2015-16 से 2018-19 तक रत्नों व आभूषणों और हथकरधा के सम्बन्ध में गिरती हुई प्रवृत्ति तथा इलेक्ट्रानिक्स, कपड़ा, रसायन, चमड़ा आदि में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शायी गयी। 2018-19 तक, रसायन, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक क्षेत्र, एए के कुल सीआईएफ मूल्य का तकरीबन 82 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान प्रभावी कुल प्रत्यक्ष निर्यातों की तुलना में एए में नियत किए गए एफओबी मूल्य के विश्लेषण से पता चला कि दो क्षेत्रों, रसायन और प्लास्टिक में एए के लिये एफओबी मूल्य 2018-19 तक कुल प्रत्यक्ष निर्यातों के 50 प्रतिशत से अधिक था जिसके बाद इंजीनियरिंग आता था। इन तीन क्षेत्रों में एए योजना कुल क्षेत्रीय निर्यातों का एक महत्वपूर्ण संचालक थी।

डीजीएफटी ने मई 2019 में एए जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ-साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग कार्यान्वित की और उसके बाद 1 दिसम्बर 2020 से प्रभावी एक नयी आईटी प्रणाली शुरू की, जिसमें सभी निर्धारित दस्तावेजों को (मोचन के लिए दस्तावेजों सहित) ऑनलाइन अपलोड़ करना, त्रुटियों और उनके उत्तरों का ऑनलाइन निपटान करना आवश्यक है तथा एए योजना को कागजरहित बनाने के लिए और

ईओडीसी को अंतिम रूप देने की बेहतर निगरानी के लिए सीमा शुल्क को डेटा का निरंतर हस्तान्तरण किया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गयी अवधि 2015-16 से 2018-19 थी; इसलिए मई 2019 और दिसम्बर 2020 से प्रभावी इन विशेषताओं के कार्यान्वयन की आगामी लेखापरीक्षाओं में समीक्षा की जाएगी।

(पैरा 1.4, 1.4.1 और 1.4.2)

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

अध्याय II: अग्रिम प्राधिकार (एए) का जारी करना

2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के लिए स्वचालित प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की और डेटा के विश्लेषण द्वारा एए को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लागू किए गए सरलीकरण उपायों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में जांच की गयी। विश्लेषण में पता चला कि एए योजना स्वचालित होने के नाते आवेदन की प्राप्ति के साथ को आंशिक रूप से स्वचालित किया गया था जबकि एए जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक मैन्युअल रही। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान एए योजना के लिए विकसित स्वचालित प्रणाली में मैन्युअल हस्तक्षेप आवश्यक था जिसके कारण परिहार्य प्रत्यक्ष इंटरफेस तथा प्राधिकृत कर्मचारियों के पास विवेकाधिकार रहा जिसके परिणामस्वरूप एए जारी करने में काफी विलम्ब हुआ। किसी मानदंड के बिना आधारित एए जिनकों डीजीएफटी मुख्यालय में मानदंड समितियों (एनसी) द्वारा अंतिम रूप दिया गया, मैन्युअल रहे।

2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए 65 प्रतिशत एए एसआईओएन आधारित थे और शेष 35 प्रतिशत बिना मानदंड की श्रेणी से सम्बन्धित थे जिन्हें सम्बन्धित एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है; समीक्षा के लिए चयनित नमूने को उसी अनुपात में तदनुसार आहरित किया गया। तथापि इस अध्याय में टिप्पणी किए गए कुल 1,422 एए में से, 621 एए एसआईओएन आधारित थे (44 प्रतिशत) और शेष 801 एए बिना मानदंड की श्रेणी (56 प्रतिशत) से सम्बन्धित थे। इस प्रकार

अधिकांश लेखापरीक्षा मुद्दे बिना मानदंड की श्रेणी के अन्तर्गत जारी किए गए एए मुद्दों से सम्बन्धित थे, यद्धपि यह कुल एए का केवल एक तिहाई था।

पर्याप्त संचित रिक्तियों के साथ डीजीएफटी मुख्यालय और आरए दोनों में स्टाफ की भारी कमी थी, जिसका न केवल अग्रिम प्राधिकार योजना बल्कि एफटीपी के अन्तर्गत अन्य योजनाओं पर भी प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

(पैरा 2.1)

एए जारी करने में पर्याप्त विलम्ब से 2015-16 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कारोबार सहजता में और क्रियाविधि के सरलीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता दर्शायी गयी। स्वाचालन से एए जारी करने की प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक था क्योंकि आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग केवल मई 2019 में कार्यान्वित की जा सकी जिसके कार्यान्वयन की आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी। तब तक, सभी निर्धारित दस्तावेज प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किए जा रहे थे जिससे एक ऑनलाइन सिस्टम को सहज बनाने का प्रयोजन विफल हो गया, परिणामस्वरूप निर्धारित समयावधि होने के बावजूद एए जारी करने में अत्यधित विलम्ब हुआ था।

(पैरा 2.2)

लेखापरीक्षा द्वारा मानदंड समितियों के पास लंबित अग्रिम प्राधिकार आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गयी। 31 मार्च 2019 को लम्बन 5606 था जिसमें 31 मार्च 2020 तक 6044 (7.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। चार महीने की निर्धारित अवधि के बाद प्रतिमानों के नियतन में 4 महीने से 16 वर्ष तक अत्यधिक विलम्ब हुआ, जो आयातों के लिए और निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए तय समय-सीमा क्रमश: 12 महीने और 18 महीने, के प्रतिकूल था। समय पर प्रतिमानों को अंतिम रूप न देने से, निर्धारित अवधि के अन्दर निर्यातकों को ईओडीसी जारी नहीं किए जा सके, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बांडों और बीजी का अवरोधन हुआ, बल्कि ईओ पूरा न करने के मामलों में भी वृद्धि हुई। आगे, चूक के मामलों के लिए सीमा शुल्क और उस पर

ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने में भी विलम्ब होता है जो उस सही एएच पर शास्ति लगाने के अलावा है जिसे सभी अनुबद्ध शर्तों का पालन करने के बाद भी ईओसीडी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(पैरा 2.4.1 और 2.4.2)

लेखापरीक्षा में डीईएल तंत्र का कार्यान्वयन पाया गया, जो निर्यातकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए माना जाता है, डीईएल के तहत ईकाईयों को रखने में 8 से 13 वर्ष की अत्यधिक देरी हो रही थी और कई स्थगन आदेश जारी किए जा रहे थे, जो इसकी अप्रभाविता को दर्शाता है। उन स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा तय नहीं है जो विद्धमान नियमों/क्रियाविधियों के अन्तर्गत एक निर्यातक को जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा, यह जानने के लिए आरए के लिए ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि क्या आवेदक सीमा शुल्क अधिनियम और उसके नियमों के अन्तर्गत दंडित किया गया है, क्योंकि सीमा शुल्क और डीजीएफटी कार्यालयों के बीच ऐसे दंडित ईकाईयों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान नहीं होता। प्राधिकार का जारी करना पूर्णरूप से आवेदक की स्व-घोषणा पर होता है।

(पैरा 2.5)

विभिन्न एए जारी करने से पहले आरए द्वारा अभिलेखों का कोई सत्यापन नहीं होता, विशेषकर उन लघु उद्योग (एसएसआई) ईकाईयों का, जिनका पिछला कोई निर्यात प्रदर्शन नहीं है और वे अपनी क्षमता से अधिक आयात करने की उनकी मांग करते है। इसके अतिरिक्त, एक समयबद्ध तरीके से पिछले एए के निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के अभाव में, फर्म को नए लाइसेंस जारी करने से योजना का असली उद्देश्य विफल होता है।

(पैरा 2.6.1 और 2.6.2)

अध्याय III : योजना का कार्यान्वयन

सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी दोनों के द्वारा योजना के कार्यान्वयन की जांच लेखापरीक्षा में की गयी। लेखापरीक्षा में यह भी सत्यापित किया गया कि क्या डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय के लिए कोई

सांस्थानिक तंत्र मौजूदा है और क्या दोनों विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके में किया जा रहा है।

लाइसेंसों के प्रति प्राधिकारों की वैधता अवधि के बाद शुल्क मुक्त आयातों या अधिक आयातों का अनुमत करना सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग माड्यूल में निगरानी तंत्र की कमज़ोरी को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बांड के कार्यान्यवन का प्रारंभकि प्रयोजन एए योजना में यथानिर्धारित नियमों और क्रियाविधियों के उचित अनुपालन को सुरक्षित करना है; यह गैर-अनुपालन के मामलों में उपयुक्त शुल्क और ब्याज के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए समर्थक प्रतिभूति के रूप में भी कार्य करता है। एक समयबद्ध तरीके में बांडों के रद्द न करने, जैसाकि सीबीआईसी के अनुदेशों में निर्धारित है, से न केवल सही एएच की निधियों का अवरोधन हुआ है बल्कि यह बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए एक गलत संकेत भी देता है।

(पैरा 3.1.1 से 3.1.3)

मोचन हेतु दावा करने के लिए आरए एएच पर निर्भर करता है क्योंकि जहां ईओ की अवधि समाप्त हो चुकी है, उन मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए तत्कालिन प्रणाली में आरए के पास कोई तंत्र नहीं है। अधिक आयातों की निगरानी न करने, पूर्व-आयात शर्तों के अननुपालन और निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) में अनुचित वृद्धि के दृष्टांत पाए गए।

(पैरा 3.2.1.1 से 3.2.1.3)

लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण की मांग करने के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है और लाइसेंस की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद भी ऐसे अनुरोध किए जाते हैं। चूंकि लाइसेंस की वैधता एचबीपी के पैरा 2.16 में निर्दिष्ट की गयी है (जारी करने की तारीख से 12 महीने) और आयातों/निर्यातों (एचबीपी का पैरा 2.18) की तारीख को भी प्राधिकार वैध होना चाहिए, इसलिए लेखापरीक्षा की राय में, पुनर्वैधीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के अन्दर ही विचार किया जाना चाहिए।

(पैरा 3.2.1.4)

परिशिष्ट 4-एच/ 4-ई के तहत यथापेक्षित निर्यायित मदों के विनिर्माण में वास्तव में प्रयुक्त सभी इनपुट की घोषणा के लिए आरए में ज़ोर नहीं दिया

जाता। लेखापरीक्षा का मत है कि केवल आयातित इनपुट के सीआईएफ मूल्य को मानने की प्रथा, मूल्यवर्धन की पूरी स्थिति को नहीं दर्शाती। देशी आपूर्तियों के मूल्य को शामिल न करना, जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी राशि का गलत मानना और एएच द्वारा वास्तविक आयातों की घोषणा न करना का लेखापरीक्षा में पता चला था, जो शुल्क मुक्त आयातों के विचलन और योजना के दुरूपयोग के जोखिम से भरा हुआ है। आरए अघोषित माल के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित कर सकते है और गलत ढंग से ली गयी छूट को अननुमत करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।

(पैरा 3.2.3.1 से 3.2.3.3)

मोचन/ईओडीसी आवेदन के लिए आनलाईन सुविधा के सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी के जारी करने में विलम्ब हुआ और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। भले की मोचन के लिए आवेदन आनलाईन फाईल किए गए थे तथापि सभी दस्तावेज जैसे बीई, एसबी, ई-बीआरसी, इनपुट और निर्यात खपत तथा प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा की अवधि 2015-16 से 2018-19 के दौरान मैनुअल रूप से फाईल किए जाने अपेक्षित थे। मोचन प्रक्रिया के पूर्ण डिजिटिकरण और लाइसेंस डेटा के साथ इसके एकीकरण से विलम्ब में कमी करने और मोचन आवेदनों के निपटान के लिए नियत किए गए 15 दिन के बैंचमार्क को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

(पैरा 3.2.6)

एक प्रभावी आनलाईन मैसेज एक्सचेंज माडयूल (एमईएम) के अभाव में, सीबीआईसी को अक्सर डीजीएफटी द्वारा दी गयी ईओडीसी की प्रास्थिति अभिनिश्चित करने के लिए एएच पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी प्रकार, डीजीएफटी को उन मामलों के लिए शुल्क भुगतान प्रास्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गयी है परन्तु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी डेटा की सूचना न देने/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ईओडीसी डेटा का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप बांडों के निपटान में विलम्ब होता है और लंबित मामलों में वृद्धि होती है।

(पैरा 3.3.1)

चूककर्ताओं के विरूद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का जारी न करना और अधिनिर्णयन प्रक्रिया में विलम्ब उन कमियों को दर्शाता है जो दो विभागों के बीच समन्वय और ईडीआई सिस्टम के अप्रभावी उपयोग अथवा डीजीएफटी के 'eodc.online' में थीं, ताकि निर्यात प्रदर्शन को अभिनिश्चित किया जा सके और ठोस कार्रवाई की जा सके। डीजीएफटी द्वारा एए को प्रदान किए गए विस्तारों, जारी किए गए एससीएन/मांग नोटिसों के बारे में डीओआर को अधिसुचित किया जाना चाहिए और साथ ही अपने पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि एक समयबद्ध तरीके में सीमा शुल्क द्वारा कार्रवाई को आसान बनाया जा सके।

(पैरा 3.3.3)

अध्याय IV : आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा पर एक प्रभावी नीति के अभाव ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी न करने में योगदान दिया जिसमें अन्य कार्यों के साथ इनपुट के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करके विभिन्न माल के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई आरए किसी ऐसे तंत्र से अनभिज्ञ थे।

(पैरा 4.1)

एससीएन और अधिनिर्णयन आदेश जारी करने के लिए एफटीडीआर एक्ट में विशेष समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कार्रवाई किए जाने वाले सभी मामलों में किसी पूर्वधारणा के बिना उसी तरीके में कार्यवाई की जाए। इससे सरकारी राजस्व के अवरोधन को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

(पैरा 4.2)

आरए द्वारा प्रस्तुत की गयी एमआईएस रिपोर्टों की डीजीएफटी द्वारा पर्याप्त रूप से निगरानी/मिलान नहीं किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सूचना की रिपोर्टिंग न करने को आरए के साथ नहीं उठाया जा रहा है। कार्यवाई प्रारम्भ करने में विलम्ब और मांग नोटिस/ एससीएन के निपटान में विलम्ब के परिणामस्वरूप भारी संचित मामले लंबित हुए। एफटीपी में न तो कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं थी और न ही कोई प्रशासनिक आदेश जारी किए गए थे

जिनमें चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाही तेज़ करने में लिए अनुदेश दिए गए हों।

(पैरा 4.3)

सिफारिशें

1. डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, ताकि यह अग्रिम प्राधिकार और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो, यदि डीजीएफटी इन योजनाएं को जारी रखने का इरादा रखता है, तो।

2. *डीजीएफटी यह सुनिश्चित करके एए को समय पर जारी करने के लिए मैनुअल और स्वचालित प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकता है कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूरा और पूर्ण आवेदन स्वीकार करने के लिए पुन: व्यवस्थित किया गया है। ऐसे निर्गमन की समयसीमा (या अन्यथा) की पर्याप्तता की समीक्षा भी की जा सकती है। तीन दिनों की निर्धारित समय-सीमा की तुलना में डीजीएफटी द्वारा एए जारी करने में महत्वपूर्ण विलम्ब (तीन महीने से दो वर्ष से अधिक) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आयातित वस्तुओं को प्राप्त करने की योजना के मूल उद्देश्य को विफल करता है। ऐसी विस्तारित अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।*

3. समय के साथ सभी क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं और सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी उन्नयन में प्रगति की, डीजीएफटी को 2009 में एचबीपी वॉल्यूम- II के माध्यम से अधिसूचित एसआईओएन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

4. चार महीने से 16 वर्षों तक प्रतिमानों के नियतन करने में विलम्ब के साथ (जबकि एए योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों के लिए निर्धारित समयसीमा क्रमश: 12 महीने और 18 महीने है), बिना-मानदंड की श्रेणी के लिए मानदंड समिति (एनसी) की प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं

कर रही है और डीजीएफटी को प्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि दुरूपयोग की गुंजाइश को कम करते हुए इसकी उपयोगिता और व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा सके।

5. डीजीएफटी समयसीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है जिसके अन्दर एनसी के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की जा सकती है।

6. डीजीएफटी समय पर सुचारू रूप से डीईएल को अद्यतन करना सुनिश्चित कर सकता है और आस्थगन आदेश जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, डीईएल में पूर्व अवधि के लिए लगाए गए दंड का विवरण, और की गई कार्रवाई के परिणाम, की गई वसूली, निर्णय आदि को शामिल करना चाहिए। आस्थगन आदेश प्रदान करने से पहले लंबित निर्यात में शामिल शुल्क के लिए या आस्थगन आदेशों के विरुद्ध जारी किए गए नए लाइसेंसों के संबंध में शामिल शुल्क के लिए पूर्ण बीजी के रूप में, राजस्व हित को बीजी के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।

7. डीजीएफटी को पहली बार माल के आयात/निर्यात के लिए मांग करने वाली फर्मों (विशेषकर एसएसआई यूनिटें जिनका पिछला कोई निर्यात प्रदर्शन न हो) को विभिन्न एए जारी करने से पहले निर्यातकों के अभिलेखों का सत्यापन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डीजीएफटी को नए एए जारी करने से पहले पूर्व एए, यदि कोई हो, के संबंध में ईओडीसी के पूरा होने का सत्यापन करना चाहिए यह सीआईए का सीमांकन और राजस्व के हित की रक्षा के लिए वर्धित बांड और बैंक गारंटी तंत्र भी निर्धारित कर सकता है।

8. डीजीएफटी आरए को नए एए जारी करने से पहले एएच द्वारा लम्बित एए के मोचन दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने की निगरानी के लिए अपने अनुदेशों की पुनरावृत्ति करा सकता है।

9. सीबीआईसी ईओ अवधि की समाप्ति के लिए उपयुक्त बांड नवीनीकरण/रद्दीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तथा ईओडीसी प्रास्थिति

को अभिनिश्चित करने के लिए एएच पर निर्भरता से बचने के लिए एक स्वचालित सतर्क प्रणाली पर विचार कर सकता है।

10. डीजीएफटी को ईओ के निरन्तर रूप् से और नियमित रूप से निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। अब तक, ऐसे मामलों पर नज़र रखने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जहां ईओपी समाप्त हो गयी थी और ईओडीसी प्रास्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए आरए एएच पर ही निर्भर थे। एए के संभावित दुरूपयोग को कम करने के लिए, घरेलू इनपुट के प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातित इनपुट के संभावित विपथन को संबोधित करने के लिए डीजीएफटी के ईडीआई प्रणाली में वैधीकरण जांचों के होने की आवश्यकता है।

11. डीजीएफटी को पुनर्वैधीकरण प्रदान करने की क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोधों को केवल प्राधिकार की वैध अवधि के अन्दर ही स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शुल्क मुक्त आयात या निर्यात के लिए निर्यात दायित्व की गणना प्राधिकार के चलन तक ही हो।

12. डीजीएफटी परिशिष्ट 4 एच में पूर्ण प्रकटन के लिए जोर दे सकता है जिसमें, एएच से "घरेलू रूप से अधिप्राप्त इनुपुट सहित निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सभी इनपुट और ऐसी अधिप्राप्ति के स्रोत के विवरण" घोषित करने की अपेक्षा की गयी है, जो आरए द्वारा वास्तविक खपत की बेहतर निगरानी को सुकर बनाने के लिए है जिससे शुल्क मुक्त आयातों के विपथन और योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

13. डीजीएफटी को 15 दिनों की अपनी निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए ईओडीसी जारी करने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा यह सुनिश्चित करके करनी चाहिए कि आनलाईन माडयूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूर्ण और मुकम्मल आवेदनों को स्वीकार करने के दोबारा बनाया गया है।

14. डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचनाओं के प्रभावी और समय पर आदान-प्रदान के लिए डीजीएफटी को अपने सभी आरए में मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) लागू करना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से अपनी

eodc.online वेबसाइट में ईओडीसी स्थिति को अपडेट करना चाहिए। समय पर सूचना साझा करने, ईओडीसी की स्थिति का समाधान करने और छोड़े गए शुल्क के आकार में शामिल सरकारी राजस्व की वसूली के लिए डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच, आवधिक बैठकें निरंतर तरीके से आयोजित की जा सकती हैं। डीजीएफटी/डीओआर द्वारा योजना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा, सुधार करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है और इसलिए आंतरिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है। डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक लेखापरीक्षा में उचित रूप से स्टाफ दिया गया है और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, विशेष लेखापरीक्षा की परिकल्पना विशेष रूप से उन मामलों के लिए की गई थी जिनमें एए स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत जारी किए जाते हैं और इसलिए गलत घोषणाएं करने वाले आवेदकों के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम कुछेक मामलों में परीक्षण के तौर पर लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी।

16. डीजीएफटी, समय पर और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णय प्रक्रिया के बेहतर नियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी करने और अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।

17. डीजीएफटी को आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी करने की आवश्यकता है और गलत/गैर-रिपोर्टिंग के दृष्टांतों को आरए के साथ उठाया जा सकता है। एमआईएस रिपोर्ट से मिली सूचना के आधार पर डीजीएफटी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

शब्दों और संकेताक्षरों की शब्दावली

सकेंताक्षर	पूर्णरूप
एए	अग्रिम प्राधिकार
एएएस	अग्रिम प्राधिकार योजना
एएच	प्राधिकार धारक
एएनएफ	आयात निर्यात फॉर्म
एआरओ	अग्रिम विमोचन आदेश
बीसीडी	मूल सीमा शुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआरसी	बैंक उगाही प्रमाणपत्र
बीडब्ल्यूसी	बॉन्ड छूट प्रमाणपत्र
सीए	सनदी लेखाकार
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीई	चार्टर्ड इंजीनियर
सेनवैट	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीएलए	मुख्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण
सीटीएच	सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष
डीईईसी	शुल्क हकदारी छूट प्रमाणपत्र
डीईल	अस्वीकृत ईकाई सूची
डीजीएफटी	महानिदेशक विदेश व्यापार
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति और संवर्धन
डीएल	कमी पूरकपत्र
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
ई-बीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र
ईसीए	प्रवर्तन सह अधिनिर्णयन
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज
ईईपीसी	अभियांत्रिकी की निर्यात संवर्धन
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख इकाइयां

सकेंताक्षर	पूर्णरूप
ईपी	निर्यात विकास
ईपीसी	निर्यात विकास परिषद
एक्जिम	निर्यात-आयात
फेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन संघ
एफओबी	पोत पर्यत नि:शुल्क
एफओआर	फ्रेट ऑनरोड
एफटीडीआर	विदेश व्यापार विकास और विनियमन
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीएसटी	माल और सेवाकर
एचबीपी	क्रियाविधि पुस्तिका
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत माल और सेवाकर
एलयूटी	शपथ पत्र
एमई	मर्चेंट एक्सपोर्टर
एमईएस/एम	मैसेज एक्सचेंज सिस्टम/ मॉड्यूल
एमएफपी	लघु वन उत्पाद
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओसीआई	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमपीआर	मासिक प्रगति रजिस्टर
एमवीए	न्यूनतम मूल्य संवर्धन
एनसी	मानदंड समिति
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीआईपी	तैनात व्यक्ति
पीएन	सार्वजनिक नोटिस
पीआरसी	नीति रियायत समिति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसएआर	नमूना विश्लेषण रिपोर्ट
एसबी	लदान बिल
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एससीओएमईटी	स्पेशल केमिकल्स, आर्गेनिज़म, मेटीरियल्स एंड टेकनोलाजीस

सकेंताक्षर	पूर्णरूप
एसईज़ेड	विशेष आर्थिक ज़ोन
एसआरएस	स्व-संपुष्टि योजना
एसआरटीईपीसी	सिंथेटिक एंड रेयान टैक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
एसएस	संस्वीकृत क्षमता
एसएसआई	लघु उद्योग
वीए	मूल्य वर्धन

अध्याय I
अग्रिम प्राधिकार योजना का विहंगवालोकन

1. प्रस्तावना

अग्रिम लाइसेंसिंग योजना, जिसे शुल्क हकदारी छूट प्रमाण पत्र (डीईईसी) के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1976 में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मूल्य वर्धन की निर्दिष्ट प्रतिशतता के साथ विनिर्मित माल के निर्यात की शर्त के अधीन भारत में सीमा शुल्क के भुगतान के बिना अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर पंजीकृत निर्यातकों को उनकी मूल्य इनपुट/कच्ची सामग्री की आवश्यकता पूरी करना है। बाद में एफटीपी 2004-09 के तहत 1 सितम्बर 2004 से प्रभावी इस योजना का नाम बदलकर अग्रिम प्राधिकार योजना (एएएस) कर दिया गया।

अग्रिम प्राधिकार (एए) उन इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है, जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है, जिसमें सामान्य अपव्यय की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किए जाने वाले ईंधन, तेल और उत्प्रेरक को भी शुल्क मुक्त करने की अनुमति है। एए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निर्धारित मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) के आधार पर और एफटीपी की मानदंड समितियों (एनसी)/ स्वंय संपुष्टि योजना द्वारा अनुमोदन के अनुमोदन के अधीन तदर्थ स्वघोषित मानदंडों के आधार पर भी जारी किए जाते हैं।

1.1 योजना के कार्यान्वयन में शामिल प्राधिकारी

यह योजना डीजीएफटी द्वारा क्रियान्यवित की जाती है जबकि आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से छूट केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित मंत्रालय (एमओएफ) के अधीन डीओआर द्वारा अनुमत की जाती है।

लाइसेंस के लिए आवेदन डीजीएफटी के अधीन क्षेत्राधिकारिक आरए को प्रस्तुत की जानी होती है, जैसा कि क्रियाविधि की पुस्तिका (एचबीपी) में निर्दिष्ट किया गया है। आरए आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन करता है और लाइसेंस जारी करता है, जिसे फिर लाइसेंस के अन्तर्गत माल के आयात और निर्यात को

अनुमत करने के लिए निर्दिष्ट सीमा शुल्क पत्तन के साथ पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण सीमा शुल्क विभाग के पास बांड, और यदि आवश्यक हो तो बैंक गारंटी (बीजी)[1] के कार्यान्वयन के अधीन होता है। निर्यात दायित्वों (ईओ) के निर्वहन पर, प्राधिकार धारक (एएच) आरए को मोचन का एक आवेदन करता है, जो एएच को एक निर्यात दायित्व प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी करता है और यदि कोई बांड और बीजी हो, के मोचन के लिए सीमा शुल्क विभाग को उसकी एक प्रति भेजता है।

1.2 एए के लिए मानदंड

एफटीपी के पैरा 4.03 के अनुसार, एए निम्नलिखित के आधार पर परिणामी उत्पाद के संबंध में इनपुट के लिए जारी किए जाते हैं:

(क) एचबीपी में अधिसूचित एसआईओएन;

(ख) स्व-घोषणा, जहां एसआईओएन अधिसूचित नहीं है;

(ग) आवेदक विशिष्ट मानदंडों का पूर्व निर्धारण;

(घ) स्व-संपुष्टि योजना।

एसआईओएन विभिन्न परिणामी उत्पादों के निर्माण में आवश्यक विभिन्न इनपुटों के अनुपात को निर्धारित करता है। यदि मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया गया है, तो आरए आवेदकों द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर एए जारी कर सकता है। इस तरह दावा किए गए अपशिष्ट, एनसी द्वारा तय किए गए अपशिष्ट मानदंडों के अधीन होगें। आवेदक-विशिष्ट मानदंडों का पूर्व निर्धारण पीएन 26 के माध्यम से 20 सितंबर 2017 से शुरू किया गया था और स्व-संपुष्टि योजना (एसआरएस) 22 मार्च 2018 से पीएन 68 के तहत लागू की गई थी।

[1] सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 दिनांक 21-10-2004 के अनुसार सीमाशुल्क पत्तनों पर एए के पंजीकरण के समय सीमा-शुल्क विभाग द्वारा बैंक गारंटी ली जाती है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। बीजी को एए योजना के तहत निर्यातकों की कुछ श्रेणियों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), स्टार हाउस निर्यातक, निर्यातक मौजूदा या पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कारोबार करने वाले और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले, विनिर्माता निर्यातकों ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात के साथ एक करोड़ से अधिक का निर्यात कारोबार किया हो और विनिर्माता निर्यातकों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकरण किया हो और पिछले वित्त वर्ष के दौरान एक करोड़ से अधिक के उत्पाद शुल्क (पूर्व माल एवं सेवा कर (जीएसटी) युग) या जीएसटी से अधिक का जीएसटी भुगतान किया हो। अन्य सभी विनिर्माता निर्यातकों को 15 प्रतिशत बीजी और बाकी सभी को 100 प्रतिशत बीजी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

1.3 योजना की मुख्य विशेषताएं

पंजीकृत निर्यातकों को एए के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आरए एए जारी करता है और उस प्राधिकार के अन्तर्गत माल के आयात और निर्यात के लिए बंदरगाह पर पंजीकरण के लिए संदेश विनिमय प्रणाली (एमईएस) के तहत सीमा शुल्क बंदरगाह को इसकी सूचना देता है। एसआईओएन के अनुसार प्राधिकार में निर्दिष्ट मात्रा में इनपुट सीमा शुल्क से मुक्त हैं। वैकल्पिक रूप से, आयात के लिए लाइसेंस अमान्य करके बिना शुल्क के घरेलू स्तर पर भी इनपुट की खरीद की जा सकती है।

सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 दिनांक 21-10-2004 के अनुसार सीमा शुल्क पत्तनों पर एए के पंजीकरण के समय सीमा शुल्क विभाग द्वारा बीजी ली जाती है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। असाधारण मामलों में, एचबीपी के पैरा 4.13 में सीमा शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बीजी को प्रस्तुत करने के अधीन पैरा 4.12 (ए) में उल्लिखित लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) की हकदारी से अधिक का प्रावधान है। आरए प्राधिकार में इस आशय का विशिष्ट अंकन करेगा। इसी प्रकार, एचबीपी के 2.29 (बी) के अनुसार, आरए इनपुट के घरेलू स्रोत के मामले में एएच से भी बीजी के लिए आग्रह कर सकता है।

लाइसेंस 18 महीने की अवधि के भीतर 15 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य वर्धन (एमवीए) के साथ ईओ प्राप्त करने की शर्त पर जारी किए जाते हैं (परिशिष्ट 4जे इनपुट के अलावा)। निर्धारित शर्तों के अधीन प्रत्येक छह महीने के लिए समय-सीमा को दो बार और बढ़ाया जा सकता है। मात्रा के संदर्भ में ईओ की पूर्ति न करने के लिए छोड़े गए सीमा शुल्क व साथ ही निर्यात मात्रा को पूरा नहीं करने के लिए आनुपातिक रूप से आवश्यक इनपुट पर ब्याज का भुगतान करके प्राधिकार के नियमितीकरण की आवश्यकता होती है। मूल्य के संदर्भ में विफलता के लिए मूल्य में कमी के एक प्रतिशत के बराबर दंड का भुगतान करके नियमितीकरण की आवश्यकता होती है।

ईओ की पूर्ति पर, निर्यातक निर्यात आय के इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी) और शिपिंग बिलों (एसबी) को प्रस्तुत करके आरए में ईओडीसी के

लिए आवेदन करता है। जब ईओडीसी जारी किया जाता है, तो इसे एमईएस के माध्यम से बॉन्ड और बीजी पत्तनों पर निष्पादित, यदि कोई हो, के मोचन के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भी सूचित किया जाता है।

एचबीपी के पैरा 4.44 (एफ) के अनुसार, यदि एएच ईओ को पूरा करने में विफल रहता है या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकार और शपथ-पत्र की शर्त लागू करेगा और चूककर्ता निर्यातक को अगले प्राधिकार से इनकार करके नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा। एए योजना में एए जारी करने से लेकर ईओडीसी तक की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है:

चित्र 1: एए योजना में प्रक्रियाओं के प्रवाह का सारांश

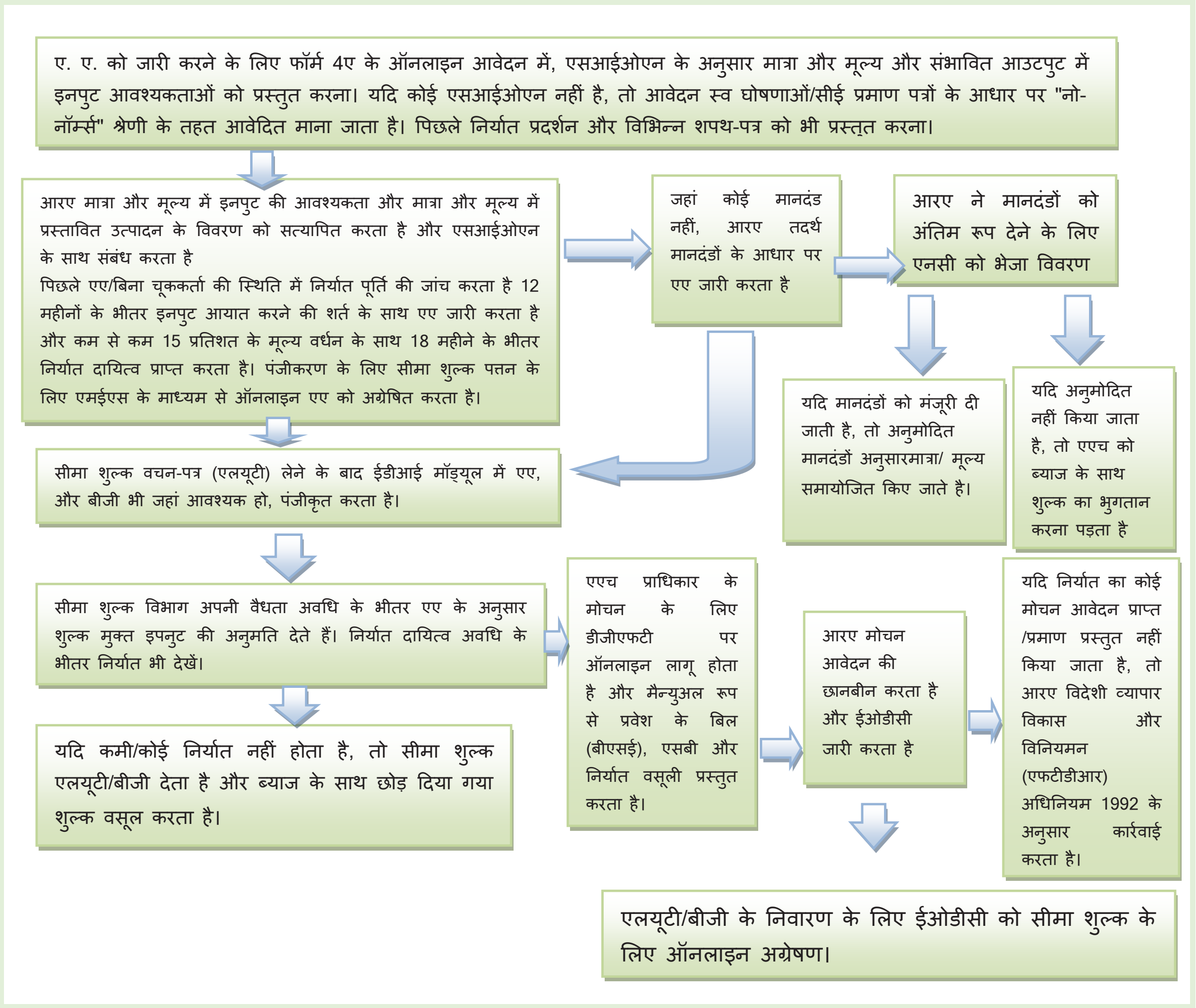

इसमें शामिल प्राधिकारियों के साथ-साथ एएएस में शामिल प्रक्रियाओं को नीचे चित्र 2 में सक्षिप्त विवरण दिया गया है:

चित्र 2: एए योजना में शामिल प्रक्रिया

आर को आवेदन

- **क्षेत्राधिकार वाले आरए कार्यालय में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फॉर्म (एएनएफ 4ए) में ऑनलाइन आवेदन।**
- आवेदक या तो पंजीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय/शाखा कार्यालय कार्यालय/विनिर्माण इकाई हो सकता है।
- **आवेदन को ऑनलाइन फाइल करने के समय एएनएफ 4ए, परिशिष्ट-4ई में निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करना।**

आरए द्वारा एए का सत्यापन और जारी करना

- दस्तावेजों के सत्यापन और एलयूटी/बीजी के निष्पादन के बाद एए जारी करना।
- निर्यातक निर्धारित फीस का भुगतान करने के बाद एए में संशोधन और आयात/निर्यात अवधि में विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- संयुक्त डीजीएफटी कार्यालयों/आरए को ईओ की निगरानी के लिए एए जारी करने के रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है।
- एए जारी करने के लिए निर्धारित समयावधि तीन दिन है।
- आरए एए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी), बहिष्करण सूची, अपात्र श्रेणियों/निर्यातकों) के संबंध में शर्तों को सत्यापित करने और एफटीपी/एचबीपी में निर्धारित प्रतिबंधों और शर्तों के संदर्भ में आवेदन की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए।

सीमा शुल्क पर पंजीकरण

- निर्यातक को विशिष्ट सीमा शुल्क पत्तन पर एए पंजीकृत करना होता है। बांड/बीजी, जहां भी आवश्यक हो, सीमा शुल्क पोर्ट के साथ निष्पादित किया जाना है।
- शुल्क मुक्त आयात/निर्यात तब निर्यातक द्वारा प्राधिकरण के आधार पर प्रभावित होते हैं और प्रत्येक निर्यात/आयात को प्राधिकरण पर सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया जाता है।
- पत्तन के पंजीकरण द्वारा जारी सलाह की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अन्य बंदरगाहों के माध्यम से आयात/निर्यात भी प्रभावित किया जा सकता है।
- शुल्क मुक्त आयात करने के लिए निर्धारित समय सीमा 12 महीने है और निर्यात के लिए यह एए जारी होने की तिथि से 18 महीने है।
- सीमा शुल्क की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि आरए द्वारा जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार आयात और निर्यात प्रभावित होते हैं।

आरए द्वारा ईओडीसी प्रमाणपत्र

- आरए कार्यालय को फॉर्म (एएनएफ 4एफ) में ईओडीसी का आवेदन।
- दिसंबर 2020 तक, निर्धारित दस्तावेज मैनुअल फार्म रूप में जमा किए गए थे।
- ईओ की पूर्ति के समर्थन में निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करना।
- आरए कार्यालय निर्यातक द्वारा जमा किए गए ईओडीसी दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं।
- ईओडीसी तब आरए कार्यालयों द्वारा सीमा शुल्क पत्तन को प्रतिलिपि के साथ जारी किया जाता है।
- आरए/सीमा शुल्क द्वारा ईओ को पूरा करने में विफलता के मामले में सीमा शुल्क की मांग करने की कार्रवाई।
- ईओडीसी के लिए आवेदन करने की समय सीमा ईओ अवधि की समाप्ति से दो महीने के भीतर है और आरए 15 दिनों के भीतर ईओडीसी जारी करने के लिए है।

1.4 सांख्यिकीय विहंगवालोकन

2015-16 से 2018-19 तक निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि के लिए एए योजना का विश्लेषण, एए की संख्या और आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) धारकों की संख्या के अनुसार, योजना के तहत कुल आयात और निर्यात की अनुमति के रूप में किया गया था, जैसा कि नीचे वर्णित है:

चित्र 3: जारी प्राधिकारों और एए योजना के तहत स्वीकृत निर्यात/आयात मूल्य

चित्र 3.1: आईईसी धारकों की संख्या की तुलना में जारी किए गए प्राधिकार

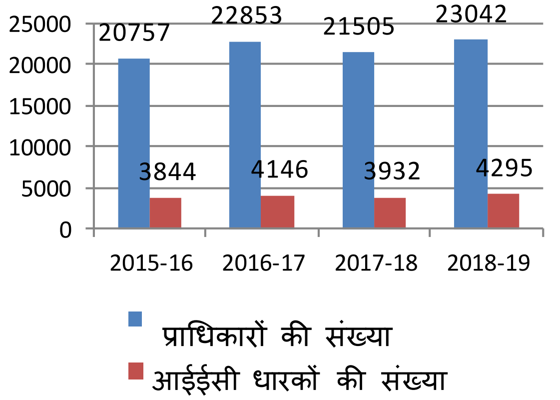

चित्र 3.2: प्राधिकारों का सीआईएफ और एफओबी मूल्य

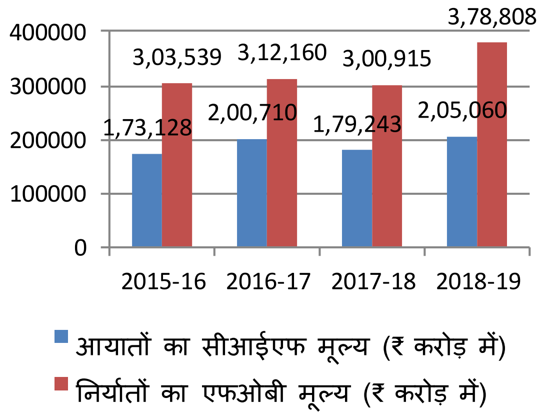

निर्यात का एफओबी मूल्य 2015-16 में 25 प्रतिशत बढ़कर ₹3,03,539 करोड़ से 2018-19 में ₹3,78,808 हो गया। इसी तरह, आयातों के एए और एएच और सीआईएफ मूल्य की संख्या में भी क्रमशः 11 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सीमा शुल्क पत्तनों पर एए के वास्तविक उपयोग का सीमा शुल्क ईडीआई (इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज) डेटा से विश्लेषण किया गया था जैसा कि नीचे चित्र 4 में विवरण दिया गया है:

चित्र 4: एए योजना के तहत जारी किए गए प्राधिकारों का उपयोग

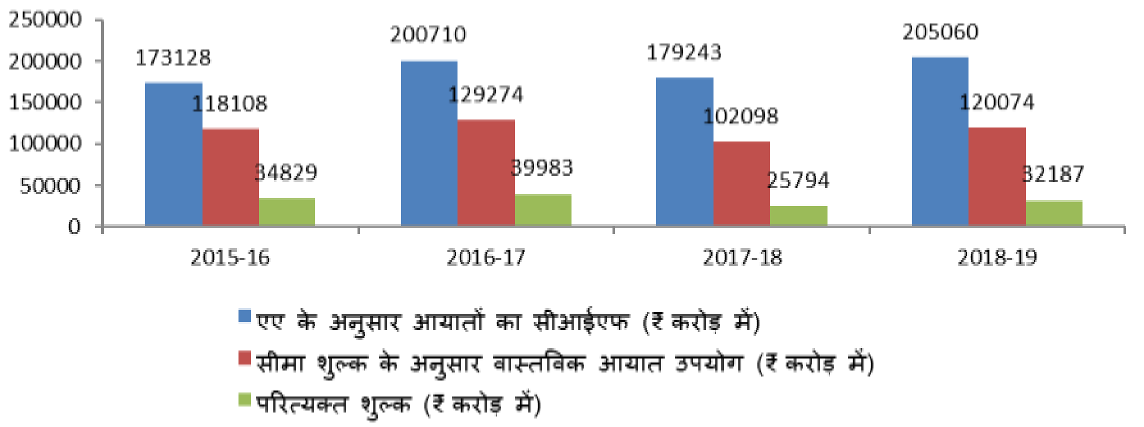

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, एए के उपयोग का प्रतिशत 2015-16 में 68.22 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 58.56 प्रतिशत हो गया और तदानुसार शुल्क छूट 2015-16 में 29.49 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 26.81 प्रतिशत हो गया।

1.4.1 एए योजना के तहत निर्यात का हिस्सा

मूल्य के संदर्भ में कुल भौतिक निर्यात के लिए एए योजना के तहत निर्यात की हिस्सेदारी 2015-16 में 9.75 प्रतिशत थी, जो 2018-19 में बढ़कर 10.77 प्रतिशत हो गई, जैसा कि नीचे वर्णित है:

चित्र 5: अखिल भारतीय निर्यात प्रतिशत के रूप में एएएस के तहत निर्यात

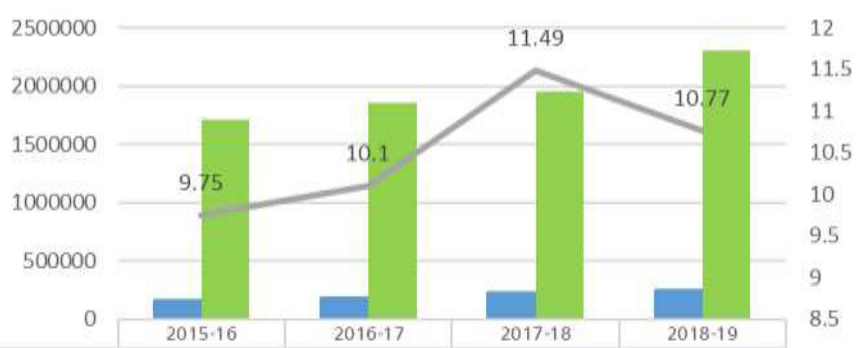

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एएएस के तहत आयात (₹ करोड़ में)	167350	186716	224783	248430
अखिल भारतीय आयात (₹ करोड़ में)	1716384	1849434	1956514	2307726
अखिल भारतीय आयात के प्रतिशत के रूप में एए के तहत आयात	9.75	10.1	11.49	10.77

एए योजना के माध्यम से किए गए निर्यात के एक करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए शुल्क परित्यक्त किया गया, जो 2015-16 में ₹21 लाख रुपये से 2018-19 में ₹13 लाख रुपये तक परिवर्तित हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:

तालिका 1: एफओबी मूल्य की तुलना में शुल्क परित्यक्त

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
शुल्क परित्यक्त (₹ करोड में)	34828.72	39982.55	25793.52	32187.01
एफओबी (₹ करोड में)	167349.93	186715.94	224782.57	248430.08
शुल्क परित्यक्त / एफओबी का एक करोड़ (₹ करोड़ में)	0.21	0.21	0.11	0.13

1.4.2 प्राधिकारों का क्षेत्रीय वितरण:

2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तहत एए (आयात की संख्या और सीआईएफ मूल्य) का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2: एए का क्षेत्रीय वितरण

	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		प्रतिशत परिवर्तन	
क्षेत्र	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्यांए	मूल्य
रासायनिक	9589	57064.29	9849	57822.56	9259	65196.81	9309	77052.82	-2.92	35.03
इलेक्ट्रॉनिक्स	185	777.09	187	984.26	126	856.74	143	1830.41	-22.70	135.55
इंजीनियरिंग	4293	48835.99	4333	60869.03	4157	57697.25	4299	64687.82	0.14	32.46
मछली	23	147.01	19	108.35	14	127.1	19	170.96	-17.39	16.29
खाद्य पदार्थ	582	6154.85	1400	14067.76	841	9626.42	814	8546.5	39.86	38.86
रत्न और आभूषण	77	40707.9	63	44000.78	51	21840.52	94	18700.32	22.08	-54.06
हस्तशिल्प	31	47.36	34	21.82	31	20.28	47	31.52	51.61	-33.45
चमड़ा	55	153.65	86	270.41	105	290.96	84	388.11	52.73	152.59
प्लास्टिक	3749	15072.71	4039	17737.89	4120	18347.46	4471	26258.11	19.26	74.21

क्षेत्र	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		प्रतिशत परिवर्तन	
	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	एए की संख्या	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्याएं	मूल्य
खेल-कूद	0	0	0	0	0	0	2	2.56	200.0	256.00
वस्त्र	1917	3549.16	2393	3791.51	2529	4426.05	3225	5597.36	68.23	57.71
विविध	256	617.87	451	1035.32	272	1139.26	535	1793.81	108.98	190.32
कुल	**20757**	**173127.9**	**22853**	**200709.7**	**21505**	**179568.9**	**23042**	**205060.3**	**11.01**	**18.44**

सीआईएफ मूल्य के संदर्भ में एए के 2015-16 से 2018-19 तक के क्षेत्रीय विश्लेषण में रत्न और आभूषण और हस्तशिल्प के संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, रसायन, चमड़ा आदि में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। 2018-19 तक, एए के सीआईएफ मूल्य के संदर्भ में रसायन, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक क्षेत्रों का हिस्सा लगभग 82 प्रतिशत था। कुल मिलाकर, सीआईएफ मूल्य के संदर्भ में लगभग 18.44 प्रतिशत और वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 19 तक जारी किए गए एए की संख्या के संदर्भ में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रमुख क्षेत्रों के तहत एए में निर्धारित किए गए एफओबी के विवरणों की तुलना कुल भौतिक निर्यात से की गई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 3: क्षेत्र में किए गए कुल भौतिक निर्यात की तुलना में एए में निर्धारित एफओबी

क्षेत्र	2015-16			2016-17			2017-18			2018-19			% प्रतिशत परिवर्तन	
	एए (क) में निर्धारित एफओबी	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	एए (क) में निर्धारित एफओबी	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	एफओबी एए में निर्धारित (क)	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	एफओबी एए में निर्धारित (क)	कुल भौतिक निर्यात का मूल्य (ख)	(क) से (ख) का % प्रतिशत	ईओ निर्धारित	कुल निर्यात
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)			
रासायनिक	159008	210542	**75.52**	139760	219810	**63.58**	154302	242114	**63.73**	206517	306131	**67.46**	29.88	45.40
इलेक्ट्रॉनिक्स	1312	37453	**3.50**	1566	38144	**4.11**	1275	39148	**3.26**	2516	58858	**4.27**	91.77	57.15
इंजीनियरिंग	67847	391359	**17.34**	78595	435769	**18.04**	78705	490244	**16.05**	92161	564688	**16.32**	35.84	44.29
खाद्य पदार्थ	8612	212459	**4.05**	17140	223207	**7.68**	12130	247708	**4.90**	10743	270618	**3.97**	24.74	27.37
रत्न और गहने	41334	257421	**16.06**	44672	290903	**15.36**	22206	267833	**8.29**	19173	281408	**6.81**	-53.61	9.32
प्लास्टिक	19077	42029	**45.39**	22725	43173	**52.64**	23449	48814	**48.04**	35365	66059	**53.54**	85.38	57.17
वस्त्र	4900	243030	**2.02**	5681	249575	**2.28**	6976	240949	**2.90**	8990	267108	**3.37**	83.47	9.91
विविध	1449	322091	**0.45**	2024	348853	**0.58**	1870	379704	**0.49**	3342	492856	**0.68**	130.64	53.02
कुल	**303539**	**1716384**	**17.68**	**312163**	**1849434**	**16.88**	**300913**	**1956514**	**15.38**	**378807**	**2307726**	**16.41**	**24.80**	**34.45**

यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स (92 प्रतिशत), प्लास्टिक (85 प्रतिशत) और वस्त्र (83 प्रतिशत) में एए (निर्धारित ईओ के संदर्भ में) की वृद्धि में बढ़ोतरी हुई, जबकि रत्न और आभूषण (54 प्रतिशत) के मामले में इसमें तेजी से गिरावट आई, जो ₹41,334 करोड़ (वित्त वर्ष 16) से ₹19,173 करोड़ (वित्त वर्ष 19) हो गई। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 16 से वित्त वर्ष 19 तक एए में निर्धारित एफओबी मूल्य के मामले में लगभग 24.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

क्षेत्र के तहत प्रभावित कुल भौतिक निर्यात की तुलना में एए के लिए निर्धारित एफओबी मूल्यों से निम्नलिखित का पता चला:

चित्र 6: क्षेत्र में किए गए कुल भौतिक निर्यात के प्रतिशत के रूप में एए के लिए निर्धारित एफओबी मूल्य

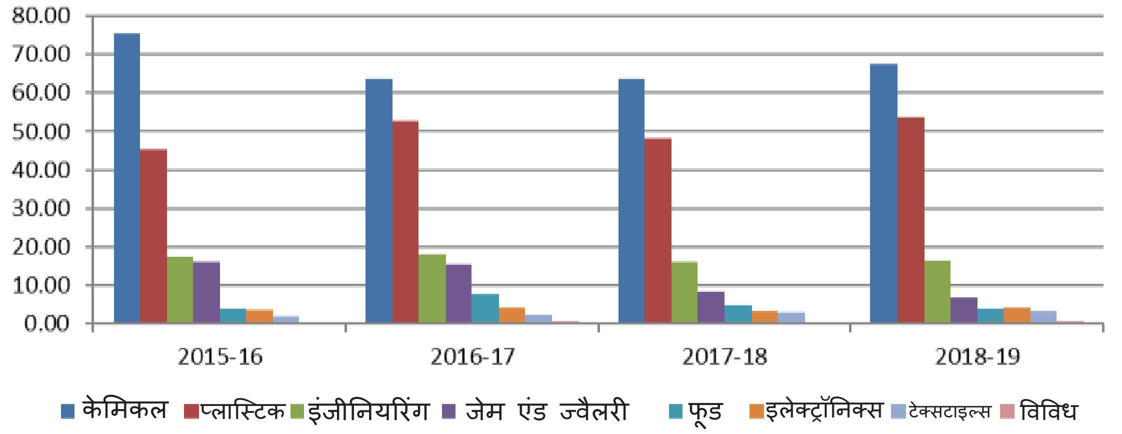

वर्ष के दौरान प्रभावित कुल भौतिक निर्यातों की तुलना में एए में निर्धारित एफओबी मूल्य के विश्लेषण से पता चला है कि दो क्षेत्रों, रसायन और प्लास्टिक, में एए के लिए इंजीनियरिंग एफओबी मूल्य के बाद 2018-19 के रूप में कुल भौतिक निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक था। इन तीन क्षेत्रों में, एए योजना कुल क्षेत्रीय निर्यात का एक महत्वपूर्ण संचालक थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि के संभावित कारणों[2] को समर्पित निर्यात संवर्धन परिषदों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो निर्यात में तेजी लाने के लिए अपने सदस्यों को (वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक व्यापार शो/प्रदर्शनी और सम्मेलनों की

[2] एमओसीआईआई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

सुविधा, वाणिज्यिक रूप से उपयोगी जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं) सेवाओं की एक सरणी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इन उद्योगों में आने वाले अधिकांश उत्पादों के लिए एसआईओएन मानदंड पहले से ही निर्धारित हैं और एएच के पास निर्यात को प्रभावित करने के बाद भी शुल्क मुक्त आयात करने का विकल्प है।

वैश्विक आर्थिक मंदी[3] के कारण रत्न और आभूषण क्षेत्र को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा, विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए अन्य एफटीपी योजनाओं की उपस्थिति, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का उदग्रहण, स्वर्ण पदकों और सिक्कों के निर्यात के लिए बहुमूल्य धातुओं के आयात के लिए एए योजना को बंद करना आदि, एए योजना में रत्न और आभूषण क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी के अन्य संभावित कारण थे।

मंत्रालय ने अक्टूबर 2017 से इस क्षेत्र के विकास को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए जीएसटी छूट पुन: स्थापित करके, आईजीएसटी छूट प्राप्त करने के लिए पूर्व आयात शर्तों को हटाने, अनुमानित आपूर्ति के लिए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर की छूट का विस्तार करने और नामित एजेंसी से निर्यातकों द्वारा मंगाए गए सोने पर 3 प्रतिशत आईजीएसटी को जनवरी 2019 से अवरुद्ध पूंजी को मुक्त करके रत्न और आभूषण क्षेत्र की मदद करने के लिए विभिन्न पहल की है।

कुल मिलाकर, नए एफटीपी 2015-20 में, योजना के क्रियान्यवयन में डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से कई सुविधा उपायों को सक्षम बनाया है जिसमें आवेदन के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट/इंजीनियरों से सभी जानकारी और प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना शामिल है। लाइसेंस के मोचन के लिए अब एसबी[4] की निर्यात प्रोत्साहन (ईपी) कॉपी के बजाय शिपिंग बिल की कोई भी कॉपी प्रस्तुत की जा सकती है और ई-बीआरसी अटैच करने की भी आवश्यकता नहीं है। डीजीएफटी ने पहले आवेदक को या समान उत्पादों के लिए अन्य आवेदकों[5] को जारी प्राधिकारों के आधार पर आरए स्तर पर तदर्थ मानदंडों पर जारी प्राधिकारों

[3] एमओसीआई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

[4] डीजीएफटी का पीएन 9/2015-20 दिनांक 9.7.2018

[5] डीजीएफटी के पीएन नं.64/2015-20 दिनांक 27.12.2018

का संपुष्टि करने में भी सक्षम बनाया। मोचन आवेदन की स्थिति सार्वजनिक पोर्टल 'eodc.online'[6] से जानी जा सकता है।

डीजीएफटी ने मई 2019 में एए जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग लागू की और बाद में 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी एक नई आईटी प्रणाली लागू की है जिसमें सभी निर्धारित दस्तावेजों (मोचन सहित) को ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है, जहां कमियों और उनकी प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन निपटाया जाएगा और ईओडीसी को अंतिम रूप देने और एए योजना को कागज रहित बनाने की बेहतर निगरानी के लिए डेटा को सीमा शुल्क विभाग को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए, मई 2019 और दिसंबर 2020 से प्रभावी इन विशेषताओं के कार्यान्वयन की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों का आकलन करना था:

i) क्या डीजीएफटी कार्यालयों द्वारा प्राधिकारों को जारी करने, उपयोग और मोचन को कुशल और प्रभावी तरीके से किया जा रहा है;

ii) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा एए का कार्यान्वयन कुशल और प्रभावी तरीके से किया जा रहा है;

iii) क्या योजना के प्रशासन में शामिल अंतर-विभागीय समन्वय तंत्र प्रभावी है;

iv) क्या आंतरिक नियंत्रण उपाय राजस्व हानि, दुरुपयोग आदि के जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त हैं।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में चार वर्ष की अवधि 2015-16 से 2018-19 तक के रिकॉर्ड और लेनदेन शामिल थे। लेखापरीक्षा में डीजीएफटी, इसके आरए और सीमा शुल्क विभाग की क्षेत्रीय संरचनाओं को शामिल किया गया था जहां एए पंजीकृत थे।

---

[6] डीजीएफटी का व्यापार नोटिस 1/2018-19 दिनांक 4.4.2018

1.7 लेखापरीक्षा कवरेज

पूरे भारत में कुल 38 आरए हैं जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा के तहत शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 के दौरान ₹7,58,141 करोड़ के आयात के लिए सीआईएफ मूल्य वाले 88,157 एए जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने 23 प्रमुख आरए (60.52 प्रतिशत) से ₹2,08,126 करोड़ (29.56 प्रतिशत) के सीआईएफ मूल्य वाली 4,048 एए फाइलों (4.96 प्रतिशत) के नमूने का चयन किया, जो कुल 38 आरए के 92.64 प्रतिशत संख्यावार (81,674 लाइसेंस) और 92.86 प्रतिशत मूल्यवार (₹7,04,008 करोड़ के सीआईएफ मूल्य) के बराबर है **(परिशिष्ट 1)**। लेखापरीक्षा ने क्षेत्राधिकारिक सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों का भी चयन किया जहां शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों को प्रभावित करने के लिए चयनित नमूना मामले पंजीकृत थे।

4,048 चयनित मामलों में से, सात आरए (मुख्य रूप से मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली) से संबंधित ₹9,906.73 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाली 405 एए फाइलें थी जिन्हें आरए को बार-बार अनुरोध करने/अनुस्मारक भेजने के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 1)**।

1.8 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा ने निष्कर्षों को बेंचमार्क करने के लिए लागू अधिनियमों, मैन्युअल, नियमावली, सरकारी अधिसूचनाओं को मापदंड के रूप में प्रासंगिक प्रावधानों का उपयोग किया। महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं:

- एफटीपी 2015-20;
- एचबीपी और इसके परिशिष्ट;
- डीजीएफटी द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस (पीएन)/परिपत्र आदि;
- विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) (एफटीडीआर) अधिनियम, 1992;
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962;
- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975;
- अग्रिम प्राधिकार योजना पर सीमा शुल्क अधिसूचनाएं और परिपत्र**;**
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा),1999;

- विदेशी मुद्रा का संरक्षण, तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974।

1.9 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के सीएजी के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों का उपयोग करके और सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 के अनुरूप की गई थी।

लेखापरीक्षा नवंबर 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान की गई। डीजीएफटी ने अक्टूबर 2018 तक के आंकड़ों के डंप डेटा को 18 दिसंबर 2018 को और नवंबर 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के आंकड़ों के डंप डेटा को 3 जनवरी 2020 को, दो किश्तों में प्रदान किया। लेखापरीक्षा जांच में डीजीएफटी डेटा का विश्लेषण और जारी किए गए प्राधिकारों की नमूना जांच तथा डीजीएफटी के चयनित आरए कार्यालयों में एएच द्वारा ईओ की पूर्ति और चयनित सीमा शुल्क पत्तनों में प्राधिकारों के उपयोग की नमूना जांच शामिल थी। योजना के क्रियान्यवयन में डीजीएफटी और सीमा शुल्क विभाग के बीच समन्वय का भी विश्लेषण किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए इंट्री/एक्जिट सम्मेलन क्रमशः 18 दिसंबर 2019 और 19 जनवरी 2021 को डीओसी/डीओआर के सदस्यों के साथ आयोजित किया गया था। पहला मसौदा 6 अक्टूबर 2020 को एमओसीआई/डीओआर को भेजा गया था, जिसका उत्तर 9 दिसंबर 2020 (डीजीएफटी) और 16 दिसंबर 2020 (डीओआर) को प्राप्त हुआ था। दूसरा मसौदा 9 जनवरी 2021 को जारी किया गया था, जिसका उत्तर 1 फरवरी 2021 (डीजीएफटी) और 12 फरवरी 2021 (डीओआर) को प्राप्त हुआ था।

1.10 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर), वाणिज्य विभाग (डीओसी) और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त हुए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है।

अध्याय II
अग्रिम प्राधिकार जारी करना

डीजीएफटी ने एफटीपी 2015-20 में परिकल्पित बेहतर व्यापार सुविधा और कागज रहित प्रसंस्करण के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रणाली से आवेदनों की प्राप्ति और आरए और निर्यातकों के बीच न्यूनतम इंटरफेस के साथ लाइसेंस जारी करने की शुरुआत की। 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के लिए स्वचालित प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की और डेटा के विश्लेषण द्वारा एए को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लागू किए गए सरलीकरण उपायों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा में जांच की गयी। विश्लेषण में पता चला कि एए योजना स्वचालित होने के नाते आवेदन की प्राप्ति के साथ को आंशिक रूप से स्वचालित किया गया था जबकि एए जारी करने की प्रक्रिया काफी हद तक मैनुअल रही। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान एए योजना के लिए विकसित स्वचालित प्रणाली में मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक था जिसके कारण परिहार्य प्रत्यक्ष इंटरफेस तथा प्राधिकृत कर्मचारियों के पास विवेकाधिकार रहा जिसके परिणामस्वरूप एए जारी करने में काफी विलम्ब हुआ। किसी मानदंड के बिना आधारित एए जिनकों डीजीएफटी मुख्यालय में एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया, मैनुअल रहे।

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जारी किए गए एए का 65 प्रतिशत एसआईओएन आधारित था और शेष 35 प्रतिशत संबंधित एनसी द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले बिना मानदंडों की श्रेणी से संबंधित थे; समीक्षा के लिए चयनित नमूना उसी अनुपात में तैयार किया गया था। हालांकि, इस अध्याय में टिप्पणी की गई कुल 1422 एए में से 621 एए एसआईओएन आधारित (44 प्रतिशत) थे और शेष 801 एए बिना मानदंडों की श्रेणी (56 प्रतिशत) के थे। इस प्रकार, एए से संबंधित अधिकांश लेखापरीक्षा मुद्दे, भले ही यह कुल एए का केवल एक तिहाई हिस्सा है, बिना मानदंडों की श्रेणी के तहत जारी किए गए।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण और व्यापार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली के साथ-साथ मैनुअल प्रणाली में कमियों को भी दर्शाया, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- डीजीएफटी में अधिकारी/कर्मचारी के स्वरूप की समीक्षा (पैरा 2.1);
- एए जारी करने में देरी (पैरा 2.2);
- एसआईओएन की समय पर समीक्षा/अद्यतन का अभाव (पैरा 2.3);
- एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण में अनियमितताएं (पैरा 2.4);
- अस्वीकृत इकाई सूची (डेल) की अपर्याप्त निगरानी (पैरा 2.5);
- अपात्र आवेदकों को अनियमित एए जारी करना (पैरा 2.6);
- अपात्र आपूर्तियों पर अनियमित एए जारी करना (पैरा 2.7);
- अन्य अनियमितताएं (पैरा 2.8)।

2.1 डीजीएफटी में अधिकारी/कर्मचारी के स्वरूप की समीक्षा

लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी मुख्यालय के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय संरचनाओं (आरए) में अधिकारी/कर्मचारी के स्वरूप और रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा की ताकि एए योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की प्रतिकुल क्षमता के साथ कर्मचारियों की कमी का पता लगाया जा सके।

यह देखा गया कि 2015-16 से 2018-19 की अवधि में डीजीएफटी मुख्यालय में रिक्ति की स्थिति, स्वीकृत संख्या (एसएस) में 9.4 प्रतिशत की कमी के बावजूद 43 प्रतिशत से बढ़कर 47 प्रतिशत हो गई, जैसा कि नीचे विवरण में दिया है:

तालिका 2.1: डीजीएफटी मुख्यालय में एसएस[7] की तुलना में पीआईपी

वर्ष	राजपत्रित		गैर राजपत्रित		कुल		रिक्ति
	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	संख्या (प्रतिशत)
2015-16	155	97	343	188	498	285	213 (42.7)
2016-17	155	93	343	172	498	265	233 (46.7)
2017-18	147	85	343	185	490	270	220 (44.8)
2018-19	147	83	304	154	451	237	214 (47.4)

इस तथ्य के बावजूद कि लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए आरए स्तर पर एसएस और पर्सन-इन-पोजिशन (पीआईपी) के लिए अनुरोध किया, डीजीएफटी ने केवल 30 जून 2021 तक पदभार स्थिति साझा की जिसमें 1,074 (58 प्रतिशत) की रिक्तियां के साथ 1,849 की स्वीकृत संख्या के प्रति पीआईपी 775 थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:

[7] एसएस- स्वीकृत संख्या; पीआईपी-पर्सन-इन-पोजिशन

तालिका 2.2: आरए स्तर पर एसएस की तुलना में पीआईपी

मापदंड	राजपत्रित		गैर राजपत्रित		कुल		रिक्ति
	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	एसएस	पीआईपी	संख्या (प्रतिशत)
30 जून 2021 तक पदभार स्थिति	211	153	1638	622	1849	775	1074 (58.0)

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, डीजीएफटी मुख्यालय और पर्याप्त संचित रिक्तियों वाले आरए दोनों में कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे न केवल अग्रिम प्राधिकार बल्कि एफटीपी के तहत अन्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सिफारिश संख्या-1 : डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, ताकि यह अग्रिम प्राधिकार और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो, यदि डीजीएफटी इन योजनाएं को जारी रखने का इरादा रखता है, तो।

2.2 एए जारी करने में विलंब

एचबीपी 2015-2020 के पैरा 9.10 के साथ पठित पीएन 16/2015-2020 दिनांक 4 जून 2015, जो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एए योजना के संबंध में आवेदनों के निपटान के लिए "तीन दिन" की समय-सीमा निर्धारित करता है। डीजीएफटी सिटीजन चार्टर दस्तावेज में भी यही समय सीमा घोषित की गई थी।

लक्षित समय-सीमा को प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी ने एचबीपी 2015-2020 के पैरा 4.02 के माध्यम से आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग के समय आयात निर्यात फॉर्म (एएनएफ) 4ए में सभी निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड करने की परिकल्पना की थी और आवेदन की कोई भौतिक प्रति आरए को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

हालांकि यह देखा गया कि केवल आवेदन की प्राप्ति स्वचालित थी और आवेदन के साथ दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग, हालांकि पॉलिसी परिपत्र संख्या 23/2015-20 के तहत अप्रैल 2015 में परिकल्पित मई 2019 में ही लागू किया जा सका था। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित सभी नमूना मामलों में सभी

निर्धारित दस्तावेज भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे थे और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्राप्ति के बाद ही आरए ने आवेदनों पर कार्रवाई की।

लेखापरीक्षा ने निर्धारित समयसीमा की तुलना में सुविधा उपायों की सफलता की जांच की और विलंब को पाया, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया हैं:

1. चयनित 23 आरए द्वारा जारी एए पर डेटा के विश्लेषण से समीक्षा (2015-16 से 2018-19) में शामिल अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 81,403 एए (77.83 प्रतिशत) में से 63,360 मामलों में देरी का पता चला। जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया हैं:

यह देरी चार दिनों से लेकर 2,349 दिनों तक थी, 52,907 एए में 1 महीने तक, 7,581 एए में 3 महीने तक, 2,750 एए में दो साल तक और 122 एए में 2 साल से अधिक की विलंब देखी जा रहा है (अनुलग्नक 1क)। वर्षवार, 2015-16 के दौरान 15,217 लाइसेंस (78.66 प्रतिशत), 2016-17 के दौरान 16,206 लाइसेंस (78.78 फीसदी), 2017-18 के दौरान 15,580 लाइसेंस (77.78 फीसदी) और 2018-19 के दौरान 16,357 लाइसेंस (76.19 फीसदी) में विलंब देखा गया, जो नीचे में दिया गया है:

तालिका 2.3 : एए जारी करने में देरी का वर्ष-वार विश्लेषण

वर्ष	कुल एए जारी किए	देरी					
		4 दिनों-एक महीना	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
2015-16	19345	12417	1979	485	220	93	23
2016-17	20558	13527	1984	397	200	78	20
2017-18	20032	13120	1758	392	164	81	65
2018-19	21468	13843	1860	414	162	64	14
Total	**81403**	**52907**	**7581**	**1688**	**746**	**316**	**122**

ज्यादा विलंब वाले नौ आरए का विश्लेषण नीचे ग्राफ में दिया गया है:

चित्र 2.2: मुख्य आरए में एए जारी करने में विलम्ब

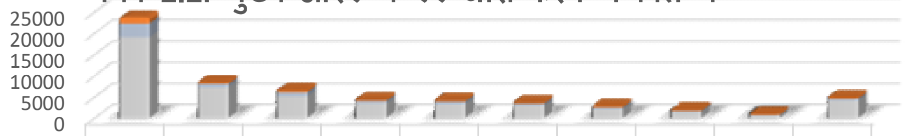

	मुंबई।	दिल्ली	अहमदाबाद	बंगलुरू	हैदराबाद	चेन्नई।	वडोदरा	कोलकाता	पुणे	अन्य
3 माह से अधिक	1338	236	383	147	125	89	183	116	76	179
1 से 3 माह	3246	710	929	522	547	475	379	198	154	421
1 माह तक	19369	7634	5495	3853	3661	3246	2438	1815	929	4467

जबकि अधिकांश विलंब एक महीने से भी कम हैं, फिर भी महत्वपूर्ण विलंब एक महीने से अधिक के हैं। तीन दिन की निर्धारित समय-सीमा पर्याप्त अंतर से अवितरित रही।

2. लेखापरीक्षा के लिए चयनित 23 आरए में से 20 में 3,497 नमूना मामलों की समीक्षा में चार दिन से लेकर 2,199 दिन तक के विलंब के साथ 1,012 मामलों में विलंब का पता चला। नमूना मामलों में विलंब की रूपरेखा समग्र आबादी की तुलना में कम है, लेकिन हमारे नमूने उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित के बाद से, कम मूल्य के मामलों में विलंब की रूपरेखा भी अधिक थी, जिसके कारण छोटे निर्यातकों को अनुचित कठिनाई हुई। तीन आरए (कोचीन, चंडीगढ़ और लुधियाना) के मामले में चयनित नमूनों में कोई विलंब नहीं पाया गया। कुल 1,012 विलंबित मामलों में से 792 में कोई कमीपूरक पत्र (डीएल) जारी नहीं किया गया था और एए जारी करने में विलंब के कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं थे जो तीन कार्य दिवसों में जारी किए जाने चाहिए थे। **(अनुलग्नक 1ख)**।

विलंब के मुख्य कारण ऑनलाइन आवेदन फाईल करने के बाद भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता, अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) आदि की अपर्याप्त निगरानी थी, जिससे एए जारी करने में देरी हुई।

एए जारी करने में पर्याप्त विलम्ब से कारोबार सहजता में और क्रियाविधि के सरलीकरण का उद्देश्य प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता दर्शायी गयी। स्वाचालन से एए जारी करने की प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप आवश्यक था क्योंकि आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग केवल मई 2019 में कार्यान्वित की जा सकी जिसके कार्यान्वयन की आगामी लेखापरीक्षा में समीक्षा की जाएगी। तब तक, सभी निर्धारित दस्तावेज प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किए जा रहे थे जिससे एक ऑनलाइन सिस्टम को सहज बनाने का प्रयोजन विफल हो गया, परिणामस्वरूप निर्धारित समयावधि होने के बावजूद एए जारी करने में अत्यधित विलम्ब हुआ था।

सिफारिश संख्या-2 : डीजीएफटी यह सुनिश्चित करके एए को समय पर जारी करने के लिए मैनुअल और स्वचालित प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकता है कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूरा और पूर्ण आवेदन स्वीकार करने के लिए पुन: व्यवस्थित किया गया है। ऐसे निर्गमन की समय-सीमा (या अन्यथा) की पर्याप्तता की समीक्षा भी की जा सकती है। तीन दिनों की निर्धारित समय-सीमा की तुलना में डीजीएफटी द्वारा एए जारी करने में महत्वपूर्ण विलम्ब (तीन महीने से दो वर्ष से अधिक) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आयातित वस्तुओं को प्राप्त करने की योजना के मूल उद्देश्य को विफल करता है। ऐसी विस्तारित अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि 1 दिसंबर 2020 को एक नई आईटी प्रणाली शुरू की गई थी जिसमें सभी अपेक्षित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने, कमियों और उनकी प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन निपटाने, ऑनलाइन जारी किए गए प्राधिकारों और सीमा शुल्क को निर्बाध रूप से डेटा स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जिससे योजना कागजरहित हो सके।

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए, इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

2.3 मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) की समय पर समीक्षा/अद्यतन का अभाव

अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत, किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत इनपुट की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है, जो निर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपव्यय पर विचार करती है। डीजीएफटी, प्रक्रिया की पुस्तिका (एचबीपी वॉल्यूम-II) के तहत मानक इनपुट-आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) की एक क्षेत्रवार सूची प्रदान करता है।

यह देखा गया था कि एसआईओएन को अंतिम बार डीजीएफटी द्वारा मई 2009 में एचबीपी 2009-14 (खंड-II) के तहत अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, डीजीएफटी द्वारा एसआईओएन की कोई व्यापक समीक्षा नहीं की गई, भले ही 2015-2020 के लिए एचबीपी 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया था और 2021-2026 के लिए एचबीपी अधिसूचित किया जाना है। हालांकि, एसआईओएन को हितधारको से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर सार्वजनिक नोटिसों के माध्यम से मामले दर मामले के आधार पर प्रस्तुत/निरस्त/संशोधित किया गया था।

सिफारिश संख्या-3: समय के साथ सभी क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं और सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी उन्नयन में प्रगति की, डीजीएफटी को एचबीपी वॉल्यूम- II के माध्यम से 2009 में अधिसूचित एसआईओएन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।

2.4 मानदंड समितियां (एनसी)

एफटीपी के पैरा 4.03 में यह अनुबद्ध है कि एचबीपी में उपलब्ध अधिसूचित एसआईओएन के आधार पर परिणामी उत्पाद के संबंध में इनपुट के लिए एए जारी किए जाए। एचबीपी के पैरा 4.06 में डीजीएफटी मुख्यालय में उन मामलों के लिए एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण का प्रावधान है जहां मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया गया है। आवेदकों को संबंधित एनसी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 4ख में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

2.4.1 एनसी का गठन

एनसी की कार्यप्रणाली को समझने और एनसी द्वारा मानदंडो के निर्धारण में देरी के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने डीजीएफटी से एनसी

संरचना, श्रमबल, समितिवार कार्यभार और बैकलॉग का विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। डीजीएफटी ने बताया (जुलाई 2021) कि मुख्य वस्तुओं (प्लास्टिक और रबर, रासायनिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद (समूह क और ख), कपड़ा और चमड़ा और समुद्री, खाद्य पदार्थ और विविध) के लिए डीजीएफटी में सात एनसी थे। आवेदकों को बिना मानदंड की श्रेणी के तहत क्षेत्राधिकार आरए के माध्यम से संबंधित एनसी से संपर्क करना होगा। एनसी के गठन में अध्यक्ष, संयोजक, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, महानिदेशालय ड्रॉबैक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि, संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद/कमोडिटी बोर्ड और कई अन्य तकनीकी प्राधिकरण शामिल है जिसे अध्यक्ष आमंत्रित करना चाहते हैं।

एनसी के साथ लंबित स्थिति का विवरण नीचे दिया है:

तालिका 2.4: एनसी के साथ लंबित स्थिति (एनसी-1 से एनसी-7)

अवधि	आदिशेष	निर्धारण के लिए प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	निर्धारण के लिए लंबित अंतशेष	लंबित प्रतिशत
2015-16	3660	5280	3820	349	4771	53.36
2016-17	4771	5306	4406	470	5201	51.61
2017-18	5201	5083	2932	274	7078	68.82
2018-19	7078	5345	6326	491	5606	45.12
2019-20	5606	3996	नहीं दिया	नहीं दिया	6044	62.95
कुल		**25010**	**17484**	**1584**		

लेखापरीक्षा ने मानदंड समितियों के साथ अग्रिम प्राधिकार आवेदनों की लंबित स्थिति की समीक्षा की। 31 मार्च 2019 तक, 5606 आवेदन लंबित थे जो 31 मार्च 2020 (7.8 प्रतिशत) तक बढ़कर 6044 हो गए। यह 2017-18 के दौरान सबसे अधिक (69 फीसदी) थे। एनसी-वार, लंबन अधिकतर एनसी-3 (रासायनिक उत्पादों) और एनसी-4 (फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों) में देखा गया था, जिसमें 31 मार्च 2019 को लंबन समय क्रमशः 1286 और 938 था।

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जारी किए गए प्राधिकारों की समीक्षा से पता चला है कि 65 प्रतिशत एए एसआईओएन आधारित थे और शेष 35 प्रतिशत बिना मानदंड की श्रेणी से संबंधित थे जिन्हें संबंधित एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है। समीक्षा के लिए चयनित नमूना उसी अनुपात में तैयार किया गया था। चयनित नमूने की नमूना जांच में निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

2.4.2 एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण में विलंब

एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.16 (i) में बताया गया है कि मानदंडों, जिनके लिए आवेदन किया गया है, यदि परिशिष्ट 4ई में निर्दिष्ट दस्तावेजों/तकनीकी विवरणों के साथ पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार महीने के भीतर एनसी द्वारा मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो इसे अंतिम माना जा सकता है।

लागू मानदंडों को अंतिम मानने के प्रावधान को बाद में दिसंबर 2017 में हटा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने नौ आरए में 3,139 मामलों की समीक्षा की और 2,113 मामलों (67 फीसदी) में अपवाद पाए गए। आरए स्तर पर पाए गए मानदंडों के गैर/विलंबित निर्धारण के कुछ मामलों को नीचे रेखांकित किया गया है:

तालिका 2.5 : एनसी द्वारा मानदंडों का गैर/लंबित निर्धारण

क्र/सं	आरए का नाम	मामलों की संख्या	लंबित अवधि	टिप्पणी
1	मुंबई	2030	16 वर्ष तक	वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 की अवधि के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों की नमूना जांच से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) - 3 रिपोर्ट में विसंगतियों का पता चला अर्थात, 136 फाइलें पहले ही मोचन की गई थीं, एनसी ने 10 मामलों में मंजूरी दी और 12 मामलों में अस्वीकृत आदेश जारी किए गए और फिर भी ये सभी लाइसेंस एनसी के साथ मानदंडों के अनुमोदन के लिए लंबित एमआईएस-3 में प्रदर्शित किए गए।
2	दिल्ली	24	19 से 65 महीने	17 मामलों में, जहां ईओपी, पहले ही समाप्त हो गया था, योजना के तहत दो विस्तारों पर विचार किया गया।
3	हैदराबाद	31	4 से 33 महीने	विलंबित 31 मामलों में से 16 में, एनसी द्वारा निर्धारित इनपुट की मात्रा निर्यातकों द्वारा आवेदित

क्र/सं	आरए का नाम	मामलों की संख्या	लंबित अवधि	टिप्पणी
				मात्रा से कम थी; हालांकि, बीच की अवधि में एएच पहले से ही इन एए के प्रति माल का आयात कर लिया था।
4	विशाखापट्टनम	9	48 महीने (मई 2021 तक)	अभी किसी भी मामले में निर्धारित नहीं है। अन्य छह मामलों में, यह बताने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं पाया गया कि मानदंडों के निर्धारण के लिए एनसी से संपर्क किया गया था।
5	कोलकाता	8	68 महीने (मई 2021 तक)	प्रत्येक प्राधिकार के प्रति एएच ने माल आयात किया, हालांकि ईओपी की समाप्ति के तीन वर्ष बाद भी नियमितीकरण के लिए आरए द्वारा एएच को जारी किए गए किसी पत्र/कारण बताओ नोटिस (एससीएन) को और न ही एनसी द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।
6	कानपुर	3	66 महीने (मई 2021 तक)	अभी किसी भी मामले में निर्धारित नहीं है। आरए ने एनसी द्वारा मानदंडों को अंतिम रूप न देने के आधार पर ईओडीसी के मुद्दे को लंबित रखा।
7	बेंगलुरु	3	66 महीने (मई 2021 तक)	इन सभी मामलों में ईओ की अवधि समाप्त हो गई और एएच निपटान/ईओडीसी आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि एसआईओएन अनुमोदन/मानदंडों संपुष्टि अभी भी डीजीएफटी के पास लंबित था। एक मामले में, मेसर्स ए लिमिटेड ने ईओडीसी के लिए आरए वडोदरा से संपर्क किया क्योंकि सीमा शुल्क ने उसके मोचन/ईओडीसी आवेदन के लंबित होने के कारण उसकी निर्यात खेप को रोके रखा था। हालांकि, ईओडीसी एनसी द्वारा मानदंडों का निर्धारण न करने के कारण लंबित है।
8	वडोदरा	2	65 महीने (मई 2021 तक)	
9	जयपुर	3	50 महीने (मई 2021 तक)	
कुल		**2113**		

संविक्षा से पता चला है कि मानदंडों के निर्धारण में विलंब के लिए मुख्य कारण एनसी की बैठकों की कार्यसूची में मामलों की सूची तैयार करने में देरी थी और संबंधित मंत्रालय/विभाग/तकनीकी विशेषज्ञों के सक्षम प्राधिकारियों से तकनीकी राय/टिप्पणियां प्रस्तुत करने में भी विलंब हुआ था। इसके अलावा, आरए से एनसी को आवेदन की प्राप्ति न होना/विलंब प्राप्तियां भी समग्र विलंब में जोड़ी गई।

सिफारिश संख्या-4 :चार महीने से लेकर 16 साल तक के मानदंडों के निर्धारण में देरी के साथ (जब एए योजना के तहत शुल्क मुक्त इनपूट और निर्यात के लिए निर्धारित समय सीमा क्रमशः 12 महीने और 18 महीने है), बिना मानदंडों

की श्रेणी के लिए मानदंड समिति (एनसी) प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही है और डीजीएफटी को दुरुपयोग की संभावना को कम करते हुए, इसकी व्यावहारिकता और व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि मुख्यालय में लंबित मामलों की समायिक समीक्षा की जा रही है और सभी एनसी को मानदंडों के निर्धारण में तेजी लाने को कहा गया है। इसके बाद 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी आईटी प्रणाली पेपर रहित होने की परिकल्पना की गई है जिसमें मध्यवर्ती चरण अर्थात एनसी को आवेदन करना, तकनीकी प्राधिकरणों की टिप्पणियां और इसकी प्रतिक्रियाओं को ऑनलाइन निपटाया जाएगा और मानदंडों के निर्धारण के लिए चार महीने की निर्धारित समय-सीमा प्राप्त होने की उम्मीद है।

आयात और निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए क्रमश 12 महीने और 18 महीने की समय-सीमा के प्रति चार महीने से लेकर 16 वर्ष तक की निर्धारित अवधि से अधिक मानदंडों के निर्धारण से काफी विलंब हुआ। समय पर मानदंडों को अंतिम रूप न देने के साथ ही निर्यातकों को निर्धारित अवधि के भीतर ईओडीसी जारी नहीं किया जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बांड और बीजी को अवरुद्ध किया जा सका बल्कि ईओ मामलों की पूर्णता न होने में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा, इससे मूल एएच को दंडित करने के अलावा चूक मामलों के लिए सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा फर्मों के प्रति कार्यवाही शुरू करने में भी देरी होती है, जिन्हें सभी निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने के बाद भी ईओडीसी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आगामी लेखापरीक्षाओं में नई आईटी प्रणालियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

2.4.3 किसी मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम समय सीमा का न होना

एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.17 में यह अनुबद्ध है कि आवेदक डीजीएफटी साइट पर निर्णय की होस्टिंग की तिथि से 90 दिनों के भीतर मानदंडों के निर्धारण के संबंध में एनसी के निर्णय के विरुद्ध पुनः विचार आवेदन कर सकता

है। 90 दिनों के बाद पुनः विचार आवेदन ₹ 5,000/- के संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन किया जाएगा।

आरए बेंगलुरु ने "बिना मानदंडों की श्रेणी" के तहत मेसर्स. ख लिमिटेड को एए (सितम्बर 2015) जारी किया, जिसकी एनसी द्वारा पुष्टि की जानी थी। एनसी ने मामला अस्वीकृत कर दिया (अगस्त 2018) और फर्म ने एनसी के निर्णय की समीक्षा के लिए एक पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2018), जो अभी भी लंबित है। ईओ की अवधि मार्च 2017 तक थी। फर्म द्वारा किए गए आयात पर शुल्क का भुगतान करके मामले को नियमित करने के लिए पूछे जाने पर (जनवरी 2019) फर्म ने आरए को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि समिति द्वारा "बिना मानदंडों की श्रेणी" के लिए मामले को अस्वीकार कर दिया गया था। आज तक आरए द्वारा आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

सीएलए दिल्ली द्वारा नमूना जांच से पता चला है कि तीन मामलों में, आवेदक ने एनसी द्वारा किए गए निर्णय की तिथि से 216 से 1,118 दिनों के बाद पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत किया और तीनों मामले अभी भी एनसी के पास विचाराधीन हैं।

आरए बेंगलुरु ने बताया कि फर्म ने एचबीपी 2015-20 के प्रावधान के अनुसार अस्वीकृति के प्रति एनसी के लिए पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत किया था। सीएलए दिल्ली से उत्तर प्रतिक्षित है।

एफटीपी/एचबीपी में एनसी के निर्णय के विरुद्ध पुनः विचार आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है जिसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारीं द्वारा एएच के प्रति कार्यवाही शुरू करने में विलंब होता है।

सिफारिश संख्या-5: डीजीएफटी एक समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है जिसके भीतर एनसी के निर्णयों की समीक्षा करने की अपील की जा सकती है।

डीजीएफटी ने सिफारिश की सराहना करते हुए बताया (फरवरी 2021) कि अगले एफटीपी को लाने के समय इसकी विस्तार से जांच की जाएगी।

2.4.4 एनसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आयात हकदारी

एनसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आयात या एनसी द्वारा मानदंडों को अनुमोदित करने में विलंब लेखापरीक्षित 893 एए में से सात में पाई गई थी, जिसमें तीन आरए में ₹2.04 करोड़ की शुल्क वसूली योग्य राशि शामिल है जिसे नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.6: एनसी द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त आयात हकदारी

क्र/स.	आरए	फर्म का नाम	एए की संख्या	एनसी के निर्णय	अतिरिक्त आयात (₹ लाख में)	टिप्पणी
1	जयपुर	मेसर्स सी लिमिटेड	1	अगस्त 2018	147.80	एनसी का निर्णय 19 महीने बाद आया है जिसमें अपशिष्ट को 5 और 2.9 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, जबकि फर्म ने 32 प्रतिशत का दावा किया था
2	मुंबई	मेसर्स डी लिमिटेड	3	अप्रैल 2016	48.87	एए बिना मानदंडों श्रेणी की पुनरावृत्ति के आधार के तहत जारी किए गए लेकिन परिशिष्ट 4ई और पिछले तीन वर्षों की घोषणा से पता चला है कि इनपुट की खपत एनसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से कम थी
3	दिल्ली	मेसर्स ई एंड एफ	3	सीएलए द्वारा सभी तीनों एए का मोचन कर दिया	6.98	निर्यात की गई मात्रा के उत्पादन में वास्तव में खपत होने वाले आयातित इनपुट की तुलना से अतिरिक्त आयात का पता चला
कुल			**7**		**203.65**	

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि सीएलए दिल्ली ने ₹ 8.94 लाख की वसूली की, और आरए मुंबई और जयपुर ने लागू सीमा शुल्क की वसूली के लिए फर्मों के प्रति कार्रवाई शुरू कर दी है।

2.4.5 मानदंडों के लिए एए आवेदन अस्वीकरण पर सीमा शुल्क का न होना

एचबीपी के पैरा 4.07 (i) के अनुसार, आरए एए जारी कर सकता है जहां किसी निर्यात उत्पाद के लिए कोई एसआईओएन/तदर्थ मानदंड नहीं है या जहां एसआईओएन/तदर्थ मानदंडों को अधिसूचित/प्रकाशित किया गया है लेकिन निर्यातक आवेदकों द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर विनिर्माण प्रक्रिया में अतिरिक्त इनपूट का उपयोग करना चाहता है। संशोधन/अस्वीकृति के मामले में, आवेदक डीजीएफटी वेबसाइट पर एनसी के निर्णय की होस्टिंग की तिथि से तीस दिनों के भीतर डीओआर द्वारा अधिसूचित शुल्क और ब्याज का भुगतान करेगा।

आरए मुंबई ने (जुन 2018) "बिना मानदंडों की श्रेणी" के तहत मेसर्स जी लिमिटेड को एए जारी किया और मामला एनसी को संदर्भित किया गया। यह पाया गया कि एनसी ने मानदंडों को यह कहते हुए कि "संबंधित विभाग/मंत्रालय से तकनीकी इनपुट उपलब्ध नहीं है" अस्वीकार कर दिया था (सितंबर 2018)। आवेदक को सलाह दी गई कि वह ड्राबैक मार्ग[8] अपनाए न कि तदर्थ एए मार्ग। इसके बाद, आरए को निर्देश दिया गया था कि ऐसे निर्यात उत्पाद के लिए तदर्थ मानदंडों के आधार पर कोई नया एए जारी न किया जाए।

चूंकि एनसी ने मानदंडों को अस्वीकृत कर दिया था, इसलिए एएच को सभी आयात पर आयात शुल्क का भुगतान करना और लाइसेंस को नियमित करना अपेक्षित था। हालांकि, आरए ने एए की वैधता को छह महीने (जून 2019 से दिसंबर 2019 तक) बढ़ा दिया और एए के प्रति किए गए सीआईएफ ₹23.49 करोड़ रुपये के आयात पर ₹3.52 करोड़ रुपये की लागू शुल्क अभी भी वसूली योग्य है।

इसी इकाई को एए जारी किया गया था (जून 2017) और मामले को मानदंडों के निर्धारण के लिए एनसी को संदर्भित किया गया। एनसी ने मानदंडों को अस्वीकृत कर दिया और इसलिए ₹7.03 करोड़ का अनुमानित परित्यक्त शुल्क वसूल किया जाना चाहिए था।

इसी तरह आरए कोच्चि में एनसी द्वारा अस्वीकृत किए गए चार मामलों में से दो में, एएच ने ₹1.06 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले इनपुट के आयात पर ₹24.50 लाख के परित्यक्त सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया। इसके अलावा, एक मामले में, आरए ने एनसी द्वारा अस्वीकृति के बाद भी छह महीने की आगामी अवधि के लिए प्राधिकार को फिर से वैध कर दिया, जो क्रम में नहीं है।

डीजीएफटी ने आरए मुंबई के संबंध में, बताया (फरवरी 2021) कि इस मामले को संबंधित एनसी के साथ उठाया जा रहा था और आरए कोच्चि के संबंध में,

---

[8]सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ड्राबैक दिया जाता है जिसके द्वारा निर्यातकों को निर्यात वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले इनपूट पर प्रदत्त करों का प्रतिदाय प्राप्त होता है। यह ड्राबैक वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित अधिसूचित दरों पर दी जाती है। अग्रिम प्राधिकार योजना का उपयोग करने वाले निर्यातकों को वापसी मार्ग का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि यदि वे शुल्कों के भुगतान पर घरेलू रूप से खरीदे जाने वाले कुछ इनपुट पर वापसी का दावा करना चाहते हैं, तो निर्यातक को प्राधिकार में आवेदन के समय ऐसी जानकारी पर वापसी का दावा करने का अपना आशय बताना अपेक्षित है।

लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए फर्मों के प्रति मांग नोटिस जारी किए गए थे।

2.4.6 चार्टर्ड इंजीनियर (सीई) के प्रमाण पत्र के बिना मानदंडों का निर्धारण

एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.06 के अनुसार, यदि एसआईओएन को अधिसूचित नहीं किया गया है, तो मानदंडों के निर्धारण के लिए डीजीएफटी में संबंधित एनसी को निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ 4 बी में आवेदन ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। एसआईओएन के निर्धारण के लिए, तकनीकी डेटा शीट (परिशिष्ट-4ई) और सीई प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-के में) निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

आरए अहमदाबाद में समीक्षित 335 एए (2 प्रतिशत) के चयनित नमूनों में से आठ में यह देखा गया कि किसी भी निर्यातक ने किसी भी आवेदन में निर्धारित परिशिष्ट-4के (एसआईओएन के निर्धारण के लिए सीई प्रमाण पत्र) प्रस्तुत नहीं किया; हालांकि, सभी प्राधिकरों में एनसी ने मानदंड निर्धारित किए। इन एसआईओएन के आधार पर निर्यातकों द्वारा आयात/निर्यात प्रभावित हुआ था और ईओडीसी को आरए द्वारा आठ मामलों में से पांच में जारी किया गया था जबकि शेष तीन मामले ईओडीसी के लिए लंबित हैं। इसके परिणामस्वरूप आठ प्राधिकरणों में परिशिष्ट 4के के बिना एसआईओएन का अनियमित निर्धारण हुआ, जिसमें ₹164.28 करोड़ का कुल सीआईएफ मूल्य शामिल है।

आरए अहमदाबाद ने बताया (नवंबर 2020) कि तदर्थ मानदंडों का निर्धारण संबंधित एनसी द्वारा किया जाता है। आरए का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसआईओएन आवश्यक सीई प्रमाण पत्र के बिना निर्धारित किया गया था।

2.4.7 एक ही निर्यात/आयात पर पहले के मानदंडों की वैधता अवधि के भीतर ही मानदंडों के निर्धारण के लिए आवेदन करना

एचबीपी के पैरा 4.12 में यह अनुबद्ध है कि जब एनसी स्व-घोषणा मानदंडों के तहत प्राप्त प्राधिकार के संबंध में समान निर्यात और आयात उत्पादों के लिए मानदंडों की पुष्टि करती है, तो ऐसे मानदंड संपुष्टि की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे और वहीं आवेदक ऐसे तदर्थ मानदंडों के आधार पर पुनरावृत्ति के प्राधिकार का लाभ उठा सकता है। डीजीएफटी ने पीएन 64 दिनांक 27 दिसंबर 2018 में एचबीपी के पैरा 4.12 में संशोधन किया और बताया कि

एनसी द्वारा संपुष्टि किए गए मानदंड एफटीपी की पूरी अवधि के लिए यानि मार्च 2020 तक या संपुष्टि की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होंगे, जो भी बाद में हो। चूंकि एनसी के सभी निर्णय डीजीएफटी वेबसाइट पर कार्यवृत के रूप में उपलब्ध हैं, इसलिए अग्रिम प्राधिकार के अन्य सभी आवेदक भी इन मानदंडों की वैधता के दौरान पुनरावृति के आधार पर ऐसे संपुष्टि मानदंडों के आधार पर आवेदन करने और अपने प्राधिकार प्राप्त करने के पात्र हैं।

आरए मुंबई ने मई और जून 2018 के दौरान एक ही फर्म को एक ही निर्यात/आयात के लिए एनसी द्वारा निर्धारित दो अलग-अलग मानदंडों के आधार पर मेसर्स एच लिमिटेड को दो एए (अप्रैल और जून 2018) जारी किए हैं।

इसी तरह का अवलोकन आरए कानपुर में किया गया था, जहां जनवरी 2015 में पहले भी इसी आयात/निर्यात के लिए अंतिम रूप दिए गए मानदंडों के आधार पर पुनरावृति आधार के तहत एए के लिए फर्म, मेसर्स आई लिमिटेड ने आवेदन किया (जुलाई 2016) था, लेकिन आरए ने मानदंडों के निर्धारण के लिए एनसी को मामला भेजा था, जो चार साल बीत जाने के बाद भी लंबित है।

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि मानदंडों में केवल 2 प्रतिशत अपशिष्ट की अनुमति दी गई थी और एएच द्वारा लिए गए किसी भी अन्य लाभ की वसूली की जाएगी।

आरए को पुनरावृति के आधार पर लगातार एए की अनुमति देनी चाहिए थी क्योंकि एनसी ने पहले से ही उसी कंपनी के लिए एक ही निर्यात/आयात मानदंडों की पुष्टि की थी और एनसी, जिसमें अधिक लंबित समय पहले से मौजूद है, आवेदन वापस कर सकता था क्योंकि मानदंड पहले से ही निर्धारित थे और संशोधन के रूप में आगामी दो वर्षों/विस्तारित अवधि के लिए वैध हैं।

2.4.8 एनसी द्वारा मानदंडों के निर्धारण में अन्य विसंगतियां

नौ एए के संबंध में तीन आरए (अहमदाबाद, कोच्चि और पुणे) में मानदंडों के निर्धारण में अन्य विसंगतियां देखी गईं, जिनमें ₹ 4.24 करोड़ की राशि का परित्यक्त शुल्क शामिल है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.7: मानदंडों के निर्धारण में अन्य विसंगतियां

क्र/सं.	आरए	फर्म का नाम	एए की संख्या	मद का विवरण	परित्यक्त शुल्क (लाख में)	टिप्पणियां
1	अहमदाबाद	मेसर्स जे लिमिटेड	2	प्रत्यक्ष भूरे रंग के एसबीआर (डाई)	398.62	आरए ने ईओडीसी (अक्टूबर 2018) जारी किया, भले ही एनसी द्वारा दो एए के लिए निर्यात की समान मात्रा के लिए एसआईओएन के निर्धारण में विसंगति थी और इसके आग्रह के बावजूद एनसी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण न करना।
2	कोच्चि	मेसर्स के लिमिटेड	1	कैप्सैसिन पाउडर	25.58	एएनएफ 4 एफ के अनुसार, 42.50 प्रतिशत आयातित इनपूटों का उपयोग नहीं किया गया। हालांकि, एनसी ने इस मामले को निपटाया (जुलाई 2019), आरए को मसाला बोर्ड, कोचीन की नमूना विश्लेषण रिपोर्ट (एसएआर) के आधार पर एए को मोचन करने का निर्देश दिया। आयात मद मसालों की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए मसाला बोर्ड के क्षेत्र में नहीं आता है। आरए, कोच्चि द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह मामला सीमा शुल्क विभाग के पास भी लंबित है।
3		मेसर्स एल लिमिटेड	5	रिफाइंड ओलेरेसिन पैप्रिका	-	आरए ने ईओडीसी जारी किया, भले ही निर्यात वस्तु एसआईओएन ई-95 के साथ संगत नहीं थी।
4	पुणे	मेसर्स एम लिमिटेड	1	बुना हुआ स्वेटर	-	एनसी पर लागू होने के बावजूद एसआईओएन मानदंड 71/161 मौजूद है।
कुल			**9**		**424.2**	

डीजीएफटी ने बताया (फरवरी 2021) कि मामला जांच के अधीन था और मांग नोटिस जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मानदंडों को शीघ्रता से निर्धारित किया जाएगा और अतिरिक्त आयात, यदि कोई हो, वसूल किया जाएगा।

2.5 अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) की अपर्याप्त निगरानी

एफटीडीआर नियम, 1993 के नियम 7 के साथ पठित एफटीपी 2015-2020 के पैरा 2.15 (सी) में बताया गया है कि सीमा शुल्क या विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून का उल्लंघन करने, ईओ की चूक और धोखाधड़ी और गलत घोषणा के मामले में, किसी इकाई को डीईएल के तहत रखा जा सकता है। इस तरह के जारी आदेश में कारणों को लिखित में दर्ज करने पर, किसी फर्म को वित्तीय या राजकोषीय लाभ प्रदान करने वाले लाइसेंस, प्रमाण पत्र, स्क्रिप या किसी भी साधन के अनुदान या नवीकरण को अस्वीकृत किया जा सकता है। एफटीपी के पैरा 2.15 (डी) बताता है कि डीईएल आदेश को एक समय में 60 दिनों की अवधि से अधिक के लिए आरए द्वारा लिखित कारणों से स्थगित रखा जा सकता है। इसके अलावा, पैरा 2.15 (ई) आरए लिखित कारणों द्वारा डीईएल से एक फर्म का नाम हटा सकता है, यदि फर्म आरए द्वारा जारी की गई मांग

नोटिस(ओं) की आवश्यकता को पूरा करती है/आरए द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करती है।

इसलिए, डीईएल तंत्र आरए को उन आवेदको को प्राधिकार देने से मना करने में मदद करता है जिन्होंने एफटीपी तथा एचबीपी के पिछले प्राधिकारो/प्रक्रियाओं की शर्तो का पालन नहीं किया है और ऐसी फर्मों को लाभ से वंचित कर सकता है। लेखापरीक्षित 1033 मामलों में से 193 (19 प्रतिशत) में निम्नलिखित अनियमित्ताएं पाई गई थी।

तालिका 2.8: डीईएल की अपर्याप्त निगरानी

क्रम. सं.	आरए का नाम	आरए की संख्या	टिप्पणी
1	हैदराबाद	175	आरए ने निर्यातक को डीईएल में रखने की तारीख से 10 वर्षों से अधिक समय के बाद प्राधिकारों का अनुपालन न करने के लिए डीईएल के तहत तीन फर्मो को रखा। इस बीच, इन्हीं फर्मो को 175 एए (150-मोचन और 25-गैर-मोचन) जारी किए गए, जिनमें ₹ 712.32 करोड़ सीआईएफ मूल्य शामिल था।
2	मुंबई	12	आरए ने दो फर्मो के संबंध में 68 डीईएल आदेशों को स्थगित करके ₹ 123.91 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 12 नए लाइसेंस इस तथ्य के बावजूद जारी किए, कि सांविधिक प्रावधानों जैसे निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत न करना आदि का अनुपालन न करने के लिए कई डीईएल आदेश जारी किए गए थे।
3	अहमदाबाद	3	आरए ने डीईएल मामलों के प्रबंधन के लिए डीजीएफटी परिपत्र (दिसंबर 2003) में निर्दिष्ट औपचारिक स्थगन आदेश जारी किए बिना डीईएल के तहत पांच फर्मों को ₹ 43.52 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ पांच लाइसेंस जारी किए।
4	पुणे	2	
5	कानपुर	1	आरए ने किसी भी कारण को अभिलेखित किए बिना ₹ 5.38 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ एए जारी किया, यद्यपि फर्म को आरए कोलकाता और वडोदरा द्वारा डीईएल सूची में रखा गया था। यह देखा गया कि ईओपी की समाप्ति से 20 महीने बीत जाने के बाद, आरए ने एए धारक को डीईएल (जुलाई 2019) पर सूचीबद्ध किया और सीमा शुल्क पत्तन (आईसीडी-जेआरवाई कानपुर) को लाइसेंस के उपयोग के लिए कहा (नवंबर 2019)। हालांकि, सीमा शुल्क पत्तन के रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि लाइसेंस पत्तन पर पंजीकृत नहीं था।
कुल		**193**	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि स्थगन को एक आईईसी को प्रदान किया जाता है न कि व्यक्तिगत फाइलों को। इसलिए, एक बार स्थगन प्रदान करने के

बाद, उक्त आईईसी के तहत डीईएल में सभी फाइलों को परिचालन न होना माना जाता है। मामले की जांच की जा रही है और यथासमय स्थिति की सूचना दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में डीईएल तंत्र का कार्यान्वयन पाया गया, जो निर्यातकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए माना जाता है, डीईएल के तहत ईकाईयों को रखने में 8 से 13 वर्ष की अत्यधिक देरी हो रही थी और कई स्थगन आदेश जारी किए जा रहे थे, जो इसकी अप्रभाविता को दर्शाता है। जैसा कि उपरोक्त उदाहरणों से देखा गया है, स्थगन आदेश बिना किसी कारण को अभिलेखित किए जारी किए गए थे और एए को डीईएल वस्तु-स्थिति बिना स्थगन आदेश जारी किए जारी किया गया था। इसके अलावा, मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं के तहत किसी निर्यातक को जारी किए जा सकने वाले स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। डीजीएफटी ने आखिरी बार मार्च 2021 में डीईएल को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसमें 21 अक्टूबर 2016 से लगाए गए जुर्माने का दर्शाया।

इसके अलावा, आरए के लिए यह जानने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि आवेदक को सीमा शुल्क अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत दंडित किया गया है, क्योंकि सीमा शुल्क और डीजीएफटी कार्यालयों के बीच ऐसे दंडित ईकाईयों के बारे में सूचनाओं का कोई आदान-प्रदान नहीं होता। प्राधिकार को जारी करना पूरी तरह से आवेदकों की स्व-घोषणा पर आधारित है।

सिफारिश संख्या 6: डीजीएफटी समय पर ढंग से डीईएल को अद्यतन करना सुनिश्चित कर सकता है और आस्थगन आदेश जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, डीईएल में पूर्व अवधि के लिए लगाए गए दंड का विवरण, और की गई कार्रवाई के परिणाम, की गई वसूली, निर्णय आदि को शामिल करना चाहिए। आस्थगित आदेश के अनुदान से पहले लंबित निर्यात में शामिल शुल्क के लिए या आस्थगन आदेशों के विरुद्ध जारी किए गए नए लाइसेंसों के संबंध में शामिल शुल्क के लिए पूर्ण बीजी के रूप में राजस्व हित को बीजी के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ईसीए डिवीजन ने एफटीडीआर अधिनियम के तहत अधिनिर्णयन कार्यवाही के लिए सभी आरए को आदर्श दिशानिर्देश और समय-सीमा (जनवरी 2021) जारी की है । अधिनिर्णयन की कार्यवाही की व्यापक निगरानी के लिए नई आईटी प्रणाली लागू की जा रही थी।

डीजीएफटी का उत्तर प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि डीईएल की निगरानी और स्थगन आदेश जारी करना अधिनिर्णयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

2.6 अपात्र आवेदकों को प्राधिकार का अनियमित जारी किया जाना

लेखापरीक्षा ने छह आरए में 2,555 मामलों की समीक्षा की और 56 मामलों (दो प्रतिशत) में निम्नलिखित कमियां पाईं:

2.6.1 लघु उद्योगों (एसएसआई) इकाइयों को अपनी क्षमताओं से अधिक प्राधिकार जारी करना

आरए पुणे ने अगस्त 2015 से मई 2016 तक 18 प्राधिकार (मेसर्स एन लिमिटेड और मेसर्स ओ लिमिटेड, प्रत्येक को नौ) जारी किए, जिसमें ₹ 29.64 करोड़ की बचत-शुल्क के साथ ₹ 132.28 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ तांबे की छड़ें के आयात की अनुमति दी गई।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि कोंधवा, पुणे में स्थित दोनों फर्मों के पास एसएसआई पंजीकरण था, जिनका कारोबार केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रावधान के अनुसार केवल डेढ़ करोड़ रुपये के भीतर होने की उम्मीद है। किसी भी फर्म का कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं था और न ही उन्होंने जारी किए गए एए के विरूद्ध कोई निर्यात किया था, यद्यपि उनके ईओपी की अवधि अगस्त 2017 में समाप्त हो गई थी। दोनों फर्मों को एससीएन जारी किए गए हैं।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह देखा गया था कि राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने पुणे में स्थित कोंधवा और बद्दी में निर्यातकों पर मामला दर्ज किया (प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसंबर 2018) जिन्होंने एए योजना का दुरुपयोग करते हुए ₹ 40 करोड़ सीमा शुल्क वाले ₹ 173 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ तांबा छड़ों का आयात किया। वास्तव में इन इकाइयों में विनिर्माण सुविधाएं नहीं थीं और उन्होंने अपने इनपुट को खुले बाजार में परिर्वतित कर दिया।

अभिलेखों, पिछले प्रदर्शन और वार्षिक क्षमताओं की जांच किए बिना 18 प्राधिकारों को जारी करना और छोटी ईकाइयों को 10 महीने की अवधि के भीतर ₹ 132.28 करोड़ मूल्य वाले शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना, उन ईकाइयों को जो पहली बार आवेदन कर रही हो, दुरुपयोग होने के जोखिम से भरा है।

इसी तरह की एक अभ्युक्ति में, आरए मुंबई ने, ₹ 20.48 करोड़ की शुल्क बचत वाले ₹ 92.38 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ माल आयात करने के लिए तीन एसएसआई इकाईयों (मेसर्स पी लिमिटेड, मेसर्स क्यू लिमिटेड और मेसर्स आर लिमिटेड) को जो पहली बार आवेदन कर रहे थे और जिनके पास कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं था, 15 एए जारी किए। ईओ को पूरा करने में दो फर्में नाकाम रही हालांकि ईओपी सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी और तीसरी फर्म ने अब तक निर्यात प्रदर्शन का कोई सबूत पेश नहीं किया है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि एफटीपी बिना निर्यात प्रदर्शन वाले एसएसआई इकाईयों वाले निर्यातकों की साख पर टिप्पणी नहीं करता है। डीआरआई के संदर्भ के आधार पर फर्म को डीईएल के तहत रखा गया है। दोनों फर्मों को एससीएन जारी किया गया है और इस मामले में प्रगति को अपडेट किया जाएगा। मुंबई स्थित अन्य तीन फर्मों के संबंध में उत्तर प्रतिक्षित है।

सिफारिश संख्या 7: डीजीएफटी को पहली बार माल आयात/निर्यात करने की मांग करने वाली फर्मों (विशेष रूप से एसएसआई इकाइयां जिनका कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं है) को कई एए जारी करने से पहले निर्यातकों की साख को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डीजीएफटी को नए एए जारी करने से पहले पूर्व एए, यदि कोई हो, के संबंध में ईओडीसी के पूरा होने का सत्यापन करना चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि मौजूदा प्रावधानों में स्व-घोषणा के आधार पर जारी किए गए एए के लिए मूल्य सीमाएं हैं। डीजीएफटी ने सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 (अक्टूबर 2004) का हवाला दिया जिसमें बीजी को लगाकर राजस्व हितों की रक्षा की जाती है और हर मामले में कई एए जारी करने से पहले साख को सत्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती है।

मूल्य सीमा को एए के लिए स्व-घोषणा के आधार पर निर्धारित किया गया है न कि सभी श्रेणियों के लिए एए यानी, एसआईओएन आधारित, स्व-संपुष्टि योजना, आवेदक विशिष्ट मानदंडों और स्व-घोषणा योजना के लिए पूर्व निर्धारण। चूंकि एसएसआई पंजीकरण में केवल डेढ़ करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है, इसलिए बिना किसी पूर्व निर्यात अभिलेखों के कई एए के लिए आवेदन करने वाली फर्में डीआरआई के संदर्भ से स्पष्ट रूप से दुरुपयोग के जोखिम से भरी हुई हैं। ऐसे मामलों में अभिलेखों को सत्यापित करना समझदारी होगी। यह पता

लगाए जाने पर कि क्या 15 प्रतिशत या बढ़ाए गए मूल्य के बीजी को लिया गया था, डीजीएफटी ने कहा कि यह मामला डीओआर से संबंधित है और डीओआर की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकती हैं। डीओआर का उत्तर प्रतिक्षित है।

2.6.2 अपात्र फर्मों को एए जारी करना

एचबीपी के नियम 4.42 (ए) के अनुसार, एए के तहत ईओ की पूर्ति की अवधि प्राधिकार जारी होने की तिथि से 18 महीने होगी और एचबीपी के नियम 4.44 (बी) के अनुसार, एएच, ईओ की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार के विरूद्ध शिपिंग बिलों का विवरण जोड़कर ऑनलाइन आवेदन फाईल करेगा। यदि एएच, ईओ को पूरा करने में विफल रहता है या प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरए प्राधिकार और शपथ-पत्र की शर्त को लागू करेगा और चूककर्ता निर्यातक को आगे प्राधिकार से इनकार करने सहित कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा।

सीएलए दिल्ली और आरए जयपुर ने ₹ 13.94 करोड़ के परित्यक्त शुल्क वाले ₹ 52.07 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ नए लाइसेंस इसके बावजूद जारी किए, कि एएच ने पिछले लंबित पांच एए के मोचन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। सीएलए दिल्ली में, नए लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय आवेदनकर्ता ने घोषणा में बताया कि निर्धारित ईओ की अवधि समाप्त होने के बावजूद पूर्व ईओ को पूरा नहीं किया गया।

आरए जयपुर ने उत्तर दिया (मार्च 2020) कि उक्त फाइल को मोचन फाइलों के बंडल के साथ समीक्षा किए बिना अभिलेख शाखा को भेज दिया गया था तथा फर्म मामले के मोचन के लिए पहले ही दस्तावेज प्रस्तुत कर चूका है और फर्म को पहले ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए डीएल/रिमाइंडर भेजे दिए हैं । सीएलए दिल्ली ने उत्तर दिया (अगस्त 2020) कि फर्म डीईएल के तहत नहीं थी और इसलिए एए शर्तों के साथ जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपात्र फर्म को जारी किए गए नए प्राधिकार विदेशी व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 7 के प्रावधान का उल्लंघन था।

एए योजना का उद्देश्य निवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना है। पिछले

एए के निर्यात दायित्व को समयबद्ध तरीके से पूरा न करने पर किसी फर्म को नए लाइसेंस जारी करना योजना के उद्देश्य को विफल करता है।

सिफारिश संख्या 8: डीजीएफटी नए एए जारी करने से पहले एएच द्वारा लंबित एए के मोचन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की निगरानी के बारे में आरए को दिए गए अपने निर्देशों को दोहरा सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि स्वत: भरण सुविधा को लागू कर दिया गया है और लंबित एए के मोचन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने की उचित निगरानी के लिए आरए को आवश्यक निर्देश दोहराए गए हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

2.6.3 गैर/प्रासंगिक आरसीएमसी वाले ईकाईयों को प्राधिकार जारी करना

एचबीपी के पैरा 2.94 (ए) के अनुसार, आरसीएमसी[9] के लिए आवेदन करते समय, एक निर्यातक को आवेदन में अपना मुख्य व्यवसाय घोषित करना होता है। निर्यातक को परिषद से आरसीएमसी प्राप्त करना होता है जो उसकी मुख्य व्यावसाय के उत्पाद से संबंधित है। पैरा 294 (बी) के अनुसार, यदि कोई निर्यात उत्पाद किसी निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी)/कॉमोडिटी बोर्ड आदि द्वारा शामिल नहीं किया जाता है तो आरसीएमसी को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (एफआइईओ) से प्राप्त किया जाना है। एए के लिए आवेदन करते समय, आरसीएमसी के बारे में विवरण का उल्लेख आवेदक द्वारा एएनएफ 4-ए में किया जाना आवश्यक है।

दो आरए (मुंबई और पुणे) में 927 मामलों में आरसीएमसी की समीक्षा से पता चला है कि निर्यातकों के पास ₹ 51.96 करोड़ के परित्यक्त शुल्क सहित नौ प्राधिकारों में संबंधित ईपीसी द्वारा जारी किया गया आरसीएमसी नहीं था जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

---

[9] आरसीएमसी पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र है जो विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा प्रदान किया जाता है। यह आस अनुदान के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। एचबीपी के पैरा 2.94 में यह निर्धारित किया गया है कि आरसीएमसी को परिषद से लिया जाना है जो आवेदक के व्यापार की मुख्य लाइन के उत्पाद से संबंधित है। यदि किसी निर्यात उत्पाद को किसी निर्यात संवर्धन परिषद/कमोडिटी बोर्ड आदि द्वारा शामिल नहीं किया जाता है, तो उसके संबंध में आरसीएमसी को एफआईईओ से प्राप्त किया जाना है।

तालिका 2.9: आरसीएमसी न होना/प्रासंगिक आरसीएमसी वाले सत्वों को प्राधिकार जारी करना

क्र.सं.	आरए का नाम	एए की सं.	परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)	आरसीएमसी की आवश्यकता	लिया गया आरसीएमसी	टिप्पणी
1	मुम्बई	1	11.77	सिंथेटिक एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपत्तन प्रमोशन काउंसिल (एसआरटीईपीसी),	कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपत्तन प्रमोशन काउंसिल	पॉलिएस्टर और विसकोस आधारित वस्त्रों के निर्यातकों को एसआरटीईपीसी से आरसीएमसी प्राप्त करना आवश्यक था
2	मुम्बई व पुणे	8	40.19	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), रासायनिक और संबद्ध ईपीसी, प्लास्टिक ईपीसी, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	एफआईईओ	निर्यातकों ने संबंधित परिषदों से लागू प्रमाण पत्र के बजाय एफईआईओ से आरसीएमसी लिया था
कुल		**9**	**51.96**			

आरए मुंबई और पुणे ने कहा कि जिन मामलों में निर्यातकों के पास कई उत्पाद हैं, वहां मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एफआइईओ से आरसीएमसी स्वीकार्य था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कई उत्पादों के मामलों में, आरसीएमसी को अपने मुख्य व्यवसाय के उत्पाद से संबंधित निर्दिष्ट परिषद से लिया जाना है।

2.6.4 एए का अनियमित जारी करना और वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति की पूर्ति न होना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.16 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि एए और/या एए के तहत आयातित सामग्री "वास्तविक उपयोगकर्ता" स्थिति के अधीन होगी। ईओ के पूरा होने के बाद भी इसे हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

आरए कोलकाता ने मेसर्स एस लिमिटेड को तीन एए जारी कर बद्दी हिमाचल प्रदेश के साथ मर्चेंट निर्यातक के रूप में, मेसर्स टी लिमिटेड की, इकाई ने एए में सहायक निर्माता के रूप में समर्थन किया। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आरसीएमसी के अनुसार मेसर्स एस लिमिटेड स्वयं एक विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत है। इसके अलावा दोनों फर्मों (मेसर्स एस लिमिटेड और मेसर्स टी लिमिटेड) का पता, फोन, ई-मेल, फैक्स और वेबसाइट एक जैसी थी। यह माल

अहमदाबाद में स्थित मेसर्स टी लिमिटेड द्वारा निर्यात किया जाता था जबकि हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित अन्य संयंत्र द्वारा विनिर्माण के लिए एए जारी किए गए थे। निर्यात दस्तावेज (एसबी/बीआरसी/चालान) में सहायक विनिर्माता (मेसर्स टी लिमिटेड) का नाम कहीं भी दर्शाया नहीं गया और इसलिए मेसर्स एस लिमिटेड द्वारा वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त की शर्त को पूरा नहीं किया गया। इसलिए ₹ 24.25 लाख की शुल्क छूट का लाभ अनियमित था, जिसे ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है ।

आरए कोलकाता ने बाद में मेसर्स एस लिमिटेड को जारी किए गए तीन एए को गठ-बंधन समझौते के सत्यापन और एक मर्चेंट निर्यातक के रूप में फर्म की घोषणा की शुद्धता की जांच के बिना मोचन कर दिया।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए कोलकाता की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

2.7 अपात्र आपूर्ति पर प्राधिकार को अनियमित जारी करना

2.7.1 अन्य एएच को की गई आपूर्ति और मसालों के लिए एए जारी करना

एफटीपी का पैरा 4.05 (सी) (iii) उस माल को निर्दिष्ट करता है जिसके लिए एए जारी किया जाएगा और श्रेणी 7.02 (ए) के तहत माल की आपूर्ति शामिल नहीं करता है, यानी एए के किसी अन्य धारक को माल की आपूर्ति के लिए एए जारी नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, एफटीपी के पैरा 4.11 (iii) में कहा गया है कि "आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय 9 और 12 के तहत वर्गीकृत 30 प्रतिशत से अधिक के मूल सीमा शुल्क वाले हल्की काली मिर्च (हल्का दाना) के अलावा अन्य सभी मसाले स्व-घोषणा के आधार पर आयात करने के लिए अग्रिम प्राधिकार के लिए पात्र नहीं हैं ।

मध्यवर्ती आपूर्ति और मसालों के संबंध में एए को जारी करने में अनियमितताएं आरए मुंबई और आरए कोच्चि में देखी गईं जैसा कि विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.10: मध्यवर्ती आपूर्ति और मसालों पर एए जारी करने में अनियमितताएं

क्रम.सं.	आरए	मामलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	मुंबई	1	2.22	आरए श्रेणी 7.02 (ए) के तहत तीन अन्य एएच को ₹ 21.78 करोड़ के एफओबी मूल्य के साथ सामग्री की आपूर्ति के लिए मेसर्स यू लिमिटेड को एए जारी (अक्टूबर 2017) किया गया है, जिसकी अनुमति नहीं है।
2	कोच्चि	1	1.15	आरए ने हल्की सफेद मिर्च के आयात के लिए स्व-घोषणा के आधार पर मेसर्स वी लिमिटेड को एए जारी (जूलाई 2016) किया जो 70 प्रतिशत के सीमा शुल्क को आकर्षित करता है। चूंकि शुल्क योजना के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था, इसलिए फर्म एए के अनुदान के लिए पात्र नहीं थी फर्म ने हालांकि लाइसेंस के विरूद्ध ₹ 143.33 लाख के सीआईएफ मूल्य के साथ हल्के मिर्च दाने का आयात किया।
कुल		**2**	**3.37**	

डीजीएफटी ने आरए मुंबई से संबंधित मध्यवर्ती आपूर्ति के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि एए को एफटीपी के पैरा 4.05 (ii) के अनुसार मध्यवर्ती आपूर्ति यानी अन्य एएच को आपूर्ति के लिए जारी किया जा सकता है। क्योंकि इसका पहले से ही पैरा 4.05 (सी) (ii) में उल्लेख किया गया है, इसलिए दोहराव और भ्रम से बचने के लिए क्रम संख्या 4.05 (iii) के विरूद्ध इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आरए कोच्चि के संबंध में, डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि फर्म को डिमांड नोटिस जारी किया गया है।

आरए मुंबई के संबंध में उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नए एफटीपी 2015-20 में पैरा 7.02 (ए) में पैरा 4.05 (iii) शामिल नहीं है।

2.7.2 विशेष रसायन, जीव, सामग्री और प्रौद्योगिकियों (एससीओएमइटी) मदों के निर्यात के लिए एए जारी करना

एचबीपी के पैरा 4.27 (सी) के साथ पठित एफटीपी के पैरा 4.18 (v) में यह अनुबद्ध है कि प्रतिबंधित एससीओएमईटी मदों का निर्यात, प्राधिकार या अनुमति की सभी शर्तों या आवश्यकताओं के अधीन आईटीसी (एचएस) की

अनुसूची 2 के अधीन हो सकता है, जिसमें डीजीएफटी से प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित एससीओएमईटी प्राधिकार शामिल हैं।

इसके अलावा, एए के लिए आवेदन करते समय, फर्म इस आशय की शपथ/घोषणा करती है कि निर्यात-आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में शामिल एससीओएमईटी मदों का अवलोकन कर लिया गई है तथा निर्यातित/प्रस्तावित मदे, जिनका निर्यात किया जाना है, इस सूची में नहीं आते।

आरए बेंगलुरु ने एयरोस्पेस श्रेणी के तहत विमानों के घटकों के निर्यात के लिए मेसर्स डब्ल्यू लिमिटेड को ₹ 150.60 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले छह एए जारी किए। हालांकि, सत्यापन करने पर निर्यात किए गए माल को सैन्य विमानों के घटक के रूप में पाया और एससीओएमईटी, आईटीसी (एचएस) के अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 की (क्र. सं. 5 डी 001)) मद की श्रेणी में आ रहे थे। इसलिए, फर्म को एएनएफ-2ई से डीजीएफटी में निर्यात प्राधिकार के लिए आवेदन फाईल करना चाहिए था और डीजीएफटी के संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय से निर्यात प्राधिकार प्राप्त करने के लिए अनुमति पत्र (एससीओएमईटी प्राधिकार) प्राप्त करना चाहिए था। हालांकि, यह पाया गया कि फर्म ने डीजीएफटी से अनुमोदन लिए बिना सीधे एए के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और आरए ने नीति का उल्लंघन करते हुए आवेदन/दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना प्राधिकार भी जारी किए थे। इसके अलावा, फर्म इस संबंध में गलत घोषणा देने के लिए एफटीडीआर अधिनियम 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि फर्म ने शपथ-पत्र में आश्वासन दिया कि निर्यात की गई वस्तुएं एससीओएमईटी के तहत शामिल नहीं हैं और एए प्राप्त करने के समय पर सीमा शुल्क पर निर्यात के लिए माल के निपटान के लिए एससीओएमईटी लाइसेंस प्राप्त करना फर्म की जिम्मेदारी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह आरए की जिम्मेदारी है कि वह निर्यात मदों का सत्यापन करे और यह पता लगाए कि क्या वे प्राधिकरण जारी करने से पहले एससीओएमईटी मदों की श्रेणी में आते हैं, और पूरी तरह से फर्म द्वारा की गई घोषणा पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, आरए द्वारा तत्परता न करने के परिणामस्वरूप उन मदों को एए जारी किया गया जो या तो लाइसेंस

के तहत अनुमत हैं या निषिद्ध है, यह एससीओएमईटी मदों के निर्यात के लिए दिशा-निर्देशों के विपरीत है

2.8 अन्य अनियमितताएं

2.8.1 एए जारी करते समय वित्तीय शक्तियों का पालन न करना

एए जारी करने के लिए वित्तीय शक्तियां डीजीएफटी द्वारा ओ.एम 1/2015 (फरवरी 2015) के संदर्भ में निर्दिष्ट की गई हैं, जिन्हें शुल्क छूट योजना के तहत एए संबंधित नामित प्राधिकारियों द्वारा जैसे एफटीडीओ, डिप्टी डीजीएफटी, ज्वाइंट डीजीएफटी, डीजीएफटी और एमओसीआई द्वारा वार्षिक आवश्यकता/डीएफआईए/अग्रिम निर्गम आदेश/गैर-वैधीकरण पत्र के लिए एए सहित जारी किया जाना है।

एए जारी करने में वित्तीय शक्तियों का पालन न करना निम्नलिखित उदाहरणों में देखा गया:

(i) आरए बेंगलुरु ने 2015-16 और 2017-18 के दौरान मेसर्स एक्स लिमिटेड को गोल्ड बार का आयात तथा गोल्ड मैडलिओन को निर्यात करने के लिए 86 एए जारी किए, जिसका कुल सीआईएफ मूल्य ₹ 84,201.64 करोड़ और एफओबी मूल्य ₹ 85469.52 करोड़ है। संवीक्षा में पता चला कि 2016-17 के दौरान 11 मामलों के संबंध में एक ही दिन दो से तीन एए जारी किए गए थे। इन सभी मामलों में प्रत्येक प्राधिकार का सीआईएफ मूल्य ₹ 1000 करोड़ से कम (अपर डीजीएफटी के स्तर पर मंजूरी के लिए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के भीतर) सीमांत रूप से रखा गया था ताकि एए को अनुमोदन और मंजूरी के लिए डीजीएफटी दिल्ली को न भेजना पड़े। **(अनुलग्नक 2)**

(ii) पांच आरए (अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पानीपत) में 835 मामलों में से 12 मामलों में प्रत्यायोजित शक्तियों का पालन नहीं किया गया।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि वित्तीय शक्ति ₹ 1000 करोड़ तक है और एए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के भीतर जारी किए गए थे। अन्य मामलों में, आरए ने डीजीएफटी की कार्योत्तर अनुमोदन की मांग की है।

डीजीएफटी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सभी मामलों में इनपुट और आउटपुट दोनों समान थे और एक ही दिन एए जारी किए गए हैं। प्राधिकारों को आगे की जांच और अनुमोदन के लिए डीजीएफटी को अग्रेषित करने से बचने के लिए विभाजित किया गया था, जिससे उक्त ओ.एम ने गतिरोध पैदा किया।

2.8.2 प्राधिकार पर बैंक गारंटी की शर्त का अंकन नहीं किया गया

एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.12 में यह निर्धारित किया गया है कि एचबीपी (बिना मानदंडों की श्रेणी) के पैरा 4.07 के तहत जारी किए जाने वाले प्राधिकारों का अधिकतम सीआईएफ मूल्य स्थिति धारकों के लिए पिछले वर्ष के निर्यात/आपूर्ति के एफओबी मूल्य का 300 प्रतिशत और अन्य लोगों के लिए ₹ 10 करोड़ या 300 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा। पैरा 4.13 में कहा गया है कि एक आवेदक सीमा शुल्क से छूट को शामिल करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण को 100 प्रतिशत बीजी प्रस्तुत करने के अधीन पैरा 4.12 में उल्लिखित पात्रता से अधिक पात्रता के लिए प्राधिकार का हकदार होगा। इस आशय का एक विशिष्ट अंकन प्राधिकार पर किया जाएगा ताकि सीमा शुल्क विभाग एए के पंजीकरण से पहले बीजी पर जोर दे।

आरए मुंबई ने 2018-19 के दौरान मेसर्स वाई लिमिटेड को बिना मानदंडों की श्रेणी के तहत ₹ 268.37 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ दो एए जारी किए। चूंकि पिछले वर्ष के निर्यात का एफओबी मूल्य ₹ 16.54 करोड़ था, इसलिए बीजी शर्त के बिना सीआईएफ मूल्य केवल ₹ 49.62 करोड़ (₹ 16.54 करोड़ के एफओबी मूल्य का 300 प्रतिशत) के लिए अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी बीजी शर्त के ₹ 218.75 करोड़ के अतिरिक्त आयात की अनुमति दी गई थी। 2019-20 के दौरान, एएच को आगे बिना किसी बीजी शर्त का अंकन किए, (₹ 1189.36 करोड़ की सीआईएफ मूल्य वाले) आठ एए जारी किए गए थे।

इसी तरह, आरए पुणे ने अतिरिक्त सीआईएफ मूल्य पर 100 प्रतिशत बीजी शर्त के अंकन के बिना ₹ 18.20 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए मेसर्स जेड लिमिटेड, पुणे को एए जारी किया, (नवंबर 2016) हालांकि फर्म ने स्वयं ₹ 3.47 करोड़ की शेष हकदारी का कार्यपत्र दिया था।

आरए मुंबई ने कहा कि दूसरा लाइसेंस पैरा 4.12 (ii) के अनुसार दोहराने के आधार पर जारी किया गया था, और एक बार एनसी द्वारा तदर्थ मानदंड तय किए जाने के बाद, बिना मानदंडों के तहत जारी लाइसेंस के लिए सीमाएं लागू नहीं होंगी। आरए पुणे ने कहा कि एए को हकदारी के भीतर सही ढंग से जारी किया गया था।

आरए मुंबई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों लाइसेंस एक ही तारीख (19.02.2019) को जारी किए गए थे और लाइसेंस में मानदंडों को जुलाई 2019 में अंतिम रूप दिया गया था, और दूसरा लाइसेंस केवल बिना मानदंडों के मामले के तहत जारी किया गया था। इसलिए, बीजी को दूसरे लाइसेंस के लिए जोर दिया जाना चाहिए था। आरए पुणे की प्रतिक्रिया ₹ 3.47 करोड़ की अतिरिक्त सीआईएफ की राशि फर्म की घोषणा को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत नहीं है।

2.8.3 100 प्रतिशत बीजी शर्त को अनियमित हटाना

एफटीपी के पैरा 2.58 डीजीएफटी को एफटीपी के प्रावधानों या उसमें निर्दिष्ट संबंधित समिति के साथ परामर्श के बाद ही किसी भी व्यक्ति को बड़ी, रिआयत या राहत देने के लिए अधिदेशित करता है। प्राधिकारों की किसी भी शर्त में रिआयत देने के मामले में डीजीएफटी को नीतिगत रिआयत समितियों (पीआरसी)[10] से परामर्श करना होता है।

आरए, पुणे ने 100 प्रतिशत बीजी शर्त के साथ मेसर्स एए लिमिटेड को एए जारी किया (नवंबर 2017) क्योंकि फर्म पहले ही अधिकतम हकदारी को पार कर चुकी थी। हालांकि, यह देखा था गया कि बीजी की शर्त को अपर डीजीएफटी, नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 27.11.2017 के आधार पर हटा दिया गया था। चूंकि, नीति शर्त में रिआयत देने की शक्ति पीआरसी के साथ परामर्श करने के बाद डीजीएफटी के पास थी इसलिए अपर डीजीएफटी से ईमेल के आधार पर बीजी शर्त को 100 प्रतिशत हटाना न्यायसंगत नहीं था। इसके अलावा ईमेल की अभिलेख प्रति अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, एएच ने निर्यात पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने में चूक की थी।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ईओ पूर्ति के दस्तावेज जमा करने के लिए मांग-सह-एससीएन जारी किया गया है। हालांकि, उत्तर ने बीजी की शर्त माफ करने को लेकर चुप्पी साध ली।

[10] नीतिगत रियायत समिति (पीआरसी) को नीति/प्रक्रियाओं (ईपीपी) से छूट के रूप में भी जाना जाता है। डीजीएफटी जनहित में ऐसे आदेश पारित कर सकता है या ऐसी रिआयत, रिआयत या राहत प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह एफटीपी या किसी भी प्रक्रिया के प्रावधान से किसी भी व्यक्ति या वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों को व्यापार पर वास्तविक कठिनाई और प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर उपयुक्त और उचित समझ सकता है।

2.8.4 निवलता के आधार पर प्राधिकार को गलत जारी करना

इंजीनियरिंग उत्पादों पर सामान्य नोट, एसआईओएन के पैरा 4 (क) के अनुसार जहां मानदंडों को मानकीकृत/प्रकाशित नहीं किया गया है और आवेदक केवल घटकों का आयात करना चाहता है, उसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बिना किसी बर्बादी के निवलता के आधार पर आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, अनुमत घटकों के आयात की अनुमति जवाबदेही खंड के साथ दी जाएगी और आयात के लिए मांगे गए घटकों के प्रकार, तकनीकी विनिर्देशों आदि को परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले घटकों के अनुरूप होना चाहिए, जिसे निर्यात दस्तावेजों में दर्शाया जाना चाहिए और इस आशय की शर्त का लाइसेंस पर अंकन किया जाएगा।

आरए मुंबई ने एकीकृत तारों के कवच निर्यात के लिए मेसर्स एबी लिमिटेड को एए जारी किया (मई 2017)। यह देखा गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 4ई (निर्यात उत्पाद की प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक इनपुट का प्रतिनिधित्व करने वाले तकनीकी डेटा) ने प्रत्येक निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक घटकों की विशिष्ट मात्रा का संकेत नहीं दिया, और संबंधित कॉलम में केवल 'नेट से नेट' कहा गया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए पिछले 3 वर्षों के उपभोग डेटा, प्रति निर्यात आइटम के लिए 0.06 से 22.74 खपत के किसी भी विशिष्ट पैटर्न को प्रदर्शित करने में विफल रहा। आवेदन, इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सामान्य नोट्स के निवलता प्रावधान के अनुरूप नहीं था; फिर भी, इस अनियमित जानकारी और गलत प्रमाणित डेटा के आधार पर लाइसेंस जारी किया गया था।

इसी तरह की टिप्पणी आरए कोयंबटूर में भी की गई थी जिसने ₹ 660.27 लाख वाले सीआईएफ मूल्य के साथ टूटी काजू गिरी के आयात के लिए मेसर्स एसी लिमिटेड क्विलन/पोलाची को एए जारी किया था (जुलाई 2015) जिसमें निवलता के आधार पर सूखे/भुना हुआ काजू के निर्यात के लिए 30 प्रतिशत से अधिक शुल्क शामिल था। एनसी ने मामलो को इस कारण का हवाला देते हुए अस्वीकृत कर दिया (दिसंबर 2013) कि आयात मद 30 प्रतिशत से अधिक सीमा शुल्क के साथ अध्याय 8 मद होने के नाते एए के अनुदान के लिए पात्र नहीं था। इसके बाद एनसी ने जवाबदेही शर्त के साथ निवलता के आधार पर लाइसेंस की अनुमति दी (जून 2014)।

खाद्य उत्पादों के लिए आयात नीति के सामान्य नोट में निवलता की अवधारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि खाद्य उत्पादों की श्रेणी में काजू गिरी निवलता श्रेणी के तहत पात्र नहीं है; हालांकि, लाइसेंस जारी किया गया था। प्राधिकार के वास्तविक उपयोग के आधार पर परित्यक्त शुल्क ₹ 297.12 लाख की गणना की गई।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि फर्म (मेसर्स एबी लिमिटेड) को डीईएल में रखा गया है और आरए कोयंबटूर ने दूसरी फर्म (मेसर्स एसी लिमिटेड) को एससीएन जारी किया है।

2.8.5 आवेदन फीस का कम संग्रहण

एचबीपी के परिशिष्ट-2के में आयात के सीआईएफ मूल्य के प्रति हजार रुपये की दर से कम से कम पॉच हजार रूपए तथा अधिकतम एक लाख रूपयें आवेदन फीस निर्धारित की गई है। एचबीपी के पैराग्राफ 4.40 के अनुसार, वृद्धि के लिए देय आवेदन फीस, अंतिम प्राधिकार और मूल सीआईएफ मूल्य में अंतर होगा।

पांच आरए (अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और विशाखापत्तनम) में 1,409 चयनित नमूना मामलों की समीक्षा से 34 मामलों (2.4 प्रतिशत) में ₹ 9.68 लाख की आवेदन फीस के कम संग्रहण का पता चला।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए विशाखापत्तनम ने चार मामलों में ₹ 1.29 लाख की वसूली की और अन्य आरए ने फर्मों को आवेदन फीस का भुगतान करने के लिए कहा है।

निष्कर्ष

डीजीएफटी मुख्यालय और पर्याप्त संचित रिक्तियों वाले आरए, दोनों में कर्मचारियों की भारी कमी थी, जिससे न केवल अग्रिम प्राधिकार बल्कि एफटीपी के अंतर्गत अन्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने में डीजीएफटी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

एए के जारी होने में पर्याप्त विलंब ने, 2015-16 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रक्रियाओं के सरलीकरण और कारोबार सुगमता के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्वचालित प्रणाली की विफलता का संकेत दिया। एए जारी करने की प्रक्रिया हालांकि स्वचालित थी आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग के रूप में आवश्यक मैनुअल हस्तक्षेप को मई

2019 में लागू किया गया, जिसके कार्यान्वयन की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी। तब तक, सभी निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे थे, जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा होने के बावजूद एए जारी करने में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप ऑनलाइन प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य को विफल किया।

लेखापरीक्षा ने मानदंड समितियों के साथ अग्रिम प्राधिकार आवेदनों की लंबित स्थिति की समीक्षा की। 31 मार्च 2019 तक, लंबित संख्या 5,606 थी जो 31 मार्च 2020 तक बढ़कर (7.8 प्रतिशत) 6044 हो गई ।

आयात और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए क्रमश 12 महीने और 18 महीने की निर्धारित समय सीमा के विरूद्ध 4 महीने से लेकर 16 वर्ष तक की अवधि से अधिक मानदंडों के निर्धारण में काफी विलंब हुआ। समय पर मानदंडों को अंतिम रूप न देने के साथ ही ईओडीसी को निर्धारित अवधि के भीतर निर्यातकों को जारी नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बांड और बीजी का अवरोध हुआ बल्कि इसके परिणामस्वरूप ईओ मामलों को पूरा न करने में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा, चूक के मामलों के लिए सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने में भी इससे विलम्ब होता है जो उस सही एएच पर शास्ति लगाने के अलावा है जिसे सभी अनुबद्ध शर्तों का पालन करने के बाद भी ईओसीडी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

एनसी के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार आवेदन के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप आरए और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क और उस पर ब्याज की वसूली करने के लिए एएच के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने में विलंब होता है।

लेखापरीक्षा में डीईएल तंत्र का कार्यान्वयन पाया गया, जो निर्यातकों को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए माना जाता है, डीईएल के तहत ईकाईयों को रखने में 8 से 13 वर्ष की अत्यधिक देरी हो रही थी और कई स्थगन आदेश जारी किए जा रहे थे, जो इसकी अप्रभाविता को दर्शाता है। मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं के तहत किसी निर्यातक को जारी किए जा सकने वाले स्थगन आदेशों की संख्या के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा, आरए के लिए यह जानने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि आवेदक को सीमा शुल्क अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत दंडित किया गया है, क्योंकि सीमा

शुल्क और डीजीएफटी कार्यालयों के बीच ऐसी दंडित ईकाईयों के बारे में सूचनाओं का कोई आदान-प्रदान नहीं होता। प्राधिकारों का मुद्दा पूरी तरह से से आवेदक की स्व-घोषणाओं पर आधारित है।

कई एए जारी करने से पहले आरए द्वारा अभिलेखों का कोई सत्यापन नहीं है, विशेष रूप से एसएसआई इकाइयों का, जिसमें कोई पूर्व निर्यात प्रदर्शन नहीं है और इन्होने अपनी स्थापित क्षमता से परे पर्याप्त आयात करने की मांग की है। इसके अलावा, पूर्व एए के ईओ को समय पर पूरा न करने पर किसी फर्म को नए लाइसेंस जारी करना योजना के उद्देश्य को विफल करता है।

सिफारिशें

1. ***डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग को योग्य संसाधनों के साथ संचित रिक्तियों को भरने के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए, ताकि यह अग्रिम प्राधिकार और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो, यदि डीजीएफटी इन योजनाएं को जारी रखने का इरादा रखता है, तो।***
2. ***डीजीएफटी यह सुनिश्चित करके एए को समय पर जारी करने के लिए मैनुअल और स्वचालित प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकता है कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूरा और पूर्ण आवेदन स्वीकार करने के लिए पुन: व्यवस्थित किया गया है। ऐसे निर्गमन की समयसीमा (या अन्यथा) की पर्याप्तता की समीक्षा भी की जा सकती है। तीन दिनों की निर्धारित समय-सीमा की तुलना में डीजीएफटी द्वारा एए जारी करने में महत्वपूर्ण विलम्ब (तीन महीने से दो वर्ष से अधिक) प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर आयातित वस्तुओं को प्राप्त करने की योजना के मूल उद्देश्य को विफल करता है। ऐसी विस्तारित अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।***
3. ***समय के साथ सभी क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं और सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी उन्नयन में प्रगति की, डीजीएफटी को 2009 में एचबीपी वॉल्यूम- II के माध्यम से अधिसूचित एसआईओएन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए।***
4. ***चार महीने से 16 वर्षों तक प्रतिमानों के नियतन करने में विलम्ब के साथ (जबकि एए योजना के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयातों और निर्यातों के लिए निर्धारित समयसीमा क्रमश: 12 महीने और 18 महीने है), बिना-मानदंड की***

श्रेणी के लिए मानदंड समिति (एनसी) की प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रही है और डीजीएफटी को प्रणाली की व्यापक रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि दुरूपयोग की गुंजाइश को कम करते हुए इसकी उपयोगिता और व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा सके।

5. ***डीजीएफटी समयसीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है जिसके अन्दर एनसी के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अपील की जा सकती है।***

6. *डीजीएफटी समय पर ढंग से डीईएल को अद्यतन करना सुनिश्चित कर सकता है और आस्थगन आदेश जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है। इसके अलावा, डीईएल में पूर्व अवधि के लिए लगाए गए दंड का विवरण, और की गई कार्रवाई के परिणाम, की गई वसूली, निर्णय आदि को शामिल करना चाहिए। आस्थगित आदेश के अनुदान से पहले लंबित निर्यात में शामिल शुल्क के लिए या आस्थगन आदेशों के विरुद्ध जारी किए गए नए लाइसेंसों के संबंध में शामिल शुल्क के लिए पूर्ण बीजी के रूप में राजस्व हित को बीजी के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।*

7. *डीजीएफटी को पहली बार माल आयात/निर्यात करने की मांग करने वाली फर्मों (विशेष रूप से एसएसआई इकाइयां जिनका कोई पिछला निर्यात प्रदर्शन नहीं है) को कई एए जारी करने से पहले निर्यातकों की साख को सत्यापित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, डीजीएफटी को नए एए जारी करने से पहले पूर्व एए, यदि कोई हो, के संबंध में ईओडीसी के पूरा होने का सत्यापन करना चाहिए।*

8. ***डीजीएफटी नए एए जारी करने से पहले एएच द्वारा लम्बित एए के मोचन दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने की निगरानी पर आरए को अपने अनुदेशों की पुनरावृत्ति करा सकता है।***

अध्याय III
योजना का कार्यान्वयन

अग्रिम प्राधिकार योजना, मोचन के लिए एए जारी करने और एएच को ईओडीसी जारी करने के संबंध में डीजीएफटी (एमओसीआई) द्वारा क्रियान्वयित की जाती है, जबकि एए के विरूद्ध आयातित इनपुट के साथ-साथ निर्यात के लेखाकरण पर सीमा शुल्क शुल्क के उदग्रहण से छूट अनुमत करने के लिए सीमा शुल्क पत्तनों पर एए का पंजीकरण सीमा शुल्क विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयित किया जाता है लेखापरीक्षा ने एए जारी करने की प्रक्रिया की जांच की और अध्याय 2 में हमारे मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख किया गया था। इस अध्याय में, लेखा परीक्षा में सीमा शुल्क विभाग और डीजीएफटी दोनों द्वारा एए योजना के कार्यान्वयन की जांच की गई थी। लेखापरीक्षा में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र की पर्याप्तता और क्या दोनों विभाग के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया जाता है, का भी सत्यापन किया गया ।

अभियुक्तियों को निम्नलिखित तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया थाः

- **सीमा शुल्क विभाग द्वारा योजना का कार्यान्वयन (पैरा 3.1)**
    - एए की वैधता अवधि से परे शुल्क मुक्त सामानों का आयात; (पैरा 3.1.1)
    - अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना (पैरा 3.1.2);
    - बांड की गैर-निगरानी (पैरा 3.1.3);
    - एए के तहत आईजीएसटी की गलत छूट; (पैरा 3.1.4)
    - अन्य अनियमितताएं (पैरा 3.1.5)
- **डीजीएफटी द्वारा योजना का कार्यान्वयन (पैरा 3.2)**
    - आरए द्वारा एए योजना की गैर/अपर्याप्त निगरानी (पैरा 3.2.1);
    - प्राधिकारों के संयोजन में अनियमितताएं (पैरा 3.2.2);
    - मूल्य वर्धन (वीए) से संबंधित अनियमितताएं (पैरा 3.2.3);

- स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय की वसूली न होना (पैरा 3.2.4);
- मोचन प्रमाण पत्र/ईओडीसी के लिए एएच द्वारा आवेदन फाइल करना (पैरा 3.2.5);
- आरए द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र जारी करने के दौरान अनियमितताएं (पैरा 3.2.6);
- अन्य अनियमितताएं (पैरा 3.2.7)

- **योजना के क्रियान्वयन में अंर्तविभागीय समन्वय (पैरा 3.3)**
    - सूचना साझा करने के लिए ऑनलाइन एमईएम का कार्यान्वयन न करना (पैरा 3.3.1);
    - चूककर्ताओं के विरूद्ध डीजीएफटी और सीमा शुल्क द्वारा की गई कार्रवाई के बीच बेमेल (पैरा 3.3.2);
- निर्यात प्रदर्शन का पता लगाने और चूककर्ता एएच पर कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र में खामिया (पैरा 3.3.3)

3.1 सीमा शुल्क विभाग द्वारा योजना का कार्यान्वयन

3.1.1प्राधिकारों की वैधता अवधि के बाद शुल्क मुक्त सामानों का आयात

एफटीपी के पैरा 4.17 के साथ पठित एचबीपी के पैरा 2.16 के अनुसार एए योजना के तहत आयात की वैधता अवधि एए जारी होने की तारीख से 12 महीने होगी। एचबीपी के पैरा 4.41 (ग) आगे पुर्नवैधीकरण द्वारा प्रत्येक छह महीने के दो विस्तार की अनुमति देता है। इस प्रकार, सामान्य श्रेणी के एए के आयात के लिए वैधता की अधिकतम अवधि 24 महीने है।

एए के तहत आयात उपयोग संबंधी ईडीआई डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि 786 मामलों में 24 महीने की विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद भी आयात की अनुमति दी गई थी, जिसमें ₹ 25.42 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल था, इनमें 191 दिनों से 2,156 दिनों तक की देरी हुई थी**(अनुलग्नक 3)**।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि एए की वैधता अवधि को 12 महीने की अवधि से अधिक बढ़ाने के संबंध में मुद्दा डीजीएफटी से संबंधित है और आयात

के लिए प्राधिकार की वैधता की अंतिम तिथि तदनुसार डीजीएफटी द्वारा सीमा शुल्क को प्रेषित की जाती है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामले दो छमाही एक्सटेंशन पर विचार करने के बाद थे। चूंकि एए की वैधता अवधि निर्दिष्ट है, इसलिए मंत्रालय (डीओआर) वैधता अवधि से परे लाइसेंस डेबिटिंग को प्रतिबंधित कर सकता है (योजना के तहत अनुमति दी गई अधिकतम दो एक्सटेंशन को ध्यान में रखते हुए) और कार्रवाई करने के लिए लाइसेंस की अंतिम तारीख प्रसारित करने के लिए डीजीएफटी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आयातों की तिथि पर बिना वैध लाइसेंस के हुए, शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जा रही है।

अधिकतम 24 महीने की वैधता अवधि से अधिक शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना (छ माह के दो विस्तार पर विचार करके) सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग मॉड्यूल में निगरानी तंत्र में दोष को इंगित करता है।

3.1.2 अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना

एचबीपी के पैरा 4.49 के अनुसार, ईओ की पूर्ति में वास्तविक चूक को डीओआर द्वारा अधिसूचित ब्याज के साथ आयातित/स्वदेश में खरीदी गई सामग्री के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क का भुगतान करके नियमित किया जा सकता है।

यह देखा गया कि सीमा शुल्क विभाग निम्नलिखित ₹ 15.47 करोड़ रुपये परित्यक्त शुल्क वाले 70 एए में एएच द्वारा किए गए अतिरिक्त आयातों की निगरानी नहीं कर रहा था जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.1 : अतिरिक्त आयात की निगरानी न करना

क्र म. सं.	पत्तन का नाम	एए की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	एसीसी हैदराबाद	68	1487.88	68 एएच ने ईओ की अवधि समाप्त होने के बाद जो 24 से 1743 दिनों तक था, अप्रयुक्त आयातों पर स्वेच्छा से सीमा शुल्क का भुगतान किया
2	एनसीएच मंगलुरु	1	55.26	एएच ने निर्धारित अवधि के भीतर ईओ के बैठक न होने की पुष्टि की। एससीएन जारी किया और बीजी भुनाकर ₹11.28 लाख की वसूली की गई थी।
3	कोलकाता पत्तन	1	3.71	सीमा शुल्क अपनी प्रणाली में बांड छूट प्रमाण पत्र के कम मूल्य को अपडेट करने में विफल रहा है जिसके कारण फर्म द्वारा बांड/बीजी के निष्पादन के बिना माल का अधिक आयात किया गया।
कुल		**70**	**1546.85**	

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि वर्तमान में सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं को उन मामलों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है जिनमें एएच ने ईओडीसी मोचन/विस्तार/संयोजन आदि के लिए डीजीएफटी को दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, और इसलिए सीबीआईसी ने क्षेत्रीय संरचनाओं को एएच को सामान्य नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। ऐसे मामलों में जहां ईओडीसी प्रस्तुत नहीं किया जाता है या डीजीएफटी कार्यालय में ईओडीसी के लिए आवेदन करने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, बांड की शर्त के अनुसार वसूली कार्रवाई सीमा शुल्क द्वारा शुरू की जानी है।

3.1.3 बॉन्ड की निगरानी न करना

3.1.3.1 सीमा शुल्क के साथ निष्पादित बांड़ को देरी से रद्द करना/रद्द न करना

सीबीआईसी के निर्देश (दिसंबर 2015) में कहा गया है कि एए जहां अनुमत ईओ की अवधि समाप्त हो रही है ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टों की सहायता से पहले ही पहचान की जा सकती है और आयुक्तों को निर्देश दिया गया था कि वे इसे एक सामान्य परिपाटी बनाएं कि बांड फाईल को प्राप्त करके एक दिन में संसाधित करने के लिए तैयार किया जाए। उक्त अनुदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी हो जानी चाहिए और सीमा शुल्क परिपत्र (मार्च 2010) के अनुसार यादृच्छिक जांच के लिए चयनित नहीं किए गए मामलों में निर्यातक के आवेदन प्राप्त होने की तिथि से सामान्य रूप से 10 दिनों के भीतर बांड/बीजी को निर्यातक को लौटा दिए जाएं। यादृच्छिक जांच के लिए चयनित मामलों के संबंध में, जांच के तहत मामलों को छोड़कर, 30 दिनों के भीतर के मानदंड को अपनाया जाना चाहिए। निम्नलिखित पत्तनों पर लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए 1,107 मामलों में से 224 मामलों (20 प्रतिशत) में बांड विलंब से रद्द करने/रद्द न करने के मामले देखे गए:

तालिका 3.2: सीमा शुल्क के साथ निष्पादित बांड की देरी रद्द न करना

क्रम.सं.	पत्तन का नाम	बांड की संख्या	टिप्पणियां
1	चेन्नई समुद्र	155	डीजीएफटी कार्यालय द्वारा ईओडीसी को प्रदान किए जाने के बावजूद रद्द करने के लिए लंबित बांड।
2	एसीसी और आईसीडी हैदराबाद	20	11 एए का पहले ही मोचन किया गया था और अन्य नौ एए के लिए ईओ की अवधि खत्म हो गई थी।
3	एसीसी और आईसीडी बेंगलुरु	49	ईओ की अवधि खत्म होने के बावजूद बांड रद्द नहीं किए गए। आरए बेंगलुरु ने मोचन पत्र जारी किए; हालांकि, बांड रद्द कर दिए गए और 30 से 591 दिनों की देरी के साथ निर्यातकों को वापस कर दिया गया।
	कुल	**224**	

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि निर्यातक द्वारा बांड रद्द करने के लिए ईओडीसी, शर्त पत्रक के साथ मूल प्राधिकार आदि जैसे दस्तावेजों के साथ बांड रद्द करने के आवेदन के बाद एए के लिए बांड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। निर्धारित समयावधि के बाद भी ईओडीसी न मिलने की स्थिति में, सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओ की अवधि समाप्त होने के साठ दिन के भीतर कार्रवाई शुरू की जानी है। क्षेत्रीय संरचनाओं को बांड का निपटान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने की सलाह दी जा रही है।

बांड के निष्पादन का प्राथमिक उद्देश्य एए योजना में वर्णित नियमावली और प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन सुरक्षित करना है; यह अनुपालन न करने के मामले में उचित शुल्क और ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने में अनुप्रासंगिक प्रतिभूति का भी कार्य करता है। सीबीआईसी के निर्देशों में निर्धारित समय पर बांडों को रद्द न किए जाने से परिणामस्वरूप न केवल वास्तविक एएच की निधियां अवरूद्ध होती है बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार को गलत संकेत भी जाता है।

3.1.3.2 बांड का निष्पादन न होना/अपर्याप्त निष्पादन

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18 (अप्रैल 2015) में आयातको द्वारा ऐसी सुरक्षा के साथ एए योजना के तहत आयातित सामग्री के निपटान के समय बांड

का निष्पादन करने का उपबंध किया गया है, जो उसे ऐसे आयातों पर उदग्राही शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। मर्चेंट नियातकों (एमई) को जारी किए गए एए के संबंध में, बांड को एमई और उसके सहायक विनिर्माता द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क विभाग के साथ निष्पादित 2,496 बांडों की समीक्षा की, जिसमें निम्नलिखित छह पत्तनों में 119 मामलों (4.76 प्रतिशत) में बांड के अपर्याप्त निष्पादन/निष्पादन न होने का पता चला, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: बांड का निष्पादन न होना/अपर्याप्त निष्पादन

क्रम. सं.	**पत्तन का नाम**	**मामलो की संख्या**	**टिप्पणियां**
1	एसीसी बेंगलुरु	51	आवंटित अवधि के भीतर ईओ की पूर्ति न करने के मामलों की पहचान करने और ₹ 2,638.19 करोड़ की राशि के बचत-शुल्क के बदले बांड डेबिट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। एनसीएच, मेंगलुरु ने अब तक पत्र जारी करते हुए ₹ 46.73 करोड़ की शुल्क के साथ दस मामलों के संबंध में एएच से विवरण मांगा है।
2	आईसीडी बेंगलुरु	15	
3	एनसीएच मंगलुरु	11	
4	जेएनसीएच मुंबई	4	मुंबई सीमा शुल्क द्वारा आरए मुंबई द्वारा जारी एए के लिए दिए गए बीजी आंकड़ों के प्रति-सत्यापन से पता चला है कि ₹ 10 करोड़ से अधिक के सीआईएफ मूल्य वाले 4 एए के संबंध में कोई बीजी नहीं लिया गया था, भले ही इन एएच द्वारा कोई निर्यात प्रभावित नहीं किया गया हो।
5	तूतीकोरिन पत्तन	22	आरए चेन्नई और कोयंबटूर से संबंधित पंजीकृत 314 बांडों में से 22 में बांडों की वैधता समाप्त हो गई।
6	आईसीडी जेआरवाई कानपुर	16	आरए कानपुर और वाराणसी से संबंधित 56 लाइसेंसों में से 16 मामलों में प्रत्येक आयात के विरुद्ध बांड राशि ठीक से डेबिट नहीं की गई। एक उदाहरण में, मेसर्स एडी लिमिटेड, कानपुर से संबंधित, लाइसेंस का सीआईएफ मूल्य बांड राशि के बजाय बांड लेजर में दर्ज की गई थी।
	कुल	**119**	

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा में बताए गए मामलों पर कार्रवाई की गई है। एए योजना से संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में बांडों की वैधता के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इन बांडों पर तब तक निरंतर देयता होती है जब तक निर्यातक डीजीएफटी द्वारा जारी ईओडीसी या एए योजना को नियंत्रित करने वाली संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचना के संदर्भ में ईओ की पूर्ति न होने की स्थिति में आवश्यक सीमा शुल्क जमा नहीं करता है। आरए मुंबई के चार मामलों में

100 प्रतिशत बीजी पर जोर न देने के संबंध में डीओआर ने कहा कि डीजीएफटी द्वारा कोई अंकन नहीं किया गया था और इसलिए बीजी की मात्रा सीमा शुल्क परिपत्र 58/2004 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार ली गई थी। लेखापरीक्षा की राय में, बांड की वैधता के लिए कोई समय निर्धारित नहीं करना उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है जिन प्राधिकारों के लिए बांड निष्पादित किए जाते हैं, उनकी एक निश्चित वैधता अवधि होती है। आरए मुंबई के चार मामलों में, लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई, एएच द्वारा किसी भी निर्यात को प्रभावित न किए जाने के बावजूद कोई बीजी नहीं लिया गया। डीजीएफटी द्वारा बीजी शर्तो को पूरा न करने के कारण प्रतिक्षित है।

3.1.3.3 बाद के आयात के मामलों के लिए विशिष्ट बांड प्रस्तुत न करना

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18 (अप्रैल 2015) में आयातक द्वारा आयात में बांड प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है, जिनका आयात यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 (शुल्क की छूट) या नियम 19 (2) के तहत पूर्ण रूप से ईओ के निर्वहन के बाद आयात किया जाता है और स्वयं को बाध्यकारी बनाने के लिए, अपने/सहायक विनिर्माता कारखाने में आयातित सामग्रियों का उपयोग शुल्क लगाने योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए और क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से या किसी निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से उक्त सामग्रियों की स्वीकृति की तारीख से छह महीने के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए, कि आयातित सामग्रियों का उपयोग किया गया है, सुविधा प्रदान की जाती है।

एसीसी, आईसीडी हैदराबाद और विशाखापत्तनम सागर पत्तन में यह देखा गया कि 58 एए में 133 बीई में से किसी में भी कोई विशिष्ट बांड प्राप्त नहीं किये गए। इसके अलावा, यह पता लगाने के लिए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि क्या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठाया गया था या नहीं, जिसके अभाव में एएच को सीमा शुल्क के लिए बांड प्रस्तुत करने, की आवश्यकता थी शुल्क लगाने योग्य माल के विनिर्माण के लिए आयातित इनपुट का उपयोग करने के लिए स्वयं को बाध्यकारी करना था और क्षेत्राधिकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी से या एक निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउंटेंट से मंजूरी की तिथि से छह महीने के भीतर उक्त सामग्री, का एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना था, कि उक्त सामग्रियों का उपयोग किया गया था। बांड प्रस्तुत किए बिना ऐसे शुल्क मुक्त आयात पर कुल शुल्क ₹ 12.39 करोड़ था।

विशाखापत्तनम सागर पत्तन में इंगित मामलों के संबंध में डीओआर ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि संबंधित आयातकों को पत्र जारी किए गए थे, जिसमें उन्हें बाद में किए गए आयात के विरुद्ध आवश्यक प्रमाण पत्र/विशिष्ट बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हैदराबाद सीमा शुल्क आयुक्तालय के संबंध में डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) था कि ईओ को पूरा करने की आवश्यकता थी और ईओ पूर्ति से पहले आयात किया गया था जिसमें शर्त (v) लागू नहीं है।

लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए मामले, पूरे ईओ की पूर्ति के बाद किए गए आयात से संबंधित थे और इसलिए शर्त (v) लागू थी। जेडीजीएफटी में प्रति-सत्यापन ने इस बात की भी पुष्टि की कि 22 बीई में ईओ की पूर्ति के बाद आयात हुआ था जिसमें मोचन के समय लाइसेंसधारियों द्वारा फाईल एएनएफ 4एफ आवेदनों से स्पष्ट हुआ कि इसमें सीआईएफ मूल्य ₹ 5.39 करोड़ और परित्यक्त शुल्क ₹ 1.99 करोड़ शामिल था।

सिफारिश संख्या 9: सीबीआईसी, ईओडीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए उचित बांड नवीकरण/रद्दीकरण सुनिश्चित करने के लिए ईओ अवधि की समाप्ति और एएच पर निर्भरता की आवश्यकता का निराकरण करने के लिए एक स्वचालित अलर्ट प्रणाली रखने पर विचार कर सकता है।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि डेटा को एकत्रित किया जा रहा है और बांड और ईओ अवधि समाप्त होने वाले के प्रतिवेदन उपलब्ध है। डीओआर, ईओडीसी डेटा ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के साथ संपर्क में है, जो सीमा शुल्क अधिकारी को इसे प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी को लिखने की आवश्यकता का भी निराकरण करेगा।

जब तक डीजीएफटी से ईओडीसी ऑनलाइन डेटा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि डीओआर, बांड नवीकरण/रद्दीकरण की प्रभावी निगरानी के लिए समयबद्ध तरीके से ईओ की स्थिति का पता लगा सकता है।

3.1.4 एए के तहत आईजीएसटी की गलत छूट

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18 (अप्रैल 2015), वैध एए लाइसेंस के विरूद्ध आयात पर पूरे सीमा शुल्क की छूट देता है। सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 79 (अक्टूबर 2017) में आईजीएसटी को पूर्व-आयात शर्त और भौतिक निर्यात के माध्यम से पूरा किए गए ईओ के अधीन छूट दी गई है। पूर्व आयात शर्त यह विचार करती है कि अग्रिम प्राधिकार के तहत आयातित कच्चे माल को भारत में

विनिर्मित अंतिम उत्पादों में शामिल करने के बाद उसे निर्यात किया जाता है। इसके बाद डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 53 (जनवरी 2019) ने आईजीएसटी छूट लेने के लिए पूर्व आयात शर्त हटा दी।

3.1.4.1 पूर्व आयात शर्त पूरी न होने के कारण आईजीएसटी का गलत अनुदान

इओडीसी फाईलों की समीक्षा और सीमा शुल्क पत्तनों से (निर्यात-आयात) ईएक्सआईएम डेटा के प्रति-सत्यापन से पता चला है कि अधिकृत पत्तनों पर सीमा शुल्क विभाग ने आरए (हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर, नई दिल्ली, अहमदाबाद और कोच्चि) द्वारा जारी 29 एए के संबंध में ₹ 8.35 करोड़ की राशि के आईजीएसटी का उदग्रहण नहीं किया था। आरए ने आईजीएसटी की उदग्रहण न करने की दिशा में बिना किसी मांग के 12 एए (29 एए में से) का मोचन किया, हालांकि एएच ने सीमा शुल्क अधिसूचना में निर्धारित पूर्व-आयात शर्त को पूरा नहीं किया।

आरए अहमदाबाद में अन्य चार मामलों में, पूर्व-आयात शर्त का पालन किए बिना ₹ 2.34 करोड़ की राशि का आयात किया गया था और इसलिए आईजीएसटी का भुगतान किया जाना था। फाईलों में विवरणों के अभाव में आईजीएसटी की राशि की गणना नहीं की जा सकी।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि विशाखापत्तनम और जयपुर सीमा शुल्क ने आयातकों को ब्याज के साथ आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए कहा है। हैदराबाद सीमा शुल्क के संबंध में, ईओ के निर्वहन से पहले सभी 16 प्राधिकार जारी किए गए हैं। सरकारी राजस्व के अनुरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 33 के अनुपालन के लिए फर्मों को पत्र जारी किए गए हैं और उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

3.1.4.2 मानित निर्यात पर आईजीएसटी का गलत अनुदान

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 79 (अक्टूबर 2017) आईजीएसटी को छूट देता है, बशर्ते निर्यात दायित्व को केवल भौतिक निर्यात द्वारा पूरा किया जाता है। निम्नलिखित तीन पत्तनों में 17 एए में ₹ 14.80 करोड़ की आईजीएसटी छूट का अनियमित अनुदान देखा गया:

तालिका 3.4: मानित निर्यात पर आईजीएसटी का गलत अनुदान

क्र म. सं.	पत्तन का नाम	एए की संख्या	आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया गया (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1	जेएनसीएच मुंबई	14	14.66	जेएनसीएच मुंबई में 4 फर्मों के संबंध में 14 एए, जिसमें भौतिक निर्यात को प्रभावित करने की आवश्यक शर्त का अनुपालन किए बिना ₹ 14.66 करोड़ की आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया गया था। एक फर्म मेसर्स एई लिमिटेड ने जेएनसीएच मुंबई के साथ कुल आठ एए पंजीकृत की थीं और ₹ 26.80 करोड़ की आईजीएसटी छूट प्राप्त की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने आठ में से केवल दो एए पर टिप्पणी की जिसमें ₹ 11.87 करोड़ की आईजीएसटी छूट का लाभ उठाया गया था जिसकी लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।
2	विशाखापट्टनम सीमाशुल्क	1	0.14	ईओडीसी की जांच से पता चला है कि आईजीएसटी छूट का दावा किया गया यद्यपि फर्म द्वारा किए गए सभी निर्यातों को मानित निर्यात[11] माना जाता था और कोई भौतिक निर्यात नहीं किया जाता था। एक बीई में, आईजीएसटी छुट ₹ 14.21 लाख था
3	नवाशेवा मुंबई	2	-	आरए वडोदरा ने मेसर्स एएफ लिमिटेड को दो एए जारी किए और ईओडीसी भी जारी किए, भले ही निर्यात मानित निर्यात के माध्यम से प्रभावित हुआ हो। इसके अलावा, एएच द्वारा अपेक्षित पूर्व-आयात शर्त का भी अनुपालन नहीं किया गया। आरए फाईलों में बीई की कॉपी न मिलने के कारण लेखापरीक्षा में इन बीई में शामिल आईजीएसटी के भुगतान का ब्योरा नहीं मिल सका।
	कुल	**17**	**14.80**	

आयात के समय, सीमा शुल्क विभाग के लिए मानित निर्यात के बारे में पता लगाना संभव नहीं है और इसलिए, यह आरए की जिम्मेदारी है कि वह उन मामलों में आईजीएसटी की वसूली के लिए सीमा शुल्क विभाग को सूचित करे जहां छूट के बाद निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है। आरए द्वारा सीमा शुल्क को इस तथ्य के अवगत नहीं कराने के परिणामस्वरूप ₹ 14.80 करोड़ की आइजीएसटी की वसूली नहीं हुई, जिसे उन उदाहरणों के साथ वसूली किए जाने की आवश्यकता है जहां टिप्पणी किए गए एए का बीई विवरण,

[11] एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.02 के अनुसार, "डीम्ड एक्सपोर्ट्स" उन लेनदेन को संदर्भित करता है जिनमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश नहीं छोड़ती हैं, और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुफ्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए गए सभी मामलों में एससीएन जारी किया है। डीजीएफटी ने आरए वडोदरा के संबंध में कहा (फरवरी 2021) था कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

3.1.5 अन्य अनियमितताएं

3.1.5.1 एए योजना से संबंधित अधिनिर्णयन आदेश पारित करने में वित्तीय शक्ति का पालन न करना

अनुमत प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में निर्यात संवर्धन योजनाओं से संबंधित मामलों के अधिनिर्णयन के लिए वित्तीय शक्तियां सीमा शुल्क मैन्युअल 2018 के पैरा 4.6 के साथ पठित सीमा शुल्क परिपत्र 24 (मई 2011) के तहत निर्दिष्ट हैं।

एसीसी मुंबई में यह देखा गया कि सभी अधिनिर्णयन आदेश सीमा शुल्क सह/उप आयुक्त/शुल्क छूट हकदारी प्रमाण पत्र (डीईईसी) सेल द्वारा उक्त निर्धारित मौद्रिक सीमाओं का पालन किए बिना पारित किए गए थे। अधिनिर्णित 42 मामलों में से केवल 17 पांच लाख रूपये से कम के थे और इसलिए एसी/डीसी के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर थे। शेष 25 मामलों में, 21 में शुल्क राशि पांच से 50 लाख रूपये तक शामिल थी और इस पर अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त द्वारा निर्णय दिया जाना चाहिए था और शेष चार मामलों में ₹ एक करोड़ से अधिक की शुल्क राशि शामिल थी और इसलिए सीमा शुल्क आयुक्त के स्तर पर निर्णय दिया जाना चाहिए था।

डीओआर ने कहा (दिसंबर 2020) कि यह मामला सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143 के तहत सरकारी बकाए की वसूली से संबंधित है। अब तक जारी नोटिस, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143 में निर्धारित प्रावधान को लागू करने के लिए सरकारी राजस्व की वसूली तक सीमित है, जिस तरह से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 में निर्धारित किया गया है, जिसके लिए उचित अधिकारी एसी/डीसी है जैसा कि उक्त धारा के प्रावधानों में उल्लेख किया गया है।

यह उत्तर सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 24 (मई 2011) और सीमा शुल्क मैन्युअल 2018 के अध्याय 13 के पैरा 4.6 के माध्यम से निर्यात संवर्धन योजनाओं

अर्थात अग्रिम प्राधिकार डीएफआईए/निर्यात को पुरस्कृत योजनाएं के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमाओं के विपरीत है।

3.1.5.2 एएएस की शर्तों को पूरा न करने के परिणामस्वरूप ईओडीसी का जारी न होना

आरए बेंगलुरु ने 2015-16 और 2016-17 के दौरान मेसर्स एक्स लिमिटेड, बेंगलुरु को ₹ 10,992.76 करोड़ के सीआईएफ मूल्य और सीटीएच 71131990 के तहत स्वर्ण पदकों का निर्यात करने के साथ सीमा शुल्क टैरिफ हैडिंग (सीटीएच) 71081200 के तहत स्वर्ण बार के आयात के लिए 11 एए जारी किए।

सीमा शुल्क ने एक अलग सीटीएच (71081300) के साथ एए में संशोधन किया ताकि वे निर्यातक द्वारा बताए गए उत्पाद के विवरणों के समझौते में नहीं थे। आरए बेंगलुरु ने ईओडीसी पर कार्रवाई करते हुए पाया कि आयात और निर्यात के आईटीसी (एचएस) कोड लाइसेंस से मेल नहीं खा रहे थे तो मामले को डीजीएफटी को भेज दिया उन्होनें मामले को डीओआर को भेज दिया। डीजीएफटी/डीओआर से स्पष्टीकरण अभी प्राप्त होना बाकी है। इस बीच, आरए ने चार लाइसेंसों (दो लाइसेंसों के संबंध में दो बार) में संशोधन किया और इस तरह के संशोधन के तथ्य को सीमा शुल्क को सूचित नहीं किया गया, जिन्होंने जारी संशोधनों का सत्यापन किए बिना बीई/एसबी में फर्म द्वारा दावा किए गए सीटीएच के अनुसार आयात और निर्यात की अनुमति भी दे दी। इसके बाद से एएच ने इन सभी मामले में ईओडीसी के लिए आवेदन किया है; हालांकि डीजीएफटी/डीओआर से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे आरए द्वारा कोई मोचन पत्र जारी नहीं किया जा सका है।

डीओआर ने (दिसंबर 2020) कहा कि प्राधिकारों के अनुसार एक ही सीटीएच के तहत आयात की अनुमति दी गई थी और डीजीएफटी द्वारा किए गए किसी भी संदर्भ के बारे में डीओआर को जानकारी नहीं है। डीजीएफटी के उत्तर प्रतिक्षित है।

3.1.5.3 आयातित वस्तुओं के पुर्ननिर्यात और पत्तनों द्वारा विस्तृत संवीक्षा का चयन न करने जैसी अन्य विसंगतियों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.5: अन्य विसंगतियां

क्र.सं.	पत्तन/आरए का नाम	मुद्दा	मामलो की संख्या	टिप्पणी
1	आरए बेंगलुरु	एए योजना के तहत आयातित वस्तुओं का पुन: निर्यात	3 एए में 26 खराब वस्तुएं	सीमा शुल्क पत्तन के पास पुन: निर्यात का प्रमाण उपलब्ध नहीं था और पुन: निर्यात के लिए निर्धारित समय पहले ही पारित हो चुका था।
2	एनसीएच मेंगलुरु	एक पत्तन पर पंजीकृत प्राधिकरणों में से कम से कम पांच प्रतिशत में याद्दच्छिक जांच सीबीआईसी के निर्देशों (जनवरी 2011 और दिसंबर 2015) के संदर्भ में की जानी है।	-	एनसीएच मंगलुरू अपने पत्तनों पर पंजीकृत एए मामलों की नमूना जांच कर रहे हैं। हालांकि, नमूना जांच कराने पर आईसीडी और एसीसी बेंगलुरु द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

एए योजना के तहत आयातित माल के पुन: निर्यात के संबंध में डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि एससीएन को ब्याज के साथ परित्यक्त शुल्क की वसूली के लिए जारी किया जा रहा है। इस मामले में एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.43ए के संदर्भ में डीजीएफटी द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता है।

नमूना जांच के संबंध में आयातित शुल्क मुक्त इनपुट के प्राधिकार/उपलब्धता पर दर्शाए गए पते की सत्यता की जांच के संबंध में डीओआर ने (फरवरी 2021) कहा कि कुछ मामलों में याद्दच्छिक आधार पर नमूना जांच की गई है और इस संबंध में बोर्ड के निर्देशों का पालन किया जाएगा ।

3.2 डीजीएफटी द्वारा योजना का कार्यान्वयन

3.2.1 आरए द्वारा एए योजना की निगरानी न होना/अपर्याप्त निगरानी होना

एचबीपी के पैरा 4.44 (बी) और (एफ) में यह उल्लेखित है कि एएच, ईओ की अवधि समाप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर प्राधिकारों के विरूद्ध एसबी के विवरण को लिंक करके ईओडीसी आवेदनों को ऑनलाइन फाईल करेगा। आरए न केवल एए और शपथ-पत्र की शर्तो को लागू करेगा बल्कि दोषी निर्यातकों को आगे के प्राधिकार से इनकार करने सहित कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू करेगा।

आरए द्वारा एए योजना की निगरानी न करना/अपर्याप्त निगरानी पर निम्नलिखित कमियां पाई गईं-

3.2.1.1 निर्यात दायित्व की निगरानी न करना

यह देखा गया कि जिन मामलों में मोचन अवधि समाप्त हो गई थी, उनका पता लगाने के लिए आरए के साथ कोई प्रभावी प्रणाली मौजूद नहीं थी जैसा कि निम्नलिखित अभ्युक्तियों से देखा गया था:

तालिका 3.6: निर्यात बाध्यता की निगरानी न करना

क्र.सं.	आरए का नाम	लंबित मामले	टिप्पणियां
1	मुंबई और पुणे	6494	3,981 मामलों (61 प्रतिशत) में, एससीएन अभी जारी किए जाने हैं और कुछ मामलों में कार्रवाई दस वर्षों से अधिक समय से लंबित है। ₹ 654.94 करोड़ का छोड़ा गया शुल्क उन 44 नमूना मामलों के संबंध में है जिसमें आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि ईओ की अवधि समाप्त हो चुकी थी और मोचन के फाइलिंग की नियत तिथि भी बीत चुकी है।
2	चेन्नई, कोच्चि और कोयंबटूर	78	78 एए में कोई कार्रवाई नहीं की गयी जिसमें ₹ 56.58 करोड़ का छोड़ा गया शुल्क शामिल है जो एए जारी करने की तारीख से 30 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद और एएच द्वारा निर्यात के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने और न ही ईओपी का कोई विस्तार करने की मांग करने के बाद था। आरए चेन्नई और कोयंबटूर ने न तो कमी पत्र जारी किए और न ही इन एएच के विरुद्ध कोई एससीएन जारी किया।
3	बेंगलुरु	5032	आरए ने या तो कोई कार्रवाई नहीं की है, या पर्याप्त देरी के साथ कार्रवाई शुरू की है। आरए ने 21 मामलों में एए की शर्तों को लागू नहीं किया था। एमआईएस-4 रिपोर्ट के अनुसार, 1990 मामलों को ईओ पूर्ण/जांच के तहत दस्तावेज के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें से 341 मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
4	हैदराबाद और कटक	1126	2006 से मोचन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए मामले लंबित थे। नमूना मामलों की जांच से पता चला कि 48 मामलों में, एएच ने निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था।
5	दिल्ली और इंदौर	28	निर्धारित अवधि में ईओडीसी आवेदन दाखिल न करने पर एएच के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। अन्य 14 मामलों में, सीएलए दिल्ली ने 149 से 688 दिनों तक की देरी के बाद एएच को चेतावनी पत्र जारी किए
6	कानपुर	3	ईओपी की समाप्ति के 23 माह तक किसी भी निर्यात को प्रभावित नहीं करने के लिए आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरए ने निर्यात के विवरण के लिए मांग करते हुए पत्र जारी किया (अक्टूबर 2018) और आठ माह के बाद (जून 2019) डीईएल के तहत ₹ 1.67 करोड़' शुल्क वाला फर्म शामिल है।
7	अहमदाबाद	5	अवैधीकरण पत्रों के प्रति देशी रूप से अधिप्राप्त इनपुट की मात्रा की आरए द्वारा ईमानदारी से निगरानी नहीं की गई जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि अवैधीकरण के तहत अनुरोध किए गए सभी इनपुट को अधिप्राप्त करने के बावजूद शेष इनपुट को शून्य के रूप में नहीं दिखाया गया था।

क्र.सं.	आरए का नाम	लंबित मामले	टिप्पणियां
8	कोलकाता,	45	आरए ने ईओ को पूरा करने में विफलता के बावजूद चूककर्ता निर्यातकों को आगे प्राधिकार से इनकार करने या ईओ की अवधि समाप्त होने पर एएच द्वारा प्रासंगिक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने सहित प्रावधानों के अनुसार न तो प्राधिकार वचनबद्धता की शर्तों को लागू किया और न ही शास्तिक कार्रवाई शुरू की। आरए जयपुर ने चार मामलों में केवल चेतावनी पत्र जारी किए।
9	चंडीगढ़	3	
10	जयपुर	9	
11	वडोदरा	5	
12	पानीपत	3	
13	अहमदाबाद	2	
	कुल	12833	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि इस मुद्दे को हल करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कई मामलों में डीईएल के तहत एससीएन/चेतावनी पत्र जारी करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरए मोचन के लिए दावा करने के लिए एएच पर निर्भर करता है क्योंकि उन मामलों का जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गई है, पता लगाने के लिए मौजूदा प्रणाली में आरए के पास कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

सिफारिश संख्या 10: डीजीएफटी को ईओ की निरंतर और नियमित रूप से निगरानी करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है। अभी तक, उन मामलों को ट्रैक करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जहां ईओपी समाप्त हो गयी थी, और आरए ईओडीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए एएच पर निर्भर थे। एए के संभावित दुरुपयोग को कम करने के लिए, घरेलू इनपुट के प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातित इनपुट के संभावित विपथन को संबोधित करने के लिए डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली में सत्यापन जांच की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने (फरवरी 2021) कहा कि नए चालू किए गए (1 दिसंबर 2020) आईटी मॉड्यूल में, जिन मामलों में ईओपी समाप्त हो गया है, उनका पता लगाया जा सकता है और इओडीसी की स्थिति का पता लगाने के लिए आरए को एएच पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अवैधीकरण के संबंध में, यह कहा गया है कि अवैधीकरण सहित सभी संशोधनों को सीमा शुल्क सर्वर के साथ साझा किया जाता है। डीजीएफटी ने डीजी (सिस्टम) के साथ एक रीयल-टाईम डेटा हस्तांतरण प्रणाली स्थापित की है जिसमें आयात और तद्नुरूपी निर्यात के उपयोग की निगरानी निकट रीयल-टाईम में की जा सकती है।

लेखापरीक्षा द्वारा ईओपी की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल के होने में डीजीएफटी के प्रयास की सराहना की गयी है; हालांकि, चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान शामिल अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी, इसलिए इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

3.2.1.2 एए योजना के तहत अधिक आयात की निगरानी न करना

आठ आरए में समीक्षा किए गए 1,737 मामलों में से 22 में अधिक आयात की निगरानी न करना देखा गया:

तालिका 3.7: अधिक आयात की निगरानी न करना

क्र.सं.	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	मुंबई और पुणे	10	55.96	निर्यात के लिए आवश्यक मात्रा की तुलना में ₹ 3.16 करोड़ सीआईएफ मूल्य वाले माल का अधिक आयात।
2	कोयम्बटूर	1	15.36	मई 2019 में ईओ की अवधि समाप्त होने के बावजूद ₹ 52.18 लाख के मूल्य वाले अधिक आयात पर सीमा शुल्क की वसूली के लिए आरए द्वारा कोई डीएल/एससीएन जारी नहीं किया गया था।
3	कोच्चि	3	409.51	₹ 57.05 करोड़ मूल्य वाले 77.28 मीट बीपी लाईट बेरी और 98.86 मीट हल्दी का अधिक आयात।
4	दिल्ली	1	28.31	17550.14 किलोग्राम आयातित माल का अधिक आयात अप्रयुक्त रहा
5	हैदराबाद	1	21.34	एएच ने ईडीआई डेटा में नहीं दर्शाए गए एसबी के प्रति निर्यात का गलत दावा किया लेकिन आरए को प्रस्तुत मोचन आवेदन में दावा किया। इसके अलावा उसी एसबी को अलग आईईसी धारक द्वारा निर्यात करते हुए दिखाया गया है।
6	अहमदाबाद और वडोदरा	6	86.75	एनसी द्वारा तय मानदंडों से अधिक आयात
कुल		**22**	**617.23**	

आरए अहमदाबाद, पुणे और वडोदरा ने ₹ 28.56 लाख की वसूली की सूचना दी। आरए कोयंबटूर और हैदराबाद ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

3.2.1.3 एए योजना के तहत पूर्व आयात शर्त की निगरानी न करना

एचबीपी 2015-20 के परिशिष्ट 4जे पूर्व आयात शर्त के साथ निर्दिष्ट इनपुट के लिए ईओ अवधि निर्धारित करता है। पूर्व आयात शर्त में यह संकल्पना की गयी है कि अग्रिम प्राधिकार के तहत आयातित कच्ची सामग्री को भारत में विनिर्मित अंतिम उत्पादों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए, उसके बाद ही निर्यात किया जाए। निम्नलिखित मदों के संबंध में पूर्व-आयात शर्त लगाए बिना आरए द्वारा एए जारी किए गए थे:

तालिका 3.8: आरए द्वारा पूर्व-आयात शर्तों की निगरानी न करना

क्र.सं	इनपुट	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1	स्टेनलेस स्टील	अहमदाबाद	2	0.54	एए को पूर्व-आयात शर्त और 18 माह के नियमित ईओपी को पीएन 30/2017 का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था जिसमें छह माह के ईओपी के साथ पूर्व आयात शर्त लगाई गई थी। इसके अलावा, सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली में उपलब्ध आयात लेजर के साथ एएच द्वारा आरए को प्रस्तुत आयात दस्तावेजों के प्रति-सत्यापन से पता चला कि फर्म ने आरए के लिए दो आयात परेषण घोषित नहीं किए थे और एक परेषण, हालांकि ईओडीसी फाइल में आरए के लिए घोषित किया गया था, सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के आयात लेजर में नहीं दर्शाया गया था।
2	प्राकृतिक रबर	कोलकाता	35	7.65	एएच, 37 परेषणों के संबंध में पीएन 35/2015 के साथ पठित 39/2018 का उल्लंघन करते हुए पूर्व-आयात शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा और इसलिए आनुपातिक आयात मात्रा पर परित्यक्त सीमा शुल्क वसूली योग्य है। एकबार की छूट का लाभ एए को नहीं मिलेगा क्योंकि लाइसेंस के साथ संलग्न कंडीशन शीट में पूर्व आयात शर्त विशेषतया समर्थित है।
3		मुंबई	2	0.43	
4		हैदराबाद	4	0.95	सभी चार आयात पीएन 39/2018 के बाद किए गए थे और इसलिए पीएन के आंकड़ों तक किए गए आयात/निर्यात के लिए एक बार की छूट का लाभ एएच को नहीं मिलेगा। आरए ने पश्च आयात पहलू का सत्यापन किए बिना मोचन आदेश जारी किया।

क्र.सं	इनपुट	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
5	मसाले	कोच्चि	3	1.23	एएच ने ईओपी की समाप्ति के बाद आंशिक निर्यात किया जिस पर दो एए में ईओ पूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाना है। तीसरे एए में पूर्व आयात शर्त पूरी नहीं की गई।
6		मुंबई	1	0.09	90 दिनों की अपेक्षित ईओपी के बजाय 12 माह की ईओ अवधि के साथ एए जारी किया गया था।
7	कीमती धातुएं	मुंबई	2	10.76	एएच के अनुरोध के आधार पर आरए ने शर्तों को हटाया (जून 2018)। संशोधित प्रावधान पूर्वव्यापी स्वरूप के नहीं हैं और मई 2018 से पहले जारी किए गए एए के लिए ईओपी/पूर्व आयात शर्त को हटाना सही नहीं था।
8	फार्मास्यूटिकल उत्पाद	हैदराबाद	1	0.12	पूर्व आयात शर्त पूरी नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शुल्क मुक्त आयात हुआ।
कुल			**50**	**21.77**	

डीजीएफटी ने स्टेनलेस स्टील के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि इस मामले की जांच की जा रही है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उनके द्वारा निष्पादित बांड को जारी करते समय सत्यापित किया जाए। आरए कोलकाता के संबंध में टिप्पणी किए गए प्राकृतिक रबड़ के लिए यह कहा गया था कि एए एल्यूमीनियम के लिए जारी किया गया था और न कि प्राकृतिक रबर के लिए; आरए मुंबई के लिए, पूर्व-आयात शर्त का विशेष रूप से अंकन नहीं किया गया था और आरए हैदराबाद के लिए, उत्तर अभी प्रतीक्षित है। आरए कोच्चि के संबंध में टिप्पणी किए गए मसालों के मामले में फर्मों के विरुद्ध मांग नोटिस जारी किए गए हैं और आरए मुंबई के लिए यह कहा गया था कि ईओ को आयात की मंजूरी से 90 दिनों के भीतर पूरा किया, इसलिए ईओडीसी को सही ढंग से प्रदान किया गया था। आरए हैदराबाद के संबंध में टिप्पणी किए गए फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए यह कहा गया था कि मामले की जांच की जा रही है।

डीजीएफटी का जवाब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। आरए कोलकाता में प्राकृतिक रबड़ के लिए एए प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए जारी किए गए थे और आरए मुंबई में, एए में संशोधन शीट संख्या 1 (21 अगस्त 2015) के द्वारा पूर्व आयात शर्त का बाद में अंकन किया गया था। इसी प्रकार, आरए

मुंबई में मसालों के संबंध में डीजीएफटी का उत्तर कि ईओ को 90 दिनों के भीतर पूरा किया गया था, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि आयात फरवरी/मार्च 2018 में किया गया था और निर्यात अगस्त 2018 में प्रभावित हुआ था।

3.2.1.4 ईओपी का अनुचित विस्तार

एचबीपी के पैरा 4.4.2 (ई) के साथ पठित पैरा 4.42 (एफ) में बताया गया है कि आरए द्वारा ईओ में कमी के 0.5 प्रतिशत की संयोजन फीस के भुगतान के अधीन ईओपी की समाप्ति की तारीख से छह माह तक ईओ अवधि के एक विस्तार के लिए एएच के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। एएच को आरए को एक स्व-घोषणा यह कहते हुए प्रस्तुत करनी होगी कि अप्रयुक्त आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त इनपुट आवेदक के पास उपलब्ध हैं। एचबीपी के पैरा 4.42 (सी) में आरए द्वारा दूसरा विस्तार निर्धारित किया गया है, बशर्ते एएच ने यथानुपात आधार पर मात्रा के साथ-साथ मूल्य में न्यूनतम 50 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूरा किया हो।

ईओपी के विस्तार पर अनियमितताएं निम्नलिखित चार आरए में देखी गईं:

(i) आरए अहमदाबाद ने मैसर्स एजी लिमिटेड को दूसरा विस्तार प्रदान किया, भले ही फर्म ने अपने ईओ का केवल 17 प्रतिशत पूरा किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.07 करोड़ के शुल्क के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ विस्तार अनियमित रूप से प्रदान किया गया था।

(ii) आरए बेंगलुरु ने मैसर्स एएच लिमिटेड को एए जारी किया (जून 2017), जिसके लिए ईओ की अवधि दिसंबर 2018 में समाप्त हो गई। फर्म ने मई 2019 में विस्तार के लिए आवेदन किया (ईओपी की समाप्ति की तारीख से पांच माह बाद), जिसे इस आधार पर संयोजन फीस लगाए बिना स्वीकृत किया गया था (मई 2019) कि उन्होंने सभी आयातित सामग्रियों का उपयोग किया था और ईओ को किए गए आयात की सीमा तक पूरा किया था। हालांकि, उक्त एचबीपी के तहत यथा अपेक्षित कोई स्व-घोषणा एएच द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(iii) आरए कोलकाता ने मैसर्स एआई लिमिटेड को एए जारी किया जिसमें दूसरा पुनर्वैधीकरण प्रदान करते हुए नियमों के तहत यथा अपेक्षित वास्तविक निर्यात के अनुपात में आयात मात्रा सीमित नहीं थी।

(iv) आरए वाराणसी ने सात मामलों में एए के पुनर्वैधीकरण की अनुमति दी भले ही वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एएच ने आवेदन किया (**अनुलग्नक 4**)।

लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण की मांग के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी ऐसे अनुरोध मांगे जाते हैं। चूंकि लाइसेंस की वैधता एचबीपी के पैरा 2.16 में निर्दिष्ट है (निर्गम तिथि से 12 माह) और प्राधिकार भी आयात/निर्यात (एचबीपी के पैरा 2.18) की तारीख को मान्य होना चाहिए, लेखापरीक्षा की राय में पुनर्वैधीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा था (फरवरी 2021) कि अनुपालन के लिए फर्मों को पत्र जारी किए गए थे और एफटीपी/एचबीपी में पुनर्वैधीकरण की मांग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

डीजीएफटी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाइसेंस की वैधता एफटीपी/एचबीपी में निर्दिष्ट है और पुनर्वैधीकरण के किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 11: डीजीएफटी को पुनर्वैधीकरण प्रदान करने की क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्वैधीकरण के अनुरोधों को प्राधिकार की वैधता अवधि के भीतर ही स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि निर्यात दायित्व के लिए गणना किए गए कोई भी शुल्क मुक्त आयात या निर्यात प्राधिकार की वैद्धता अवधि में ही हों।

3.2.2 प्राधिकारों के संयोजन में अनियमितताएं

एचबीपी के पैराग्राफ 4.38 (xii) में कहा गया है कि संयोजन के बाद, एए को सभी उद्देश्यों के लिए एक प्राधिकार माना जाएगा। एमवीए (15 प्रतिशत) की गणना एए को मिलाने के बाद प्राप्त हुए कुल सीआईएफ/एफओबी के आधार पर की जाएगी और मूल्य या मात्रा में किसी भी कमी को एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.49 के अनुसार नियमित किया जाएगा।

3.2.2.1 प्राधिकारों के संयोजन के कारण अधिक आयात का पता न लगना

एचबीपी के पैरा 4.20 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि एएच ने आयातित से कम मात्रा में इनपुट की खपत की है, तो एएच अप्रयुक्त आयातित सामान पर सीमा शुल्क और उस पर ब्याज का भुगतान करने अथवा अप्रयुक्त रही सामग्री के निर्यात के लिए ईओ अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आरए अहमदाबाद ने मैसर्स एजे लिमिटेड को जारी किए गए पांच एए का संयोजन करने की अनुमति दी। निर्यातक एए के संबंध में किसी भी निर्यात को प्रभावित नहीं कर सका; हालांकि, आयात किया गया जिसके परिणामस्वरूप ईओ की पूर्ति नहीं हुई। यह देखा गया कि ईओडीसी आवेदन में निर्यातक द्वारा घोषित इनपुट में से एक से अधिक आयात को ईओडीसी प्रदान करते समय आरए द्वारा पता नहीं लगाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.05 लाख का शुल्क नहीं लगाया गया था।

इसी तरह, आरए चेन्नई ने फ्लोरस्पार (एसिड ग्रेड) के शुल्क मुक्त आयात के लिए मैसर्स एके इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दो एए जारी किए, जिसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के निर्यात दायित्व में ₹ 9.78 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल था और प्राधिकारों के संयोजन के आधार पर लाइसेंस का मोचन कर दिया गया था (दिसंबर 2019)। समेकित एएनएफ 4एफ की समीक्षा से 567.94 मीट्रिक टन अधिक आयात का पता चला, जिसे एएच द्वारा स्वीकार किया गया था। हालांकि, विभाग ने अधिक आयात को नियमित करने और ब्याज के साथ ₹ 10.38 लाख की शुल्क राशि की वसूली करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

डीजीएफटी ने आरए अहमदाबाद के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि मामले की जांच की जा रही है। आरए चेन्नई ने ₹ 2.12 लाख की आंशिक वसूली की सूचना दी।

3.2.2.2 एए के संयोजन पर संयोजन फीस का कम संग्रहण/संग्रहण न होना

एचबीपी के पैरा 4.38 (vii) के अनुसार, संयोजन करने पर जहां कहीं निर्यात पहले के प्राधिकार के ईओपी से परे है, ईओ में कमी के 0.5 प्रतिशत की संयोजन फीस लगायी जाएगी।

मैसर्स अल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आरए वडोदरा द्वारा जारी तीन एए के संयोजन के लिए आवेदन किया (मार्च 2019)। यह देखा गया कि तीनों संयोजन किए

गए प्राधिकारों के कुल मूल्य के बजाय केवल एक प्राधिकार में प्राप्त किए गए वीए पर आरए ने ईओडीसी प्रदान किया (मई 2019), जिसके परिणामस्वरूप वीए की कमी ₹ 41.25 करोड़ हो गई। प्राधिकार के संयोजन करने में गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 41.25 लाख की संयोजन फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

इसी प्रकार, आरए हैदराबाद में मैसर्स एएम लिमिटेड को अनुमत संयोजित प्राधिकारों पर ईओ में कमी के लिए ₹ 13.90 लाख की संयोजन फीस नहीं लगायी गयी। तीन अन्य मामलों में एएच द्वारा मांगे गए विस्तार पर ईओ में कमी के लिए ₹ 20.37 लाख की संयोजन फीस नहीं लगाई गई।

डीजीएफटी ने आरए हैदराबाद के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आरए वडोदरा ने एक मामले में ₹ 11.69 लाख की वसूली की सूचना दी।

3.2.3 मूल्य वर्धन (वीए) से संबंधित अनियमितताएं

एफटीपी 2015-2020 के पैरा 4.09 (i) के अनुसार, एए के तहत प्राप्त किया जाने वाला एमवीए 15 प्रतिशत है। एचबीपी 2015-2020 के पैरा 4.49 (बी) के अनुसार, यदि वीए न्यूनतम निर्धारण से कम रहता है, तो एएच को भारतीय रुपये में एफओबी मूल्य में कमी के 1 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। परिशिष्ट 4एच के अनुसार, शुल्क मुक्त आयात की खपत और स्टॉक का लेखांकन करने के लिए पंजीकृत या कच्चे माल, घटकों आदि की घरेलू खरीद आदि, एए/डीएफआईए के तहत अनुमेय है। एए (एएनएफ-4एफ) के मोचन के लिए आवेदन में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वीए के उद्देश्य से निर्यात का एफओबी मूल्य विदेशी एजेंसी कमीशन, यदि कोई हो, को छोड़कर प्राप्त होगा।

3.2.3.1 एफओबी मूल्य के लिए जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी राशि का गलत मानना

आरए मुंबई के तहत दो एएच ने 100 प्रतिशत ईओयू की आपूर्ति करके तीन एए के संबंध में मात्रा के साथ-साथ मूल्य के संदर्भ में भी ईओ प्राप्त किया। हालांकि यह देखा गया कि एफओबी के प्रति गिने जाने वाले बीजक मूल्यों में आईजीएसटी और कमीशन जैसी अपात्र राशि शामिल थी। अपात्र राशि को छोड़ने के परिणामस्वरूप एफओबी में ₹ 13.59 करोड़ की कमी आई और वसूली योग्य 1 प्रतिशत दंड राशि ₹ 13.59 लाख बनती है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए मुंबई को निर्देश दिया गया है कि वसूली प्रभावी होने तक फर्मों को डीईएल में रखा जाए।

3.2.3.2 एएच द्वारा वास्तविक आयात की घोषणा न करना

सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के लाइसेंस उपयोग आंकड़ों के साथ आरए (अहमदाबाद और वडोदरा) को प्रस्तुत ईओडीसी आवेदन के प्रति सत्यापन से पता चला कि 11 एए के प्रति सभी आयात ईओडीसी आवेदन में घोषित नहीं किए गए थे। एएच ने 147 परेषणों के वास्तविक आयात के प्रति अपने ईओडीसी आवेदनों में 123 आयात परेषण घोषित किए, जिससे उपयोग किए गए सीआईएफ का कम मूल्य दिखाई दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ के आयात को कम बताया गया। आरए इन गैर-घोषित वस्तुओं के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है और गलत तरीके से लाभ प्राप्त छूट की अननुमति देने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

इसी प्रकार की अभ्युक्तियां आरए (चेन्नई और कोयंबटूर) में भी की गई थीं जिनमें 13 एए का मोचन करके ईओडीसी को जारी किया गया था, हालांकि एएच ने निर्यात को प्रभावित करने के लिए वास्तव में आवश्यक मात्रा (एसआईओएन के अनुसार) की तुलना में कम मात्रा में इनपुट का आयात किया था। इसके अलावा, भुगतान किए गए शुल्क या घरेलू स्रोत के सामान (आयात के अलावा) के उपयोग की कोई घोषणा नहीं की गई थी और मोचन फाईल में दिखाई गई वास्तविक खपत (बर्बादी सहित) कम थी। परिशिष्ट 4एच में खपत के पूर्ण विवरण का संकेत न होने से खपत की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया जाता है **(अनुलग्नक 5)**।

डीजीएफटी ने आरए अहमदाबाद के संबंध में (फरवरी 2021) कहा था कि सीमा शुल्क संरचनाओं को उनके साथ निष्पादित बांड का निपटान करते समय यह सत्यापित करना होता है। अन्य आरए के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

डीजीएफटी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईओडीसी आवेदनों की समीक्षा करते समय क्षेत्राधिकारिक आरए द्वारा कम मात्रा में आयात के पहलू और वे निर्यात दायित्व को कैसे प्राप्त करते हैं, को सत्यापित किए जाने की आवश्यकता है। क्या किसी गैर-घोषित माल का उपयोग किया गया था, अवैधीकरण का विवरण आदि आरए द्वारा ईओडीसी जारी करने से पहले सत्यापित किया जाना चाहिए। एएच द्वारा आयात को कम बताने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

3.2.3.3 निवलता के आधार पर घटकों के आयात पर वीए का गलत अनुमान

इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी की क्रम संख्या 4 के साथ पठित सभी निर्यात उत्पाद समूहों के लिए सामान्य टिप्पणी की क्रम संख्या 6 और नीति परिपत्र 10/2018-19 (जुलाई 2018) के अनुसार, इनपुट के रूप में घटकों का आयात करने की मांग करने वाले आवेदक को बिना किसी अपशिष्ट के निवलता के आधार पर आयात करने की आरए द्वारा अनुमति दी जा सकती है जो आयात के लिए मांगे गए घटकों के जवाबदेही खंड और प्रकार, तकनीकी विनिर्देशों आदि के परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किए गए घटकों के अनुरूप होना चाहिए, व निर्यात दस्तावेजों में परिलक्षित होना चाहिए। इस आशय की एक शर्त लाइसेंस पर अंकन किया जाएगा। इसके अलावा, यदि घटकों की अधिप्राप्ति किसी मानदंड श्रेणी में नहीं आती है, तो आवेदक को चार्टर्ड/कॉस्ट अकाउंटेंट या क्षेत्राधिकारिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्यात उत्पाद की एक इकाई के विनिर्माण में आवश्यक सटीक घटकों (आयात और घरेलू दोनों इनपुट) का ब्यौरा देते हुए परिशिष्ट 4ई प्रस्तुत करना होता है।

आरए मुंबई और पुणे ने दो लाइसेंसों के संबंध में केवल आयातित घटकों पर विचार करते हुए वीए का अनुमान लगाया और न कि निर्यात उत्पाद की एक इकाई की आपूर्ति करने के लिए निवलता के आधार पर आवश्यक सभी घटकों पर। आयातित मात्रा एए में लागू मात्रा से कम थी जो संभव नहीं थी क्योंकि एक निर्यात सेट (निवलत के आधार पर जवाबदेही खंड) बनाने के लिए कम से एक घटक की आवश्यकता होती है। शेष मात्रा की अधिप्राप्ति और निर्यात सेट में उपयोग कैसे किया गया, इसकी जांच किए बिना लाइसेंस का मोचन किया गया। 4एच खपत पत्रक और जवाबदेही विवरण भी केवल आयातित वस्तुओं की खपत को दिखाता है जो वास्तविक आवश्यकता से कम थे। सभी एसबी में, आवेदन में आवेदित कुल मात्रा का उल्लेख किया गया था और न कि निर्यात मात्रा में खपत की गई वास्तविक मात्रा को । इसलिए एसबी को सामान्य टिप्पणी और उक्त पॉलिसी सर्कुलर के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। जवाबदेही विवरण में उपयोग की गई इनपुट की मात्रा फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्यातवार आयात विवरणों से मेल नहीं खाती हैं। इसके अलावा, निर्यात पर ₹ 6.05 करोड़ के भुगतान किए गए आईजीएसटी के प्रतिदाय का दावा किया गया है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के बराबर है। इसलिए सभी घटकों (आयातित और घरेलू दोनों) के सीआईएफ/एफओआर मूल्य को केवल आयातित घटकों के बजाय वीए

का अनुमान लगाने के लिए लिया जाना चाहिए था। यदि निर्यात में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद सभी घटकों के सीआईएफ/फ्रेट ऑन रोड (एफओआर) मूल्य को लिया गया होता तो वास्तव में निकाला गया वीए निर्धारित 15 प्रतिशत से काफी कम रहा होता।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ऐसा कोई अधिदेश नहीं है कि फर्म को उत्पाद के विनिर्माण में आवश्यक सभी घटकों का आयात करना होता है। तथापि, आयातित मदों के संदर्भ में उपभोग का ब्यौरा जवाबदेही के लिए प्रस्तुत किया जाना है और वीए के लिए शुल्क भुगतान किए गए इनपुट पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जिस पर कोई ड्राबैक नहीं लिया गया।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जवाबदेही विवरण में केवल आयातित इनपुट का अनुमान है और इसमें घरेलू अधिप्राप्ति का हिसाब में लेने का प्रावधान नहीं है। आरए परिशिष्ट 4एच/4ई के तहत यथापेक्षित निर्यातित मदों के विनिर्माण में वास्तव में उपभोग किए गए सभी इनपुट की घोषणा के लिए जोर नहीं देते हैं।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि केवल आयातित इनपुट के सीआईएफ मूल्य पर विचार करने की प्रथा मूल्य वर्धन की पूरी स्थिति नहीं दर्शाती है। घरेलू आपूर्ति के मूल्य को शामिल न करना, जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी की राशि पर गलत विचार करना और एएच द्वारा वास्तविक आयात की घोषणा न करना लेखापरीक्षा में देखा गया जो शुल्क मुक्त आयातों के विपथन के जोखिम के साथ-साथ योजना के दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ है। आरए गैर-घोषित माल के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है और गलत तरीके से प्राप्त छूट को अननुमत करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

सिफारिश संख्या 12 :डीजीएफटी परिशिष्ट 4एच में पूर्ण प्रकटीकरण के लिए जोर दे सकता है जिसमें एएच को "घरेलू अधिप्राप्ति इनपुट और ऐसी अधिप्राप्ति के स्रोत सहित निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में उपभोग की जाने वाली इनपुट के सभी विवरण" की घोषणा करने की आवश्यकता होती है, ताकि आरए द्वारा वास्तविक खपत की बेहतर निगरानी को सुगम बनाया जा सके जिससे शुल्क मुक्त आयात के विपथन और योजना के दुरुपयोग को रोका जा सके।

3.2.3.4 सहयोगी संस्था को आपूर्ति पर नकारात्मक वीए

आरए मुंबई द्वारा मैसर्स एएन लिमिटेड को जारी किए गए तीन लाइसेंसों में यह देखा गया कि एएच ने अपनी सहयोगी इकाई, एक निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) को खरीद मूल्य से कम कीमत पर तैयार माल का निर्यात करके नकारात्मक वीए प्राप्त किया। चूंकि ईओयू इकाई निर्यातक की सहयोगी संस्था है, इसलिए खरीद मूल्य से कम होने पर आपूर्ति के मूल्य को आर्मस लैंथ पर नहीं माना जा सकता है। इस कमी को निर्धारित न्यूनतम वीए के मुकाबले कम होने वाले मूल्य पर ₹ 9.51 लाख की राशि की 1 प्रतिशत दंड राशि का भुगतान करके नियमित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, खरीद मूल्य से कम कीमत पर सहयोगी संस्था को इनपुट को विपथित करने की प्रथा से नकारात्मक वीए को जानबूझकर दर्शाया गया था न कि यह वास्तविक चूक थी जिसे केवल 1 प्रतिशत दंड राशि का भुगतान करके नियमित किया जा सकता है। लेखापरीक्षा की राय में निर्यातकों को योजना के तहत शुल्क बचाने के लाभ को चुकाने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए और योजना के जानबूझकर दुरुपयोग के लिए एफटीडीआर एक्ट के तहत दंड राशि लगायी जानी चाहिए।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि डीटीए और ईओयू के ईओ को अलग से माना जाना है क्योंकि दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं और ईओ की अलग-अलग योजनाएं हैं और दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। फर्म से एफओबी मूल्य में 1 प्रतिशत कमी की वसूली करके आरए मुंबई द्वारा नकारात्मक मूल्य वर्धन को नियमित किया गया।

3.2.4 स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात प्राप्तियों की वसूली न करना

एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.21 (iii) के संदर्भ में, ईओ के निर्वहन के लिए विशेष आर्थिक ज़ोन (सेज) इकाइयों के निर्यात को ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते भुगतान प्राप्ति सेज इकाई के विदेशी मुद्रा खाते (एफसीए) में हो।

एफसीए में निर्यात प्राप्तियों की वसूली का न होना 84 उदाहरणों में देखा गया जिसमें पांच आरए में ₹ 3.38 करोड़ की राशि का परित्यक्त शुल्क शामिल था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.9: एफसीए में निर्यात प्राप्तियों की वसूली न होना

क्र.सं.	आरए का नाम	मामलों की संख्या	परित्यक्त शुल्क (₹ लाख में)	टिप्पणियां
1	चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम	9	259.26	सेज इकाइयों को किए गए निर्यात को निर्यात दायित्व के प्रति मूल्य वर्धन के लिए गिना गया था, भले ही निर्यात प्राप्तियों की आईएनआर में वसूली की गयी और न कि एफसीए में
2	अहमदाबाद	13	79.15	6 एए में सेज और बीआरसी को किया गया निर्यात आईएनआर में हुआ। 3 एसबी में निर्यात प्राप्तियों की वसूली नहीं हुई और 4 एसबी में कोई ई-बीआरसी फाइल में या डीजीएफटी की वेबसाइट के ई-बीआरसी मॉड्यूल में उपलब्ध नहीं था।
3	पुणे	62	-	एसबी वीए के लिए गणना की गई भले ही निर्यात प्राप्तियों की गणना आईएनआर में थी।
कुल		**84**	**338.41**	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आईएनआर में प्राप्त भुगतान ईओ पूर्ति के लिए नहीं लिया जा सकता है और कमी की वसूली करने का आश्वासन दिया। आरए मुंबई को निर्देश दिया गया है कि जब तक वसूली प्रभावी न हो जाए तब तक फर्म को डीईएल में रखा जाए। आरए अहमदाबाद, चेन्नई और पुणे के संबंध में मामले की जांच की जा रही है।

3.2.5 मोचन प्रमाण पत्र/ईओडीसी के लिए एएच द्वारा आवेदन दाखिल करना

3.2.5.1 ऑनलाइन फाइलिंग का अभाव और ईओडीसी का निपटान

एचबीपी के पैरा 4.46 में कहा गया है कि एएच एएनएफ-4एफ में ऑनलाइन आवेदन आरए को दाखिल करेगा और मोचन प्रमाण पत्र/ईओडीसी के लिए ईओ की पूर्ति के समर्थन में निर्धारित दस्तावेज अपलोड करेगा। डीजीएफटी ने पीएन 55 (मार्च 2014) के द्वारा 1 जून 2014 से प्रभावी एए के लिए इओडीसी/मोचन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की।

हालांकि यह देखा गया कि एएच 1 दिसंबर 2020 तक मोचन/ईओडीसी के लिए आवेदन अभी भी मैनुअल रूप से दाखिल कर रहे थे, जबकि ऑनलाइन आवेदन

लिंक सक्रिय हो गया था। इस प्रकार, मोचन/ईओडीसी के लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी जारी करने में देरी हुई और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। ऑनलाइन आवेदन कार्यात्मकता की प्रभावकारिता की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

3.2.5.2 एएच द्वारा ईओडीसी आवेदन जमा करने में विलम्ब

एचबीपी के पैरा 4.44 में यह उल्लेखित है कि एएच को देयता अवधि समाप्त होने की तिथि से दो माह के भीतर निर्यात के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

11 आरए (बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, लुधियाना, पानीपत और विशाखापत्तनम) में ईओपी की समाप्ति से दो माह से अधिक की देरी 193 एए में देखी गई थी जिसमें 5 से 792 दिन तक की देरी हुई थी और आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी **(अनुलग्नक 6)**।

एक मामला सोदाहरण दिया गया है जिसमें मैसर्स एओ को आरए बेंगलुरु द्वारा एए जारी किया गया था (मई 2015) और ईओडीसी/मोचन के लिए प्रस्तुत करने की नियत तिथि जनवरी 2017 तक थी। हालांकि यह देखा गया कि एएच ने 32 माह की देरी के साथ केवल अगस्त 2019 में मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

आरए चेन्नई, हैदराबाद और इंदौर ने बताया (नवंबर 2020) कि सावधानी पत्र जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि योजना 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी नई आईटी प्रणाली के साथ कागजरहित हो गई है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, कमियों और उनके उत्तरों को ऑनलाइन निपटाया जाएगा और डेटा मूल रूप से सीमा शुल्क को हस्तांतरित किया जाएगा जो ईओडीसी को अंतिम रूप देने की निगरानी में मदद करेगा।

इस संबंध में प्रगति को आगामी लेखापरीक्षा में देखा जाएगा।

3.2.6 आरए द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र जारी करने के दौरान अनियमितताएं

3.2.6.1 आरए द्वारा ईओडीसी जारी करने में देरी

एचबीपी 2015-20 के पैरा 9.10 में यह निर्धारित किया गया है कि एए का आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर मोचन किया जाना है। एमओसीआई ट्रेड नोटिस नंबर 20 (जून 2019) में दोहराया गया कि सभी आरए को समयबद्ध तरीके से और केवल एक ही बार में कमी पत्र (डीएल) देना चाहिए।

17 आरए (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोयंबटूर, कटक, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, पानीपत, पुणे, वडोदरा और विशाखापट्टनम) में समीक्षा किए गए 2,242 मामलों में से 546 मामलों (24 प्रतिशत) में 18 से 1,001 दिनों की देरी के साथ ईओडीसी के जारी करने में विलम्ब देखा गया। अहमदाबाद और वडोदरा में 16 मामलों में, 15 दिनों से अधिक की देरी देखी गई, हालांकि एएच ने आरए द्वारा चिह्नित सभी कमियों का अनुपालन किया। प्रमुख नौ आरए का विश्लेषण ग्राफ में नीचे दिया गया है:

चित्र 3.1: ईओडीसी के जारी करने में विलम्ब

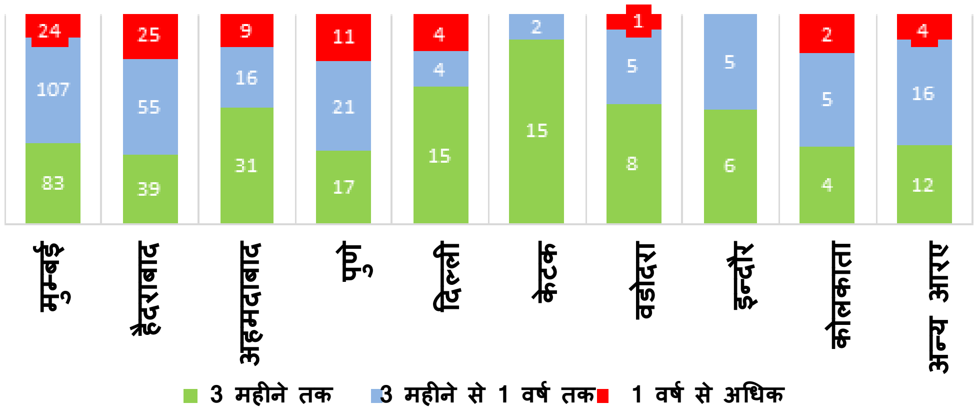

एक मामला सोदाहरण दिया गया है जिसमें आरए बेंगलुरु ने मैसर्स एओ लिमिटेड को एए जारी किया (जनवरी 2018) और एएच द्वारा आवेदित लागू ईओडीसी (अप्रैल 2019) में एक बार में सभी डीएल जारी न होने के कारण पांच माह से अधिक की देरी हो गई। ईओडीसी को आखिरकार अक्टूबर 2019 में जारी किया गया। यदि प्रारंभिक पूर्व संवीक्षा (अप्रैल 2019) के दौरान सभी कमियों को बताया गया होता और एए की निर्धारित समय-सीमा का फर्म और

आरए दोनों द्वारा पालन किया जाता, तो ईओडीसी के जारी करने में पांच माह से अधिक की अनुचित देरी से बचा जा सकता था।

मोचन/ईओडीसी आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी जारी करने में देरी हुई और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। हालांकि मोचन आवेदन ऑनलाइन फाईल किए गए थे, लेकिन बीई, एसबी, ई-बीआरसी, इनपुट और एक्सपोर्ट खपत और सर्टिफिकेट जैसे सभी दस्तावेजों को 2015-16 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मैनुअल रूप से फाईल करना जरूरी था। मोचन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण और लाइसेंस डेटा के साथ इसके एकीकरण से देरी को कम करने और मोचन आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित 15 दिनों के बेंचमार्क को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि इस मुद्दे को सुलझाने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी नई आईटी प्रणाली से ईओडीसी के मुद्दे में देरी के मुद्दे को हल करने की उम्मीद है; तब तक ईओडीसी आवेदनों की केवल हार्ड कॉपी मिलने के बाद ही फाईलों पर कार्रवाई की गई।

सिफारिश संख्या 13: डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करके 15 दिनों की अपनी निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए ईओडीसी जारी करने की क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए कि ऑनलाइन मॉड्यूल को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूर्ण और मुकम्मल आवेदनों को स्वीकार करने के लिए फिर से बनाया गया है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि eodc.online 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी नई आईटी प्रणाली के साथ कार्य कर रहा है।

लेखापरीक्षा के दौरान शामिल की गई अवधि 2015-16 से 2018-19 तक थी; इसलिए, इस संबंध में कार्यान्वयन और प्रगति की स्थिति की समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

3.2.6.2 आरए द्वारा अनियमित मोचन

आरए मुंबई ने दो फर्मों (मैसर्स एएन लिमिटेड और मैसर्स एच लिमिटेड) को जारी किए गए तीन एए का मोचन किया, भले ही ईओ को पूरी तरह से मानित निर्यात द्वारा प्राप्त किया गया था। आईजीएसटी छूट का लाभ केवल प्रत्यक्ष

निर्यात और एएच के लिए है, सीमा शुल्क द्वारा आईजीएसटी के उद्ग्रहण से बचने के लिए, घोषणा की कि केवल प्रत्यक्ष निर्यात किया जाएगा। हालांकि, आरए ने गलत घोषणा के आधार पर ₹ 32.80 लाख की आईजीएसटी के अनियमित लाभ के तथ्यों का पता लगाए बिना मामलों का मोचन करते हुए ईओ के प्रति मानित निर्यात को स्वीकार किया, जिसकी ब्याज के साथ वसूली करने की आवश्यकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि आरए को निर्देश दिया गया है कि वसूली होने तक फर्मों को डीईएल में रखा जाए।

3.2.6.3 ईओपी के बाद किया गया निर्यात

एचबीपी के पैराग्राफ 2.18 (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि प्राधिकार की निर्यात दायित्व अवधि निर्यात की तारीख को वैध होनी चाहिए। निर्यातक को निर्यात को प्रभावित करने से पहले ईओपी में विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए था। इसलिए, बिना किसी विस्तार के प्रभावित निर्यात को आनुपातिक अधिक आयातों पर शुल्क/ब्याज एकत्र करके पैराग्राफ 4.49 के अनुसार अननुमत और नियमित किए जाने की आवश्यकता थी।

ईओडीसी की समीक्षा से पता चला कि छह आरए में 11 एए में एए योजना के तहत अनुमत ईओ अवधि के बाद प्रभावी थे, जो ₹ 8.42 करोड़ के आनुपातिक शुल्क के साथ थे जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.10: ईओपी के बाद किए गए निर्यात

क्र.सं.	आरए का नाम	एए की संख्या	परित्यक्त आनुपातिक शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
1	वडोदरा	3	6.19	137 एसबी में से पांच और दो अन्य एए में निर्धारित ईओ अवधि के बाद निर्यात प्रभावित हुए और एएच द्वारा किसी विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात (मात्रावार और मूल्यवार) की कम पूर्ति हुई। इसके अलावा वीए में कमी के लिए 1 प्रतिशत फीस भी लागू है।
2	अहमदाबाद	2	1.29	एएच ने ईओपी की वैधता के बाद निर्यात को प्रभावित किया और बाद में कार्योत्तर विस्तार के

क्र.सं.	आरए का नाम	एए की संख्या	परित्यक्त आनुपातिक शुल्क (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
				लिए आवेदन किया जिसे आरए द्वारा प्रदान किया गया था। इस प्रकार, मध्यवर्ती अवधि के दौरान ईओ अवधि में किसी विस्तार की मांग किए बिना, निर्यातकों ने अपना निर्यात जारी रखा।
3	कोलकता	2	0.50	ईओपी के बाद प्रभावित आयात छूट के लिए पात्र नहीं थे।
4	जयपुर	1	0.41	आरए ने ईओ अवधि में कार्योत्तर विस्तार प्रदान किया, जो ईओपी के बाद प्रभावित अवैध निर्यातों को अस्वीकार करने के बजाय था।
5	पुणे	1	0.03	अपात्र निर्यात के लिए अधिक आयात का उपयोग किया गया। इसके अलावा, मानित निर्यात दस्तावेजों में प्रत्येक परेषण के लिए आनुपातिक इनपुट खपत को प्रतिबिंबित नहीं किया गया था और प्रावधानों के तहत यथा अपेक्षित एक सहायक विनिर्माता के माध्यम से निर्यात के तथ्य का एए में समर्थन नहीं किया गया था।
6	बेंगलुरु	2	-	निर्धारित ईओ अवधि के बाद किए गए ₹ 2.49 करोड़ मूल्य वाले निर्यात।
कुल		**11**	**8.42**	

डीजीएफटी ने कहा कि आरए बेंगलुरु ने ₹ 0.70 लाख की वसूली की और ₹ 0.55 लाख की संयोजन फीस की वसूली करने के लिए मांग जारी की। आरए पुणे द्वारा फर्म के विरुद्ध मांग-सह-एससीएन भी जारी किया गया था। आरए जयपुर में, ईओपी को पहले ही अप्रैल 2019 तक बढ़ा दिया गया है और फर्म ने उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्यात को भी प्रभावित किया है। आरए अहमदाबाद के लिए यह कहा गया था कि एचबीपी का पैरा 4.27 निर्यात/मानित निर्यात की आपूर्तियों की अनुमति प्राधिकार जारी करने की प्रत्याशा में या प्राधिकार जारी करने के बाद देता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्यातकों द्वारा निर्यात पूरा होने के बाद ईओ अवधि में कार्योत्तर विस्तार प्रदान करने के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई प्रावधान नहीं है और एचबीपी के पैराग्राफ 2.18 के अनुसार, निर्यात की तारीख को प्राधिकार वैद्ध होना चाहिए। इसके अलावा निर्यातक को निर्यातों को प्रभावित करने से पहले ईओपी के विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए था।

3.2.6.4 लदान बीजक में इनपुट का अंकन न करना

एफटीपी के पैरा 4.12 (ii) से (iv) के अनुसार, निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तव में उपयोग किए गए/उपभोग किए गए इनपुट का अनुपात एसबी में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा जिसमें मानित निर्यात के प्रति बीजक शामिल हैं और आरए केवल उन्हीं इनपुट की अनुमति देगा जो निर्यात दायित्व के निर्वहन के समय विशेष रूप से एसबी में दर्शाए गए हैं।

निम्नलिखित मामलों में, आरए ने एसबी में अंकन के बिना ईओडीसी जारी किया:

तालिका 3.11: एसबी में इनपुट का अंकन न करना

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>आरए का नाम</th><th>एए की संख्या</th><th>टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कोच्चि</td><td>1</td><td>मैसर्स एल लिमिटेड को जारी किया गया, ईओडीसी यद्यपि एएच ने निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तव उपयोग किए गए/उपभोग किए गए इनपुट का संकेत नहीं दिया था, जिसमें एफओबी मूल्य ₹ 11.83 करोड़ शामिल था।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अहमदाबाद</td><td>2</td><td>मैसर्स एपी लिमिटेड को एक एए में ईओडीसी जारी किया गया और अन्य के लिए विस्तार से मना कर दिया, यद्यपि 26 बीई में एसआईओएन/प्राधिकार के अंतर्गत यथा अपेक्षित आयातित इनपुट के बारे में अधूरी सूचना पाई गई थी। हालांकि, आरए द्वारा इस बेमेलता को सत्यापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसमें ₹ 20.69 करोड़ का परित्यक्त शुल्क शामिल है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चेन्नई</td><td>3</td><td rowspan="2">मैसर्स एक्यू लिमिटेड और मैसर्स एआर लिमिटेड को जारी किए गए पांच एए में ईओडीसी जारी किया गया, हालांकि एएच ने एए में समर्थित की तुलना में भिन्न इनपुट का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप गलत आयात हुआ जिसमें ₹ 3.62 करोड़ का सीमा शुल्क अन्तर्ग्रस्त था।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कोयम्बटूर</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

डीजीएफटी ने आरए चेन्नई, कोयंबटूर और कोच्चि के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि कार्रवाई शुरू की जा रही है। आरए अहमदाबाद ने कहा कि इस योजना के तहत मंजूरी दिए गए बीई में विशिष्ट प्राधिकार संख्या दी जाती है और अनुमत आयात के समय अनुमत विवरण मात्रा, मूल्य आदि के संबंध में प्राधिकार की सीमा शुल्क जांच करता है। सीए द्वारा जारी परिशिष्ट 4एच भी किए गए निर्यात और उपयोग किए गए इनपुट की पुष्टि करता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एसबी में इनपुट के समर्थन की जांच इओडीसी/मोचन जारी करने के दौरान आरए द्वारा की जानी होती है जो प्रक्रिया का अंतिम चरण है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि योजना के तहत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्य के लिए किया गया है।

3.2.6.5 उचित अंकन/संशोधन के बिना ईओडीसी/मोचन पत्र जारी करना

एचबीपी के पैरा 4.39 के अनुसार, आरए सीआईएफ मूल्य, इनपुट की मात्रा, एफओबी मूल्य और एए के निर्यात की मात्रा में वृद्धि/कमी के लिए फार्म एएनएफ-4 डी में अनुरोध पर विचार कर सकता है। हालांकि, इस तरह की वृद्धि के बाद मूल्य वर्धन अनुबद्ध एमवीए (निर्यात उत्पाद के लिए) से कम नहीं होना चाहिए और इनपुट-आउटपुट मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

आरए हैदराबाद में, प्राधिकार प्रदान करने के समय निर्धारित सीआईएफ और एफओबी मूल्यों की तुलना में कम सीआईएफ/एफओबी मूल्यों के साथ 43 एए का मोचन किया गया था। इन सभी मामलों में, एएच को सीआईएफ या एफओबी मूल्य में कमी हेतु संशोधन के लिए किसी भी अनुरोध के बिना मोचन की अनुमति दी गई थी। एए का यह कहते हुए मोचन किया गया कि किए गए आयात किए गए निर्यातों के प्रति उसी अनुपात (सीआईएफ और एफओबी के समान) में थे और कि एए के अनुसार अपेक्षित मूल्य वर्धन प्राप्त किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि उपयोग और 15 प्रतिशत वीए के अनुसार लाइसेंस का मोचन किया गया था।

डीजीएफटी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एएच द्वारा सीआईएफ या एफओबी मूल्य में कमी हेतु संशोधन के लिए किसी अनुरोध के बिना मोचन की अनुमति दी गई थी।

3.2.6.6 मसाला बोर्ड द्वारा एसएआर की प्राप्ति न होने के कारण ईओडीसी जारी करने में देरी

नीति परिपत्र 5 (अगस्त 2014) के अनुसार, मसालों के लिए इनपुट के रूप में जारी एए को मामले को एनसी को संदर्भित किए बिना मसाला बोर्ड, कोच्चि को प्रस्तुत किया जाएगा और संबंधित आरए, मसाला बोर्ड, कोच्चि के एसएआर के

आधार पर एए का मोचन कर सकता है। यह नीति परिपत्र सभी लंबित मामलों के साथ-साथ भविष्य के एए के संबंध में अगस्त 2013 से लागू किया गया था।

आरए कोच्चि में, ₹ 1596.60 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले 100 एए मसालों से संबंधित थे जो 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जारी किए गए ₹ 2145.74 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले कुल लंबित 271 एए में से हैं। मसालों से संबंधित चयनित 22 एए की संवीक्षा से मसाला बोर्ड से एसएआर प्राप्त न होने के कारण सभी मामलों में ईओडीसी जारी करने में विलंब का पता चला।

डीजीएफटी ने कहा (नवंबर 2020) कि नीति परिपत्र के पैरा 2 के अनुसार, संबंधित आरए मसाला बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एसएआर के आधार पर एए का मोचन कर सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरए द्वारा एसएआर को इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि क्या ईओडीसी दावे के अनुसार घोषित आय एसएआर के अनुसार आय से अधिक है। यह देखा गया कि 22 में से 18 मामलों में, ईओडीसी आवेदनों के अनुसार आय एसएआर के अनुसार आय से अधिक थी, जैसाकि सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित एएच द्वारा फाईल किए गए परिशिष्ट 4एच से स्पष्ट था। इस प्रकार, आरए के लिए ईओडीसी को जारी करने में देरी करने का कोई कारण नहीं था जब अधिकांश मामलों में, एएनएफ 4एफ आवेदन के अनुसार घोषित आय अधिक पाई गई थी। इस प्रकार, उक्त नीति परिपत्र के मद्देनजर एसएआर की प्राप्ति में देरी के कारण ₹ 453.01 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ 22 एए के मोचन में विलम्ब परिहार्य था और उक्त परिपत्र जारी करने का असली उद्देश्य विफल हो गया, अर्थात मसालों के लिए जारी प्राधिकारों के मोचन में विलम्ब में कमी।

3.2.7 अन्य अनियमितताएं

3.2.7.1 प्राधिकार में उचित अंकन के बिना मदों का निर्यात और डीएल जारी करने में देरी

एचबीपी के पैरा 4.35 में कहा गया है कि आरए द्वारा प्राधिकार में उचित अंकन के साथ एचबीपी के पैराग्राफ 4.10 या जॉबर/सहायक विनिर्माता की शर्त के अधीन एएच की किसी भी इकाई में आयातित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

मैसर्स एएस लिमिटेड ने एए के लिए आवेदन करते समय कहा कि कुछ निर्यात उत्पादों का विनिर्माण सेज, कोचीन में स्थित उनके सहायक विनिर्माता द्वारा किया जाएगा। आरए बेंगलुरु ने सहायक विनिर्माता के संबंध में दो डीएल जारी किए, जिसमें एएच ने सहायक विनिर्माता का नाम हटाने का अनुरोध किया। तदनुसार, आरए ने किसी भी सहायक विनिर्माता अंकन किए बिना एए जारी किया।

फर्म ने ईओडीसी के लिए आवेदन किया (दिसंबर 2018), जिस पर आरए ने डीएल (मार्च 2019) जारी किया कि निर्यात की गई मद एससीओएमईटी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली प्रतीत होती है और यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या एससीओएमईटी मद के निर्यात के लिए आवश्यक अनुमति डीजीएफटी से ली गई थी। डीजीएफटी ने यह भी सूचित किया कि संदर्भ के तहत मद एससीओएमईटी श्रेणी 8ए602 के तहत आ सकती है, और डीजीएफटी से प्राधिकार के माध्यम से निर्यात किया जाएगा। इसके अलावा, यह देखा गया कि एएच ने उक्त नियमों के तहत यथा अपेक्षित किसी भी अंकन के बिना अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) इकाई (सहायक विनिर्माता) के माध्यम से ₹ 19.64 करोड़ का निर्यात किया। मामले को अभी मोचन किया जाना है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि सेज नियमावली 2006 के नियम 43 के तहत उप-अनुबंध की अनुमति के लिए फर्म ने डीसी, सीसेज से संपर्क किया है।

उत्तर में इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या डीजीएफटी से प्राधिकार एससीओएमईटी श्रेणी के निर्यात को प्रभावित करने के लिए प्रदान किया गया था। आरए को यह पता लगाने में 14 माह लगे कि क्या निर्यात मद प्रतिबंधित श्रेणी के अन्तर्गत आती है जिसे एए जारी करते समय (फरवरी 2018) सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, सेज प्रावधानों के तहत उप-अनुबंध की अनुमति आरए द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद कार्योत्तर ली गयी थी और इसलिए अपेक्षित अंकन के बिना पहले से किए गए निर्यात को अननुमत किया जाना चाहिए था और फर्म को निर्यात उत्पाद में उपयोग किए गए इनपुट पर परित्यक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए था।

अन्य उदाहरणों, जहां आरए ने एए में उचित समर्थन के बिना निर्यात की अनुमति दी, का विवरण यहां नीचे दिया गया है:

तालिका 3.12: प्राधिकार में गैर-समर्थन

क्र.सं.	आरए का नाम	मामलों की संख्या	टिप्पणियां
1	कोलकाता	7	एएच द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद प्राधिकार में अनुमत किए गए से अलग थे। आरए ने निर्यात उत्पादों में बेमेल का सत्यापन नहीं किया और निर्यात परेषण की पूरी मात्रा के लिए बीडब्ल्यूसी[12] जारी किया। तीन मामलों में, एएच ने घोषणा की कि सेनवेट क्रेडिट की सुविधा ली गई थी और इनपुट की घरेलू अधिप्राप्ति की अनुमति देते हुए बीडब्ल्यूसी जारी करने के बाद आरए द्वारा अवैधीकरण पत्र भी जारी किए गए थे।
2	अहमदाबाद	10	2 एए में एएच द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद प्राधिकार में अनुमत किए गए उत्पादों से भिन्न थे जिसके परिणामस्वरूप आरए द्वारा निर्यात पर गलत विचार किया गया था, जिसमें ₹ 83.93 लाख का परित्यक्त शुल्क था जिसकी वसूली करने की आवश्यकता है। अन्य आठ एए में सीए सर्टिफिकेट में इस बात का उल्लेख नहीं था कि सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया है या नहीं। यह भी प्रमाणित किया गया कि निर्यात के बाद आयातित माल का उपयोग शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए किया जाएगा। एक मामले में, सीए ने सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने के साथ-साथ लाभ न उठाने दोनों को प्रमाणित किया। आरए ने सीए प्रमाणपत्रों और माल के विपथन की संभावना का विधिवत सत्यापन किए बिना सभी आठ एए में ईओडीसी जारी किया और निर्यात पूरा होने या दोहरे लाभ का फायदा उठाने के बाद इसके आयात के कारण से इनकार नहीं किया जा सकता।
	कुल	17	

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि मामले की जांच की जा रही है। आरए अहमदाबाद में दो फर्मों के संबंध में निर्यात किए गए उत्पाद का नाम और विवरण एए के साथ मेल खाते थे।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि निर्यातित उत्पाद (क्लोरपाइरिफॉस तकनीकी 48 प्रतिशत मिन और 'आईटीसी 63051200 के तहत गैर-बुना हुआ कपड़ा') एए में समर्थित उत्पाद (क्लोरपाइरिफॉस तकनीकी 94 प्रतिशत और

---

[12] बीडब्ल्यूसी बांड छूट प्रमाण-पत्र होता है। जब किसी एएच ने पहले निर्यात किया हो, तब बांड छूट जारी की जाती है क्योंकि उसने पहले ही शर्तों का अनुपालन किया है। परित्यक्त शुल्क की सुरक्षित रखने के लिए बांड लिया जाता है और निर्यात बाध्यता को पूरा न करने की स्थिति में बीजी को निरस्त किया जाता है। जब एएच ने पहले ही निर्यात किया हो, तब बांड अर्थहीन हो जाता है और इसलिए बांड-छूट जारी की जाती है।

आईटीसी एचएस कोड 56031200 के तहत मानव निर्मित फाइबर (पॉलीप्रोपाइलीन) से बने गैर-बुने हुए कपड़े') के साथ मेल नहीं खाता था।

3.2.7.2 ई-बीआरसी के साथ निर्यात लदान बिल/बीजक को लिंक न करना

एचबीपी 2015-2020 के पैरा 4.44 (ई) में यह निर्धारित किया गया है कि ई-बीआरसी को ईओ/वसूली की समाप्ति की तारीख या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए निर्धारित समय अवधि से छह माह के अन्दर एसबी के साथ लिंक किया जाएगा।

आरए कोच्चि में मैसर्स एटी लिमिटेड को जारी एए (नवंबर 2015) में यह देखा गया कि केवल ईओडीसी जारी होने के बाद ही डीजीएफटी सिस्टम में एसबी के लिए ई-बीआरसी अपलोड की गई थी। ई-बीआरसी प्रस्तुत न करने के लिए आरए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और यह सत्यापित और सुनिश्चित किए बिना ईओडीसी जारी किया गया कि निर्यात प्राप्तियों की वास्तव में वसूली की गई थी।

आरए (कानपुर और पटना) में यह देखा गया कि विमाचेन किए गए सभी 42 मामलों में कोई भी ई-बीआरसी एसबी के साथ लिंक नहीं किया गया। एसबी को एएच द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया था (**अनुलग्नक 7**)।

डीजीएफटी ने आरए कोच्चि के संबंध में कहा था (फरवरी 2021) कि फर्म को मांग नोटिस जारी किया गया है और अन्य आरए से उत्तर प्रतीक्षित है।

3.2.7.3 अवैधीकरण/पुनर्वैधीकरण पत्र जारी करने में देरी

एचबीपी के पैरा 9.10 (xi) के साथ पठित एफटीपी के पैरा 4.20 में एएच से आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों की अवधि के भीतर अग्रिम रिलीज आदेश (एआरओ) या अवैधीकरण पत्र के प्रति सीधे आयात के बदले देशी आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट अधिप्राप्त करने की अनुमति दी गयी है। एचबीपी के पैरा 9.10 (vi) के अनुसार, आरए एएच से आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों की अवधि के भीतर ईओपी के प्राधिकार या विस्तार का पुनर्वैधीकरण जारी करेगा।

आरए हैदराबाद में अवैधीकरण पत्र जारी करने में 12 मामलों में तीन दिन से 221 दिन तक की देरी देखी गई। इसी प्रकार, आरए हैदराबाद और विशाखापत्तनम में 29 मामलों में ईओपी के पुनर्वैधीकरण या विस्तार के लिए पत्र जारी करने में तीन से 72 दिनों की देरी देखी गयी।

डीजीएफटी ने आरए हैदराबाद के संबंध में श्रमबल की कमी को विलम्ब का कारण बताया (फरवरी, 2021)।

3.2.7.4 ईओपी के विस्तार के लिए संयोजन फीस का कम संग्रहण होना/संग्रहण न होना

ईओ में कमी के 0.5 प्रतिशत की संयोजन फीस के भुगतान के अधीन ईओपी का विस्तार प्रदान किया जा सकता है।

सीएलए दिल्ली और आरए जयपुर, कानपुर और कोलकाता में सात मामलों में ₹ 26.07 लाख की संयोजन फीस का कम संग्रहण होना/संग्रहण न होना देखा गया।

सीएलए दिल्ली और आरए जयपुर ने ₹ 3.60 लाख की वसूली सूचित की।

3.2.7.5 अस्वीकार्य ड्राबैक का दावा

एफटीपी 2015-20 के पैरा 4.15 में यह निर्धारित किया गया है कि निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त शुल्क प्रदत्त आयातित या घरेलू इनपुट (मानदंडों में निर्दिष्ट नहीं) के लिए ड्राबैक उपलब्ध होगा, बशर्ते कि आवेदक एए के लिए आवेदन में शुल्क प्रदत्त इनपुट के विवरण को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा।

आरए कोयंबटूर में मैसर्स एयू लिमिटेड के ईओडीसी आवेदन की समीक्षा से पता चला है कि एएच ने निर्यात के प्रमाण के प्रति प्रस्तुत सभी 95 एसबी में ड्राबैक और अग्रिम लाइसेंस दोनों का दावा किया। यह एचबीपी के पैरा 4.29 के प्रावधानों के उल्लंघन में है और इसलिए इन एसबी को ईओ के उद्देश्य से अपात्र के रूप में माना जाना था। एए का सीआईएफ मूल्य ₹ 8.10 करोड़ था, जिसमें परित्यक्त शुल्क ₹ 1.34 करोड़ शामिल था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि एएच गैर-कपड़े मदों के लिए ड्राबैक की सभी उद्योग दर के लिए पात्र है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एएच ने एसबी के अनुसार कपड़े की मदों के लिए ड्राबैक का दावा किया था, और इसलिए इन एसबी को मूल्य वर्धन के लिए अयोग्य माना जाना है।

3.3 योजना के क्रियान्वयन में अंतरविभागीय समन्वय

3.3.1 ऑनलाइन एमईएम का कार्यान्वयन न होना

एचबीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.47 (बी) के अनुसार, ईओडीसी/मोचन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, आरए ईओडीसी की प्रति प्राधिकार के पंजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अग्रेषित करेगा, जिसमें ईओ की पूर्ति के प्रमाण के विवरण दर्शाए गए हों। डीजीएफटी और सीबीआईसी के बीच एमईएम के तहत ईडीआई के माध्यम से इन्हें संचारित करने की प्रणाली शुरू होने तक आरए द्वारा सीमा शुल्क को भी ईओडीसी की प्रति पृष्ठांकित की जाएगी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आरए जयपुर, कोलकाता पत्तन और एसीसी हैदराबाद में एमईएम कार्यान्वित नहीं हुआ था। आरए कोलकाता, अहमदाबाद और वडोदरा ने सूचना के आदान-प्रदान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मॉड्यूल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऑनलाइन एमईएम के अभाव में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचना का आदान-प्रदान पर्याप्त नहीं था और निम्नलिखित देखा गया:

तालिका 3.13: ऑनलाइन एमईएम का कार्यान्वयन न होना

क्र.सं.	पत्तन का नाम	कुल	स्थिति
1	कोलकाता समुद्री सीमाशुल्क	273	डीजीएफटी से ईओडीसी के प्राप्त न होने के कारण 273 एए दो साल से अधिक समय से निपटान के लिए लंबित थे।
2	आईसीडी बेंगलुरु	783	डीजीएफटी से ईओडीसी के सूचित न करने के 1070 मामले।
3	एनसीएच मंगलुरु	287	
4	आईसीडी हैदराबाद	20	12 एए में आरए द्वारा सीमा शुल्क को अवैधीकरण सूचित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में इनपुट की अधिप्राप्ति के साथ-साथ पंजीकरण के पत्तन से शुल्क मुक्त उसी इनपुट का आयात करते समय एएच द्वारा दोहरे लाभ का उपयोग किया जा सकता है। अन्य 8 एए में कोई इओडीसी प्राप्त नहीं हुआ।
5	एसीसी हैदराबाद	1	आरए को न दर्शाया गया ₹ 42.01 लाख का आयात
6	दिल्ली	2620	दिल्ली क्षेत्राधिकार (जनवरी 2020) के

क्र.सं.	पत्तन का नाम	कुल	स्थिति
			तहत सीमा शुल्क पत्तनों के मासिक प्रगति रजिस्टर (एमपीआर) के अनुसार, 2620 मामलों में ईओपी खत्म हो गया था। इन मामलों का धनमूल्य सीमा शुल्क से मांगा गया था, जो प्रतीक्षित है।
	कुल	3984	

एक प्रभावी ऑनलाइन संदेश विनिमय मॉड्यूल (एमईएम) के अभाव में, सीबीआईसी को अक्सर डीजीएफटी द्वारा दी गई ईओडीसी स्थिति का पता लगाने के लिए एएच पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तरह डीजीएफटी को उन मामलों के लिए शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनमें ईओ की अवधि खत्म हो गई है लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी डेटा को न भेजने/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ईओडीसी डेटा का उपयोग न करने से बांडों के निपटान में विलंब होता है और लम्बन में वृद्धि होती है। सोदाहरण मामलों में सरकारी राजस्व शामिल था; इसलिए एएच को आरए से मोचन पत्र प्राप्त करने और उन्हें सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके और अन्तर्निहित सरकारी राजस्व की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जा सके।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि एए सॉफ्टवेयर आरए को ऐसी पहुंच की अनुमति नहीं देता है। आरए द्वारा ईओ निगरानी पहले ही शुरू की जा चुकी है और नई आईटी प्रणाली से ईओडीसी में देरी के मुद्दे को हल करने की आशा है।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि लंबित प्राधिकारों के संबंध में सीमा शुल्क राजस्व की अधिकतम वसूली के लिए फरवरी-मार्च, 2020 में एक विशेष अभियान चलाया गया था। एमईएम के कार्यान्वयन पर, सीमा शुल्क द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव होगी, जहां ईओ समाप्त हो गई है।

इस संबंध में प्रगति आगामी लेखापरीक्षा में देखी जाएगी।

3.3.2 चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच बेमेलता

आसूचना का आदान-प्रदान करने, दुरुपयोग की जांच करने और ईओ पूर्ति स्थिति जैसे मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए आरए के साथ त्रैमासिक आधार

पर आवधिक बैठकों के लिए सीमा शुल्क और डीजीएफटी के बीच एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया था ताकि डीओआर निर्देशों (जनवरी 2011) के तहत चूककर्ताओं के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जा सके।

चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर डीजीएफटी के साथ सीमा शुल्क के डेटा के प्रति-सत्यापन से निम्नलिखित दो पत्तनों में 101 उदाहरणों में विसंगतियों का पता चला, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 3.14: चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई में डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच बेमेलता

क्र.सं.	**पत्तन का नाम**	**आरए का नाम**	**मामलों की संख्या**	**बेमेलता**
1	एसीसी मुंबई	मुंबई	15	एसीसी मुंबई ने वित्तीय वर्ष 2005 से वित्तीय वर्ष 2013 तक की अवधि से संबंधित 10 एए का अधिनिर्णय किया। हालांकि, आरए मुंबई के अनुसार, एए अभी भी एससीएन स्तर या पीएच स्तर पर लंबित हैं, और अभी तक अधिनिर्णय नहीं हुआ है और एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार कोई दंड राशि निर्धारित नहीं की गयी है। अन्य पांच एए में, एसीसी मुंबई ने निर्यातकों से ₹ 1.90 करोड़ की शुल्क की मांग करते हुए पांच मामलों का अधिनिर्णय किया। हालांकि, डीजीएफटी की ओर से, ऐसे अधिनिर्णय आदेशों की तारीख से 1.5 वर्ष से 7.5 वर्ष पूर्व इनका पहले ही मोचन किया गया था।
2	जेएनसीएच मुंबई		86	86 एए के संबंध में जेएनसीएच द्वारा जारी किए गए एससीएन अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं, जबकि इन लाइसेंसों का डीजीएफटी की ओर से पहले ही मोचन किया गया था।
	कुल		**101**	

सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई द्वारा मैसर्स एवी लिमिटेड के विरुद्ध ₹ 1.63 करोड़ के शुल्क की मांग करते हुए अधारणीय इकतरफा अधिनिर्णयन आदेश का एक मामला पारित किया गया था, हालांकि एएच ने एए का उपयोग नहीं किया था और सीमा शुल्क विभाग ने स्वयं सितंबर 2015 में एक गैर-उपयोगिता प्रमाण

पत्र जारी किया था, जिसके आधार पर डीजीएफटी कार्यालय ने अभ्यर्पण पत्र जारी किया था (नवंबर 2015)।

यह चूककर्ताओं के विरुद्ध सूचना के आदान-प्रदान और समन्वयित कार्रवाई में दो विभागों के बीच कमजोर संस्थागत तंत्र को इंगित करता है। या तो एससीएन जारी नहीं किए गए थे या पहले से जारी किए गए एससीएन को लंबित रखा गया था या आरए की ओर से इसकी तदनुरूपी स्थिति का पता लगाए बिना सीमा शुल्क की ओर से अधिनिर्णय किया गया था। इसके अलावा, डीजीएफटी द्वारा भेजे गए ईओडीसी आदेश प्रभावी रूप से सीमा शुल्क तक नहीं पहुंच रहे थे।

यह देखा गया है कि डीजीएफटी ने 'eodc.online' वेबसाइट लॉन्च की है (अप्रैल 2018) जिसमें सीमा शुल्क स्थिति की निगरानी कर सकता है क्योंकि डीजीएफटी निर्यातकों द्वारा फाईल किए गए मोचन आवेदनों पर कार्रवाई की प्रगति को अद्यतन करता है। इसका दो विभागों के बीच कार्रवाई की एकरूपता लाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता था।

डीओआर ने कहा (दिसंबर 2020) कि कई मामलों में डीजीएफटी द्वारा eodc.online वेबसाइट अद्यतन नहीं की गई। लाइसेंसधारी न तो मांग नोटिस का उत्तर देते हैं और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पेश होते हैं। सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर और समय देने के बाद भी ईओ की पूर्ति के मुद्दे पर एएच की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए विभाग अधिनिर्णयन के समय अग्रिम प्राधिकारों की वर्तमान स्थिति की जानकारी में असमर्थ है।

सिफारिश संख्या 14: डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचनाओं के प्रभावी और समय पर आदान-प्रदान के लिए डीजीएफटी को अपने सभी आरए में मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) लागू करना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से अपनी eodc.online वेबसाइट में ईओडीसी स्थिति को अपडेट करना चाहिए। समय पर सूचना साझा करने, ईओडीसी की स्थिति का समाधान करने और छोड़े गए शुल्क के आकार में शामिल सरकारी राजस्व की वसूली के लिए डीजीएफटी और सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच, आवधिक बैठकें निरंतर तरीके से आयोजित की जा सकती हैं। डीजीएफटी/डीओआर द्वारा योजना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि डीजीएफटी और सीमा शुल्क क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच आवधिक बैठकों के निर्देश जारी किए गए हैं (दिसंबर 2020) जिसमें आरए को ईओडीसी की स्थिति का मिलान करने और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए एचबीपी/एफटीपी और एफटीडीआर अधिनियम 1992 में यथा निर्धारित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीओआर ने कहा (फरवरी 2021) कि यह ऑनलाइन ईओडीसी प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के साथ संपर्क कर रहा है। डीओआर ने उन लंबित प्राधिकारों का विवरण प्रदान करने के लिए डीजीएफटी से अनुरोध किया (मई 2019) जहां ईओ की अवधि खत्म हो गई है और ईओडीसी/मोचन पत्र जारी नहीं किया गया है और क्षेत्रीय संरचनाओं को आवधिक बातचीत के लिए जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों से मिली सूचना के अनुसार ऐसी किसी भी बैठक का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। मुंबई कार्यालय ने कहा कि लेखापरीक्षा में टिप्पणी किए जाने के बाद बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसकी टिप्पणी किए गए अखिल भारतीय मामलों के भारी लंबन के साथ भी पुष्टि होती है। मुख्यालय स्तर पर भी डीजीएफटी और डीओआर के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की आवश्यकता है और डीजीएफटी/ डीओआर द्वारा समय-समय पर बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश दिए जाने/निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.3 निर्यात निष्पादन का पता लगाने और चूककर्ता एएच पर कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र में दोष

सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 16 (मई 2017) में निर्यात दायित्व के निर्वहन का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एएच को सीमा शुल्क द्वारा सामान्य नोटिस जारी करने का निर्धारण किया गया है। यदि एएच डीजीएफटी को अपने आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करता है और ईओडीसी जारी करने की प्रक्रिया चल रही है तो इस मामले को स्थगित रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं को संस्थागत तंत्र के माध्यम से डीजीएफटी के साथ बातचीत करनी चाहिए। धोखाधड़ी या अपवंचन के मामले में, क्षेत्रीय संरचनाओं को सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

सीमा शुल्क पत्तनों में एए से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

तालिका 3.15: कमजोर संस्थागत तंत्र के कारण निर्यात निष्पादन की निगरानी न करना

क्र.सं.	आयुक्तालय का नाम	एए की संख्या	टिप्पणियां
1	चेन्नई समुद्री पत्तन और तूतीकोरिन	19	एएच ने 19 एए में निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, हालांकि ईओपी की अवधि समाप्त हो गई और कोई विस्तार नहीं मांगा गया। इन एए के प्रति ₹ 9.00 करोड़ के परित्यक्त शुल्क के साथ ₹ 50.26 करोड़ का आयात किया गया था। विभाग ने प्रारंभिक मांग पत्र जारी किया लेकिन राजस्व की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई एससीएन जारी नहीं किया गया।
2	हैदराबाद सीमाशुल्क	93	1,343 अमोचित एए में से 93 एए में ₹ 309.67 करोड़ परित्यक्त शुल्क के साथ ₹ 3674.85 करोड़ का आयात किया गया था, भले ही ईओपी समाप्त हो गई थी और कोई निर्यात नहीं हुआ था।
3	जेएनसीएच और एसीसी मुंबई	19	16 एए फाइलों में कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था भले ही ईओपी की अवधि समाप्त होने के बाद एएच ने डीजीएफटी को मोचन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, 15 एए फाइलों के संबंध में डीजीएफटी के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या एएच ने मोचन के लिए डीजीएफटी में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अन्य तीन उदाहरणों में, हालांकि एससीएन जारी किए गए थे, लेकिन छह से 10 वर्षों के लिए अधिनिर्णयन लंबित था।
4	एसीसी बेंगलुरु	328	₹ 80.15 करोड़ के शुल्क प्रभाव वाले 328 एए के संबंध में एससीएन पर अभी अधिनिर्णयन दिया जाना है जिसमें 2 से 10 वर्ष तक की देरी हो रही है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अवरूद्ध हो रहा है।
5	एसीसी मुंबई	42	एससीएन जारी होने की तारीख से 60 से 1145 दिनों के भीतर 42 फाइलों का अधिनिर्णयन किया गया।
6	जेएनसीएच मुंबई	25	अधिनिर्णयन के विवरण के लिए अनुरोध किया गया था, जो अभी प्रतिक्षित है; हालांकि, उपलब्ध डेटा के अनुसार, 72 से 511 दिनों की अवधि के भीतर 25 मामलों में एससीएन का अधिनिर्णय किया गया था।
	कुल	**526**	

डीओआर ने कहा (दिसंबर 2020) कि राजस्व की रक्षा के लिए इकतरफा अधिनिर्णयन किया जा रहा है क्योंकि अधिकतम मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई

में एएच शामिल नहीं हो रहे हैं। एसीसी बेंगलुरु के संबंध में, ₹ 1.28 करोड़ के राजस्व से जुड़े 13 मामलों पर पहले ही अधिनिर्णयन हो चुका है और शेष लंबित एससीएन को शीघ्र निपटाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अधिनिर्णय किया जा रहा है।

चूककर्ताओं के विरुद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा एससीएन जारी न करना और अधिनिर्णयन प्रक्रिया में देरी दोनों विभाग के बीच समन्वय में कमजोरी और निर्यात निष्पादन का पता लगाने और ठोस कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली या डीजीएफटी के 'eodc.online' के अप्रभावी उपयोग को इंगित करता है। डीजीएफटी को जारी किए गए एए, एससीएन/डिमांड नोटिस को दिए गए विस्तार के बारे में डीओआर को सूचित करना चाहिए और अपने पोर्टल को नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए जिससे सीमा शुल्क द्वारा एक समयबद्ध तरीके में कार्रवाई को सुकर बनाया जा सके।

निष्कर्ष

लाइसेंस के प्रति प्राधिकार की वैधता अवधि के बाद शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना या अतिरिक्त आयात सीमा शुल्क लाइसेंस उपयोग मॉड्यूल में निगरानी तंत्र में दोष को इंगित करता है। इसके अलावा, बांड के निष्पादन का प्राथमिक उद्देश्य एए योजना में यथा निर्धारित नियमों और क्रियाविधियों का उचित अनुपालन सुरक्षित करना है; यह अनुपालन न करने के मामलों में उचित शुल्क और ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक समर्थक प्रतिभूति के रूप में भी कार्य करता है। सीबीआईसी के निर्देशों में यथा निर्धारित समय पर बांडों को रद्द न किए जाने से न केवल वास्तविक एएच की निधियां अवरूद्ध होती हैं बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार को गलत संकेत भी दिया जाता है।

आरए मोचन के लिए दावा करने के लिए एएच पर निर्भर करता है, क्योंकि उन मामलों का पता लगाने के लिए हाल ही में आरए के पास कोई तंत्र मौजूद नहीं था जहां ईओ की अवधि समाप्त हो गई है। अधिक आयातों की निगरानी न करने, आयात पूर्व शर्तों का अनुपालन न करने और निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) के अनुचित विस्तार के उदाहरण देखे गए।

लाइसेंसों के पुनर्वैधीकरण की मांग के लिए एफटीपी/एचबीपी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी ऐसे अनुरोध मांगे जाते हैं। चूंकि लाइसेंस की वैधता एचबीपी के पैरा 2.16 में

निर्दिष्ट है (निर्गम तिथि से 12 माह) और प्राधिकार भी आयात/निर्यात (एचबीपी के पैरा 2.18) की तारीख को वैध होना चाहिए, लेखापरीक्षा की राय में पुनर्वैधीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर केवल लाइसेंस की वैधता के भीतर ही विचार किया जाना चाहिए।

आरए परिशिष्ट 4एच/4ई के तहत यथापेक्षित निर्याततित मदों के विनिर्माण में वास्तव में उपभोग किए गए सभी इनपुट की घोषणा के लिए जोर नहीं देते हैं। लेखापरीक्षा की राय है कि केवल आयातित इनपुट के सीआईएफ मूल्य पर विचार करने की प्रथा मूल्य वर्धन की पूरी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। देशी आपूर्तियों के मूल्य को शामिल न करना, जीएसटी/कमीशन/आईजीएसटी राशि पर गलत विचार करना और एएच द्वारा वास्तविक आयात की घोषणा न करना लेखापरीक्षा में देखा गया जो शुल्क मुक्त आयातों के विपथन के जोखिम के साथ-साथ योजना के दुरुपयोग से भरा हुआ है। आरए गैर-घोषित माल के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है और गलत तरीके से प्राप्त छूट को अननुमत करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है।

मोचन/ईओडीसी आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा सक्रिय न होने के परिणामस्वरूप ईओडीसी जारी करने में देरी हुई और संव्यवहार लागत और समय में वृद्धि हुई। हालांकि मोचन आवेदन ऑनलाइन फाइल किए गए थे, लेकिन लेखापरीक्षा 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान बीई, एसबी, ई-बीआरसी, इनपुट और एक्सपोर्ट खपत और प्रमाण-पत्र जैसे सभी दस्तावेजों को मैन्युअल रूप से दाखिल करना जरूरी था। मोचन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण और लाइसेंस डेटा के साथ इसके एकीकरण से देरी को कम करने और मोचन आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित 15 दिनों के बेंचमार्क को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

एक प्रभावी ऑनलाइन मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) के अभाव में, सीबीआईसी को अक्सर डीजीएफटी द्वारा प्रदान की गई ईओडीसी स्थिति का पता लगाने के लिए एएच पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी तरह डीजीएफटी को उन मामलों के लिए शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनमें ईओ की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। डीजीएफटी द्वारा ईओडीसी डेटा का संप्रेषण न करने/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा ईओडीसी डेटा का उपयोग न करने के परिणामस्वरुप बांडों को बंद करने में विलंब होता है और लंबित मामलों में वृद्धि होती है।

चूककर्ताओं के विरूद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा एससीएन जारी न करना और अधिनिर्णय प्रक्रिया में देरी दोनों विभागों के बीच समन्वय में कमजोरी और निर्यात निष्पादन का पता लगाने और ठोस कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी की ईडी प्रणाली या डीजीएफटी के '*eodc.online*' के अप्रभावी उपयोग को इंगित करता है। डीजीएफटी को एए को प्रदान किए गए विस्तार, जारी किए गए एससीएन/डिमांड नोटिस के बारे में डीओआर को अधिसूचित करना चाहिए और अपने पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए जिससे सीमा शुल्क द्वारा समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को सुकर बनाया जा सके।

सिफारिशें

9. ***सीबीआईसी उपयुक्त बांड नवीकरण/रद्दीकरण को सुनिश्चित करने के लिए और ईओडीसी प्रास्थिति को अभिनिश्चित करने के लिए एएच पर निर्भर होने की आवश्यकता के नियकरण के लिए ईओ अवधि की समाप्ति के लिए एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली पर विचार कर सकता है।***

10. ***डीजीएफटी को ईओ के निरन्तर रूप् से और नियमित रूप से मानीटरन के लिए एक प्रभावी तंत्र रखने की आवश्यकता है। अब तक ऐसे मामलों पर नज़र रखने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जहां ईओपी समाप्त हो गयी थी और ईओडीसी प्रास्थिति को सभिनिश्चित करने के लिए आरए एएच पर निर्भर थे। एए के संभावित दुरूपयोग को कम करने के लिए देशी इनपुट के प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातित इनपुट के संभावित विपथन को संबोधित करने के लिए डीजीएफटी के ईडीआई सिस्टम में वैधीकरण जांचों के होने के आवश्यकता है।***

11. ***डीजीएफटी को पुनर्वैधीकरण प्रदान करने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्वैधीकरण के लिए अनुरोधों को केवल प्राधिकार की वैधता अवधि के अन्दर ही स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि निर्यात दायित्व के लिए गणना किए गए कोई भी शुल्क मुक्त आयात या निर्यात प्राधिकार की वैद्धता अवधि के अन्दर हो।***

12. ***डीजीएफटी परिशिष्ट 4 एच में पूर्ण प्रकटन के लिए जोर दे सकता है जिसमें, एएच से "घरेलू अधिप्राप्त इनुपुट सहित निर्यातित माल के विनिर्माण में उपयुक्त सभी इनपुट और एसी अधिप्राप्ति के स्रोत के विवरण" घोषित करने की अपेक्षा की गयी है। जो आरए द्वारा वास्तविक खपत की बेहतर निगरानी को***

सुकर बनाने के लिए है जिससे शुल्क मुक्त आयातों के विपथन और योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

13. *डीजीएफटी को 15 दिनों की अपनी निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने के लिए ईओडीसी को जारी करने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा यह सुनिश्चित करके करनी चाहिए कि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल पूर्ण और मुकम्मल आवेदनों को स्वीकार करने के आनलाईन माडयूल को फिर से बनाया गया है।*

14. *डीजीएफटी और सीमा शुल्क के बीच सूचनाओं के प्रभावी और समय पर आदान-प्रदान के लिए डीजीएफटी को अपने सभी आरए में मैसेज एक्सचेंज मॉड्यूल (एमईएम) लागू करना चाहिए और साथ ही नियमित रूप से अपनी* eodc.online *वेबसाइट में ईओडीसी स्थिति को अपडेट करना चाहिए। समय पर सूचना साझा करने, ईओडीसी की स्थिति का समाधान करने और छोड़े गए शुल्क के आकार में शामिल सरकारी राजस्व की वसूली के लिए डीजीएफटी और सीमा शुल्क की क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच, आवधिक बैठकें निरंतर तरीके से आयोजित की जा सकती हैं। डीजीएफटी/डीओआर द्वारा योजना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू की जा सकती है।*

अध्याय IV
आंतरिक नियंत्रण प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण को मोटे तौर पर एक इकाई के प्रबंधन द्वारा प्रभावित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संचालन की प्रभावशीलता और दक्षता के उद्देश्यों की प्राप्ति, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र न केवल निवारक के रूप में कार्य करता है बल्कि धोखाधड़ी की गतिविधियों की संभावना को भी कम करता है और अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करता है। लेखापरीक्षा ने मानदंड जैसे निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन, आंतरिक/विशेष लेखा परीक्षा, डेटा प्रबधन की प्रणाली, लेखाकरण और आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आंतरिक अभिलेखन का सत्यापन किया और निम्नलिखित कमियों को पाया:

- आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा की अपर्याप्त निगरानी (पैरा 4.1);
- एससीएन जारी करने/अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा का अभाव (पैरा 4.2);
- सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के अनुसार एमआईएस रिपोर्ट और डेटा में बेमेलता (पैरा 4.3);
- अन्य अनियमितताएं (पैरा 4.4)

4.1 आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा की अपर्याप्त निगरानी

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 7.10 के अनुसार, एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) चालू रहेगी, जिसमें प्रत्येक महीने डीजीएफटी मुख्यालय में कंप्यूटर प्रणाली, यादृच्छिक आधार पर, प्रत्येक आरए के ऐसे 10 प्रतिशत मामलों का चयन करेगी, जहां लाभों को पहले ही प्रदान किया जा चुका है। ऐसे मामलों की जांच संबंधित आंचलिक अतिरिक्त डीजीएफटी के कार्यालय में संयुक्त डीजीएफटी की अध्यक्षता वाली एक आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा की जाएगी। टीम न

केवल अपने कार्यालय के लिए दावों बल्कि जोन के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी आरए के दावों की लेखापरीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। संबंधित आरए या तो आंतरिक/बाह्य लेखापरीक्षा एजेंसी की रिपोर्ट या स्व-प्रेरणा के आधार पर भी किसी मामले का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, जहां कोई त्रुटिपूर्ण/अपात्र भुगतान किया गया हो/दावा किया गया हो। आरए, वसूली योग्य राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के साथ भुगतान की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

एफटीपी के पैरा 4.07 (ix) में आगे यह निर्दिष्ट है कि डीजीएफटी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति स्व-संपुष्टि योजना के तहत जारी एए से संबंधित विनिर्माण की लेखापरीक्षा कर सकता है। इस तरह की लेखापरीक्षा को प्राधिकार जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आरएमएस के आधार पर किया जा सकता है। उप-पैरा (x) में आगे कहा गया है कि डीजीएफटी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति मामले के स्वरूप और जटिलता एवं सरकार के राजस्व को ध्यान में रखते हुए एक विशेष लेखापरीक्षा शुरू कर सकता है, यदि संवीक्षा/जांच/पूछताछ के किसी भी चरण में उसका यह मत है कि मानदंडों का सही दावा नहीं किया गया है या अधिक लाभ प्राप्त किए गए हैं।

नौ आरए (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद, लुधियाना, पानीपत, वडोदरा और विशाखापट्टनम) में देखा गया था कि स्व-संपुष्टि योजना के तहत मामले होने के बावजूद कोई आंतरिक लेखापरीक्षा या विशेष लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

मुंबई और पुणे आरए में यह देखा गया कि एमओएफ के पीएओ द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा कराई जा रही है जो डीजीएफटी के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है और जिसका दायरा आरएमएस आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा से भिन्न है। आरए मुंबई और पुणे द्वारा विशेष लेखापरीक्षा के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

आरए बेंगलुरु, हैदराबाद और विशाखापत्तनम को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एए मामलों का आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आरए के पास ऐसा कोई तंत्र मौजूद है। इस संबंध में अनुरोध/अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद भी

सीएलए दिल्ली द्वारा आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा कराने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी।

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए श्रमबल की उपलब्धता की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि आरए बेंगलुरु, मुंबई और कोच्चि में आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा के लिए कोई अलग पद मौजूद नहीं था या श्रमबल आवंटित नहीं किया गया और आरए मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोच्चि में स्टाफ की कमी देखी गई।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि सभी आरए को आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रगति पर है या क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। डीजीएफटी ने आगे कहा (जुलाई 2021) कि डीजीएफटी मुख्यालय में कोई अलग आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं बनाया गया है और आरए/सीएलए में आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कोई अलग पद निर्दिष्ट नहीं है, तथापि, कुछ आरए ने अपना लेखापरीक्षा विंग बनाया है। डीजीएफटी मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा सीसीए, डीओसी द्वारा गठित पीएओ टीम द्वारा की जाती है।

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा संबंधी प्रभावी नीति के अभाव ने उन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी न करने में योगदान दिया था जिसमें अन्य कार्यों के बीच इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देकर विभिन्न माल के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए गए। क्षेत्रीय स्तर पर बहुत से आरए ऐसे किसी तंत्र से अनजान हैं।

सिफारिश संख्या 15: आंतरिक लेखापरीक्षा, सुधार करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है और इसलिए आंतरिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है। डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक लेखापरीक्षा में उचित रूप से स्टाफ दिया गया है और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, विशेष लेखापरीक्षा की परिकल्पना विशेष रूप से उन मामलों के लिए की गई थी जिनमें एए स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत जारी किए जाते हैं और इसलिए गलत घोषणाएं करने वाले आवेदकों के लिए निवारक के रूप में कार्य

करने के लिए कम से कम कुछेक मामलों में परीक्षण के तौर पर लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि सभी आरए को आंतरिक लेखापरीक्षा और विशेष लेखापरीक्षा कराने का भी निर्देश दिया गया है जिसमें कुछ परीक्षण जांचें करके स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत एए जारी किए जाते हैं।

बाद के लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति की निगरानी की जाएगी।

4.2 आरए द्वारा प्राधिकार और ईओ पूर्ति की शर्तों की निगरानी न करना

एफटीडीआर अधिनियम 1992 को 7 अगस्त 1992 से लागू किया गया था ताकि आयात को सुगम बनाकर और भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन का प्रावधान किया जा सके। एफटीडीआर अधिनियम, 1992 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13, अधिनिर्णयन प्राधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत एससीएन जारी करने के बाद लाइसेंस की किसी भी शर्त उल्लंघन या ईओ को पूरा करने में विफलता के के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति देती है।

लेखापरीक्षा ने यह देखने के लिए आरए के लिए स्थापित तंत्र की समीक्षा की कि क्या एएच द्वारा लाइसेंसों की शर्तों और ईओ की पूर्ति का अनुपालन किया जा रहा था जो यह जांच करके पता किया कि क्या एससीएन/अधिनिर्णय आदेशों की सूची का विधिवत रखरखाव किया जाता है, एससीएन/अधिनिर्णय जारी करने में लगने वाला समय और यह भी की क्या कोई वसूली तंत्र लागू है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एससीएन जारी करने और बाद में उसके अधिनिर्णय के लिए अधिनियम में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। एससीएन/अधिनिर्णय आदेश जारी करने के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा के अभाव में, आरए, लाइसेंस की शर्तों के किसी उल्लंघन या ईओ को पूरा करने में विफलता के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप एससीएन के जारी करने में/उसके अधिनिर्णय में अत्यधिक विलंब हुआ जैसा कि यहां नीचे सोदाहरण दर्शाया गया है:

(i) आरए मुंबई में, 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान 1,074 प्राधिकारों में एससीएन जारी करने में लगने वाला समय 2 से 17 वर्ष तक

था। 396 मामलों में पीएच की गई, फैक्टशीट तैयार की गई लेकिन दो से तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई अधिनिर्णय आदेश जारी नहीं किए गए। अन्य मामलों में एससीएन जारी होने के बाद भी सुनवाई की कार्यवाही और कार्यवाही के निष्कर्ष आवधिक रूप से नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा में आरए मुंबई और पुणे में 25 नमूना मामलों की जांच की गई और एससीएन जारी करने और उनके अधिनिर्णय में देरी के लिए कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं पाया गया । ईडीआई के डेटा के अनुसार, आरए मुंबई ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान 374 एससीएन का अधिनिर्णय किया था और ₹ 432.26 करोड़ की दंड राशि लगायी थी। लेखापरीक्षा में जांच की गई दो नमूना अधिनिर्णय फाइलों में जनवरी/फरवरी 2018 में लगाई गई ₹ 46 करोड़ की दंड राशि शामिल थी और मामले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं।

(ii) आरए बंगलुरु में, 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान 949 एससीएन जारी किए गए थे, जिनमें से केवल 51 मामलों (5.37 प्रतिशत) पर ही अधिनिर्णय हो सकता था जिसमें ₹824.17 लाख की दंड राशि शामिल है। हालांकि आज तक कोई वसूली नहीं हो सकी।

(iii) आरए हैदराबाद में, 229 एए के संबंध में 229 एससीएन जारी किए गए थे; हालांकि, किसी का भी अधिनिर्णय नहीं किया गया। आगे की जांच से पता चला कि 2001-02 से 2017-18 से संबंधित चूक के लिए 2018-19 में 228 एससीएन (कुल 229 एससीएन में से) जारी किए गए थे। आरए को एससीएन जारी करने में 17 वर्ष तक का समय लगा।

(iv) आरए जयपुर में, समीक्षा में शामिल अवधि के दौरान आठ एससीएन 67 से 981 दिनों तक की देरी के साथ जारी किए जा सके। सात महीने से छह वर्ष तक की देरी के साथ केवल छह एससीएन का ही अधिनिर्णय किया जा सका। हालांकि, किसी भी मामले में आज तक कोई वसूली (₹29.00 लाख की दंड राशि में) नहीं की जा सकी है।

(v) आरए कटक, जयपुर और कोलकाता में एससीएन/अधिनिर्णय रजिस्टर का सही रखरखाव नहीं किया गया था।

(vi) जारी किए गए एससीएन या किए अधिनिर्णय का विवरण तीन आरए (अहमदाबाद, दिल्ली और वडोदरा) द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि इस मामले को हल करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और देरी के लिए श्रमबल की कमी जैसे कारणों के निपटान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

एससीएन और अधिनिर्णय आदेश जारी करने के लिए एफटीडीआर अधिनियम में विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कार्रवाई किए जाने वाले सभी मामलों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक ही तरीके से निपटाया जाना चाहिए और जिससे सरकारी राजस्व के अवरोधन को कम करने में भी मदद मिलेगी।

सिफारिश संख्या 16: डीजीएफटी, समय पर और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णय प्रक्रिया के बेहतर नियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी करने और अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि ईसीए डिवीजन ने एफटीडीआर अधिनियम के तहत अधिनिर्णय कार्यवाही के लिए सभी आरए को मॉडल दिशानिर्देश और समय-सीमा जारी किए है (जनवरी 2021), और अधिनिर्णय कार्यवाही की व्यापक निगरानी के लिए लागू की जा रही नई आईटी प्रणाली का भी उल्लेख किया है।

इस संबंध में प्रगति को आगामी लेखापरीक्षाओं में देखा जाएगा।

4.3 सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली के अनुसार एमआईएस रिपोर्ट और डेटा में बेमेलता

डीजीएफटी की एमआईएस रिपोर्ट, आरए के परिचालन पहलुओं/प्रदर्शन/कार्यभार का निर्धारण करने के लिए बहुमूल्य इनपुट्स प्रदान करता है। आरए को विभिन्न सूचनाओं की जाँच करनी होती है अर्थात प्रसंस्कृत विभिन्न आवेदनों का विवरण, एनसी को भेजे गए मामले, ईओ निगरानी, एससीएन/अधिनिर्णय, न्यायालय में मामले, स्वीकृत संख्या और पीआईपी जो सांख्यिकी संभाग द्वारा आरए के विभिन्न अनुभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर संकलित किए जाते हैं। डीजीएफटी द्वारा निगरानी आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों के आधार पर की जाती है।

डीजीएफटी को प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्ट की जब सीमा शुल्क ईडीआई डेटा से तुलना की गई तो उस की समीक्षा से तीन आरए में विसंगतियों का पता चला जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

आरए मुंबई में, वित्तीय वर्ष 01 से वित्तीय वर्ष 17 तक की अवधि के लिए प्रति-सत्यापन से गैर-मोचन वाले लाइसेंस के 956 मामलों, जारी किए गए एससीएनएस के 331 मामलों और जारी न किये गए एससीएन के 1,287 मामलों में बेमेलता का पता चला। इसके अलावा एमआईएस-4 रिपोर्ट में एक कमी है क्योंकि इसमें जारी किए गए एससीएन/मांग नोटिस के लंबित होने और उनके लंबित होने के कारणों का आयु-वार विश्लेषण नहीं दिया गया है।

इसी तरह, आरए पुणे में, वित्तीय वर्ष 09 से वित्तीय वर्ष 19 तक की अवधि के लिए गैर-मोचन वाले मामलों में बेमेलता की संख्या 85 थी। डीजीएफटी को प्रस्तुत की गई एमआईएस रिपोर्ट में एससीएन के लंबित होने का विवरण नहीं दिया गया है। इसका पता चलने पर यह बताया गया था कि 59 एससीएन 1 से 2.5 वर्ष तक की अवधि के लिए लंबित हैं।

आरए जयपुर में, 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए एए की संख्या और उस पर सीआईएफ मूल्य, डीजीएफटी को भेजी गई एमआईएस रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाती थी, जिसमें 43 एए का अंतर था, जिसमें ₹540.86 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल था।

आरए जयपुर ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए जनवरी 2020 में मौजूदा एमआईएस-4 रिपोर्ट को सही किया। हालांकि, पहली एमआईएस रिपोर्ट में डेटा के बेमेल होने के कारणों को व्यक्त नहीं किया गया था।

आरए द्वारा प्रस्तुत की गई एमआईएस रिपोर्टों की डीजीएफटी द्वारा पर्याप्त निगरानी/मिलान नहीं किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सूचनाओं की रिपोर्टिंग न करने को आरए के साथ उठाया नहीं जा रहा है। कार्रवाई शुरू करने में देरी के साथ-साथ मांग नोटिस/एससीएन के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप भारी संचित लम्बन हुआ। एफटीपी में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी और कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किए गए थे जिसमें कार्रवाई शुरू करने और चूककर्ताओं के विरुध कानूनी कार्यवाही तेज करने के निर्देश थे।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि eodc.online की सुविधा डाटाबेस इंटरफेस प्रदान करती है और इस मामले को हल करने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सिफारिश संख्या 17: डीजीएफटी को आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी करने की आवश्यकता है और गलत/गैर-रिपोर्टिंग के दृष्टांतों को आरए के साथ उठाया जा सकता है। एमआईएस रिपोर्ट से मिली सूचना के आधार पर डीजीएफटी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि नई आईटी प्रणाली शुरू किए जाने के साथ (1 दिसंबर 2020), यह योजना अब पेपरलेस है जिसमें 100 प्रतिशत सटीकता के साथ ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार की जाएगी और मास्टर रजिस्टर के गैर-रखरखाव या बेमेल होने का कोई सवाल ही नहीं है।

आगामी लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति पर नजर रखी जाएगी। एमआईएस रिपोर्टों से एकत्रित सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।

4.4 अन्य अनियमितताएं

4.4.1 मास्टर रजिस्टर का रखरखाव/अद्यतन न करना

एचबीपी 2015-20 के नियम 4.44 (ए) यह निर्धारित करता है कि ईओपी की आरम्भ और समापन तिथियों और ईओ की प्रभावी निगरानी के लिए अन्य विवरणों को दर्शाते हुए आरए एक मास्टर रजिस्टर में उचित रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा ताकि चूककर्ता एएच के विरुध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच आरए (कटक, दिल्ली, पानीपत, पटना और वाराणसी) में मास्टर रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था और अन्य पांच आरए (हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर और विशाखापट्टनम) में ठीक से अद्यतन नहीं किया गया था।

आरए हैदराबाद में, एक मामले को उजागर किया गया है जहां ईओ की पूर्ति की प्रभावी निगरानी नहीं की जा रही थी, भले ही मास्टर रजिस्टर का भौतिक और कंप्यूटर सिस्टम (एलईएमआईएस) दोनों में रखरखाव किया गया था। मोचन न

किए गए 1,343 में से 93 एए में, जहां ईओपी समाप्त हो गया था, तब भी कोई निर्यात नहीं किया गया था, भले ही एएच ने इन मामलों में ₹309.67 करोड़ के छोडे गए शुल्क के साथ शुल्क मुक्त माल का आयात किया था। चार उदाहरणों में इस संबंध में एएच के साथ कोई संवाद नहीं किया गया। एक मामले में, अधिक आयात केवल एए के मोचन के समय देखा गया। इसके अलावा, पुनर्वैधीकरण/विस्तार/ वृद्धि/अवैधीकरण के संशोधन आदेशों को मास्टर रजिस्टर में अद्यतन नहीं किया गया था।

डीजीएफटी ने कहा (फरवरी 2021) कि 'eodc.online' ऑनलाइन मॉड्यूल, ईओ की स्थिति की निगरानी करता है जिससे लंबित मामलों के विवरण की जांच की जा सकती है। अब सभी ईओडीसी प्रणाली से उत्पन्न होते हैं जो स्वयं मास्टर रजिस्टर के रूप में काम कर सकते हैं।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान मास्टर रजिस्टर के अभाव में, आरए के पास न तो ईओ की पूर्ति निर्धारित करने के लिए कोई तंत्र था जब तक एएच द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और न ही आरए, एएच से ईओ की पूर्ति के लिए विवरण मांग सकता था। इसके अलावा, आरए ऐसे आवश्यक अभिलेखों के अभाव में आगे लाइसेंस से इनकार करने, लाइसेंस की शर्तों को लागू करने या शुल्क/ब्याज की वसूली के साथ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने जैसी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं थे। ऑनलाइन कार्यात्मकताओं का केवल 1 दिसंबर 2020 से कार्यान्वयन किया जाना बताया गया था और इसकी समीक्षा आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

4.4.2 नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातुओं के आयात के लिए गैर-निगरानी

एचबीपी के पैरा 4.94 यह निर्धारित करता है कि नामित एजेंसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चार/पांच सितारा निर्यात गृह आरए में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप-पैरा (बी) (iii) में यह उल्लेखित है कि आरए जो नामित एजेंसी प्रमाण पत्र जारी करता है, ऐसी एजेंसियों द्वारा भरे जाने वाले एचबीपी के परिशिष्ट-4 एम के अनुसार छमाही रिटर्न के आधार पर ऐसे प्रमाण पत्र धारकों के निष्पादन की निगरानी करेगा। आरए, डीजीएफटी को नॉन फाइलर्स के बारे में भी जानकारी देंगे और नामित एजेंसी प्रमाण-पत्र के निलंबन/रद्द करने के लिए

30 दिन के भीतर उचित कार्रवाई भी करेंगे। डीजीएफटी मुख्यालय जब भी आवश्यक हो, नामित एजेंसियों के निष्पादन की समीक्षा भी कर सकता है।

आरए बेंगलुरु ने गोल्ड बार/मेडेलिऑंस के आयात/निर्यात में शामिल मेसर्स एक्स एक्सपोर्ट्स (एक स्टार हाउस निर्यातक) को नामित एजेंसी प्रमाण-पत्र जारी किया। तथापि, आरए, अर्द्धवार्षिक रिटर्न दाखिल न करने या नामित एजेंसी प्रमाण पत्र के निलंबन/रद्द करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने के बारे में डीजीएफटी को रिपोर्ट करने में विफल रहा।

4.4.3 एनसी को भेजे गए मामलों की अपर्याप्त निगरानी

एनसी को भेजे गए मामलों की निगरानी आरए द्वारा की जा रही है और इस संबंध में एमआईएस-3 रिपोर्ट को मासिक आधार पर डीजीएफटी मुख्यालय को भेजे जाने की आवश्यकता है। एमआईएस-3 रिपोर्ट बिना मानदंड श्रेणी से संबंधित लंबित मामलों की एक उत्पाद समूहवार सूची है जिसे मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए आरए द्वारा एनसी को भेजा जाता है। इसे सांख्यिकी संभाग द्वारा विभिन्न अनुभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर संकलित किया जाता है। यह डीजीएफटी के ईडीआई प्रणाली से अपने आप जेनरेट नहीं होता है।

आरए कोच्चि में, एनसी को भेजे गए एए से संबंधित सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध नहीं थी और मुख्यालय को प्रस्तुत एमआईएस-3 रिपोर्ट को इस आधार पर शून्य के रूप में दर्शाया गया था कि एएच ने सीधे एनसी को मानदंडों के निर्धारण के लिए आवेदन भेजा है, जो एनसी को भेजे गए एए मामलों की अप्रभावी निगरानी का संकेत है।

डीजीएफटी ने नई आईटी प्रणाली (1 दिसंबर 2020) के साथ, कहा (फरवरी 2021) कि आरए द्वारा ईओडीसी जारी करने में देरी का समाधान किया जाएगा। नीति परिपत्र 23 (मई 2019) में स्व-घोषणा के तहत जारी किए गए एए के लिए आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को सीधे एनसी को अग्रेषित करने को अनुबद्ध किया गया है जब एसआईओएन मौजूद नहीं है और इसलिए एनसी को भेजे गए मामलों को शून्य के रूप में दर्शाया गया था।

उक्त नीति परिपत्र का प्रयोजन ऑनलाइन आवेदन और एनसी द्वारा दस्तावेजों की प्राप्ति के बीच समय अंतराल को कम करने के लिए किया गया था और इसलिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों को सीधे एनसी को अग्रेषित करने की

अनुमति दी गई थी। चूंकि एए को आरए क्षेत्राधिकारिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता हैं, इसलिए लेखापरीक्षा का मानना है कि आरए को अपनी एमआईएस-3 रिपोर्ट में एनसी को भेजे गए एए को दर्शाना चाहिए और डीजीएफटी द्वारा इसकी निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

आंतरिक/विशेष लेखापरीक्षा संबंधी प्रभावी नीति के अभाव ने इस योजना के कार्यान्वयन की गैर-निगरानी में योगदान दिया था जिसमें अन्य कार्यों के बीच इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करके विभिन्न माल के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई आरए ऐसे किसी तंत्र से अनजान थे।

एससीएन और अधिनिर्णय आदेश जारी करने के लिए एफटीडीआर अधिनियम में विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि कार्रवाई किए जाने वाले सभी मामलों को बिना किसी पूर्वाग्रह के एक ही तरीके से निपटाया जाए। इससे सरकारी राजस्व के अवरोधन को कम करने में भी मदद मिलेगी।

आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की डीजीएफटी द्वारा पर्याप्त निगरानी/मिलान नहीं किया जा रहा है और महत्वपूर्ण सूचनाओं की रिपोर्टिंग न करने को आरए के साथ उठाया नहीं जा रहा है। कार्रवाई शुरू करने में देरी के साथ-साथ मांग नोटिस/एससीएन के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप भारी संचित लम्बन हुआ। एफटीपी में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किए गए थे जिसमें कार्रवाई शुरू करने और चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तेज करने के निर्देश थे।

सिफारिशें

15. ***आंतरिक लेखापरीक्षा, सुधार करने के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है और इसलिए आंतरिक नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है। डीजीएफटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंतरिक लेखापरीक्षा में उचित रूप से स्टाफ दिया गया है और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, विशेष लेखापरीक्षा की परिकल्पना विशेष रूप से उन मामलों के लिए की गई थी जिनमें एए स्व-संपुष्टि/घोषणा के तहत जारी किए जाते हैं और इसलिए गलत***

घोषणाएं करने वाले आवेदकों के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के लिए कम से कम कुछेक मामलों में परीक्षण के तौर पर लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी।

16. ***डीजीएफटी, समय पर और प्रभावी तरीके से अधिनिर्णय प्रक्रिया के बेहतर नियमन को लागू करने के लिए एससीएन जारी करने और अधिनिर्णय के लिए समय-सीमा तय करने पर विचार कर सकता है।***

17. ***डीजीएफटी को आरए द्वारा प्रस्तुत एमआईएस रिपोर्टों की निगरानी करने की आवश्यकता है और गलत/गैर-रिपोर्टिंग के दृष्टांतों को आरए के साथ उठाया जा सकता है। एमआईएस रिपोर्ट से मिली सूचना के आधार पर डीजीएफटी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।***

के माथुर

नई दिल्ली | **(कार्तिकेय माथुर)**
दिनांक: 28 अक्तूबर OCT 2021 | **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 29 अक्तूबर OCT 2021 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट और अनुलग्नक

परिशिष्ट 1 : नमूना चयन (पैरा 1.7/अध्याय I)							
क्र सं	**चयनित आरए का नाम**	**जारी कुल एए**	**सीआईएफ ₹करोड़ में**	**चयनित नमूना**	**एमवी ₹ करोड़ में**	**रिकॉर्ड के गैर उत्पादन (एनपीआर) मामले**	**एनपीआर मामलों का एमवी ₹ करोड़ में**
1	दिल्ली	13193	113776.92	504	13187.37	35	372.42
2	मुंबई	28362	232686.8	873	30163.22	268	7450.54
3	चेन्नई	4431	26797.35	369	1239.89	0	
4	कोलकाता	2772	17024.48	158	6826.79	16	572.52
5	अहमदाबाद	8673	32644.31	398	8924.28	63	1331.5
6	बेंगलुरु	6168	115357.56	424	91487.2	0	
7	हैदराबाद	4628	42789.49	316	12770.54	0	
8	पुणे	1558	11449.8	128	1660.6	16	80.59
9	वडोदरा	3798	70600.27	179	31499.05	0	
10	जयपुर	1219	6133.41	98	1938.61	0	
11	कोयंबटूर	1209	2450.94	118	576.44	0	
12	कोच्चि	878	5247.3	106	1255.76	0	
13	विशाखापत्तनम	152	575.68	24	31.99	0	
14	गुवाहाटी	3	58.65	3	58.65	0	
15	कानपुर	993	2835.65	71	826.99	0	
16	वाराणसी	112	204.11	40	113.98	0	
17	लुधियाना	936	3632.8	69	1233.33	0	
18	चंडीगढ़	855	7799.11	60	1777.25	0	
19	पानीपत	239	1901.25	15	764.93	0	
20	कटक	98	929.26	42	703.35	6	95.52
21	पटना	5	20.93	5	20.95	1	3.62
22	भोपाल	396	3343.89	6	414.57	0	
23	इंदौर	996	5748.17	42	649.82	0	
	कुल	**81674**	**704008.13**	**4048**	**208125.56**	**405**	**9906.73**
24	अन्य 15 आरए	6483	54132.87				
38 आरए का योग		**88157**	**758141**				

अनुलग्नक 1क
(पैरा 2.2/ अध्याय II)

क्र.	आरए का नाम	आरए कोड	वर्ष	फाईलिंग करने की तिथि से प्राधिकार जारी करने के लिए दिनों की संख्या								कुल
				जारी संख्या	3 दिनों तक	4 दिनों - 1महीना	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	
1	**कोलकाता**	**2**	**2015-16**	**578**	115	389	35	13	12	14	0	**578**
			2016-17	**692**	138	428	78	16	18	11	3	**692**
			2017-18	**725**	187	487	37	8	6	0	0	**725**
			2018-19	**691**	117	511	48	13	2	0	0	**691**
2	**मुंबई**	**3**	**2015-16**	**6881**	988	4551	886	246	141	61	8	**6881**
			2016-17	**7370**	1297	4961	790	181	99	36	6	**7370**
			2017-18	**6982**	1075	4896	701	189	69	16	36	**6982**
			2018-19	**7127**	1047	4961	869	145	68	29	8	**7127**
3	**चेन्नई**	**4**	**2015-16**	**1065**	262	640	134	20	3	5	1	**1065**
			2016-17	**1081**	149	779	132	11	4	5	1	**1081**
			2017-18	**1135**	140	873	108	9	1	4	0	**1135**
			2018-19	**1150**	70	954	101	14	6	5	0	**1150**
4	**दिल्ली**	**5**	**2015-16**	**2861**	795	1782	217	49	14	1	3	**2861**
			2016-17	**3175**	1035	1861	229	30	9	6	5	**3175**
			2017-18	**3361**	1260	1872	133	21	28	29	18	**3361**
			2018-19	**3763**	1490	2119	131	21	1	1	0	**3763**
5	**कानपुर**	**6**	**2015-16**	**206**	125	75	4	1	1	0	0	**206**
			2016-17	**241**	145	94	1	1	0	0	0	**241**
			2017-18	**250**	144	100	5	1	0	0	0	**250**
			2018-19	**282**	184	97	1	0	0	0	0	**282**

अनुलग्नक 1क
(पैरा 2.2/ अध्याय II)

क्र.	आरए का नाम	आरए कोड	वर्ष	फाईलिंग करने की तिथि से प्राधिकार जारी करने के लिए दिनों की संख्या								कुल
				जारी संख्या	3 दिनों तक	4 दिनों - 1महीना	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	
6	बंगलुरू	7	2015-16	1410	282	910	161	40	16	1	0	1410
			2016-17	1594	239	1130	192	26	5	2	0	1594
			2017-18	1574	516	930	92	14	11	11	0	1574
			2018-19	1593	612	883	77	13	7	0	1	1593
7	अहमदाबाद	8	2015-16	2121	630	1266	161	44	9	0	11	2121
			2016-17	2168	562	1308	218	55	20	5	0	2168
			2017-18	2061	308	1354	312	69	15	2	1	2061
			2018-19	2322	365	1567	238	89	43	19	1	2322
8	हैदराबाद	9	2015-16	1211	81	954	144	27	5	0	0	1211
			2016-17	1193	55	968	138	20	10	2	0	1193
			2017-18	1091	37	887	139	17	6	4	1	1091
			2018-19	1104	93	852	126	26	5	1	1	1104
9	कोचीन	10	2015-16	228	27	180	17	1	2	1	0	228
			2016-17	237	48	183	5	0	1	0	0	237
			2017-18	172	34	124	14	0	0	0	0	172
			2018-19	239	30	184	21	4	0	0	0	239
10	भोपाल	11	2015-16	42	8	28	4	2	0	0	0	42
			2016-17	62	11	40	7	3	1	0	0	62
			2017-18	55	18	27	5	2	3	0	0	55
			2018-19	237	102	126	5	0	0	1	3	237

अनुलग्नक 1क
(पैरा 2.2/ अध्याय II)

क्र.	आरए का नाम	आरए कोड	वर्ष	फाईलिंग करने की तिथि से प्राधिकार जारी करने के लिए दिनों की संख्या								
				जारी संख्या	3 दिनों तक	4 दिनों - 1महीना	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	कुल
11	जयपुर	13	2015-16	265	23	233	9	0	0	0	0	265
11	जयपुर	13	2016-17	301	46	249	4	0	1	1	0	301
11	जयपुर	13	2017-18	310	57	241	9	3	0	0	0	310
11	जयपुर	13	2018-19	319	98	215	6	0	0	0	0	319
12	गुवाहाटी	14	2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	गुवाहाटी	14	2016-17	2	0	1	1	0	0	0	0	2
12	गुवाहाटी	14	2017-18	1	0	1	0	0	0	0	0	1
12	गुवाहाटी	14	2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	वाराणसी	15	2015-16	33	11	17	5	0	0	0	0	33
13	वाराणसी	15	2016-17	28	5	21	2	0	0	0	0	28
13	वाराणसी	15	2017-18	22	3	16	3	0	0	0	0	22
13	वाराणसी	15	2018-19	29	8	21	0	0	0	0	0	29
14	पटना	21	2015-16	1	0	1	0	0	0	0	0	1
14	पटना	21	2016-17	1	0	0	1	0	0	0	0	1
14	पटना	21	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पटना	21	2018-19	3	0	1	2	0	0	0	0	3
15	चंडीगढ़	22	2015-16	218	63	120	25	5	2	3	0	218
15	चंडीगढ़	22	2016-17	193	93	89	7	1	1	1	1	193
15	चंडीगढ़	22	2017-18	178	68	91	14	3	1	0	1	178
15	चंडीगढ़	22	2018-19	240	58	154	18	9	0	1	0	240

अनुलग्नक 1क
(पैरा 2.2/ अध्याय II)

क्र.	आरए का नाम	आरए कोड	वर्ष	फाईलिंग करने की तिथि से प्राधिकार जारी करने के लिए दिनों की संख्या								
				जारी संख्या	3 दिनों तक	4 दिनों - 1महीना	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	कुल
16	**कटक**	**23**	**2015-16**	**8**	5	3	0	0	0	0	0	**8**
			2016-17	**11**	8	1	1	1	0	0	0	**11**
			2017-18	**51**	37	13	1	0	0	0	0	**51**
			2018-19	**26**	13	12	1	0	0	0	0	**26**
17	**विशाखापट्टनम**	**26**	**2015-16**	**31**	0	21	9	0	1	0	0	**31**
			2016-17	**37**	5	28	4	0	0	0	0	**37**
			2017-18	**38**	0	21	12	3	1	1	0	**38**
			2018-19	**42**	1	29	5	1	6	0	0	**42**
18	**लुधियाना**	**30**	**2015-16**	**220**	120	84	6	8	2	0	0	**220**
			2016-17	**201**	83	93	10	5	5	5	0	**201**
			2017-18	**219**	136	64	9	7	2	1	0	**219**
			2018-19	**279**	189	78	9	2	0	1	0	**279**
19	**पुणे**	**31**	**2015-16**	**537**	117	337	73	6	1	3	0	**537**
			2016-17	**408**	83	251	31	18	18	3	4	**408**
			2017-18	**305**	91	172	29	7	4	2	0	**305**
			2018-19	**308**	108	169	21	6	2	2	0	**308**
20	**कोयम्बटूर**	**32**	**2015-16**	**216**	29	170	16	0	0	1	0	**216**
			2016-17	**252**	42	188	17	5	0	0	0	**252**
			2017-18	**288**	95	186	7	0	0	0	0	**288**
			2018-19	**448**	241	200	7	0	0	0	0	**448**

अनुलग्नक 1क
(पैरा 2.2/ अध्याय II)

क्र.	आरए का नाम	आरए कोड	वर्ष	फाईलिंग करने की तिथि से प्राधिकार जारी करने के लिए दिनों की संख्या								
				जारी संख्या	3 दिनों तक	4 दिनों - 1महीना	1-3 महीने	3-6 महीने	6-12 महीने	1-2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक	कुल
21	पानीपत	33	2015-16	51	10	33	6	1	1	0	0	51
			2016-17	60	10	42	8	0	0	0	0	60
			2017-18	48	15	32	1	0	0	0	0	48
			2018-19	79	28	47	3	0	1	0	0	79
22	वडोदरा	34	2015-16	882	302	517	37	15	8	3	0	882
			2016-17	1041	197	735	80	20	8	1	0	1041
			2017-18	902	106	627	114	34	11	10	0	902
			2018-19	973	193	559	148	54	16	3	0	973
23	इंदौर	56	2015-16	280	135	106	30	7	2	0	0	280
			2016-17	210	101	77	28	4	0	0	0	210
			2017-18	264	125	106	13	5	6	1	8	264
			2018-19	214	64	104	23	17	5	1	0	214
कुल			2015-16	19345	4128	12417	1979	485	220	93	23	19345
			2016-17	20558	4352	13527	1984	397	200	78	20	20558
			2017-18	20032	4452	13120	1758	392	164	81	65	20032
			2018-19	21468	5111	13843	1860	414	162	64	14	21468

अनुलग्नक 1ख : एए जारी करने में देरी (पैरा 2.2/ अध्याय II)				
क्र सं	**आरए का नाम**	**आरए कोड**	**उन मामलों की संख्या जहां डीएल जारी किया गया**	**उन मामलों की संख्या जिनमें डीएल जारी नहीं किया गया**
1	अहमदाबाद	8	6	16
2	वडोदरा	34	0	5
3	जयपुर	13	1	14
4	बेंगलुरु	7	3	0
5	चेन्नई	4	0	6
6	कोयंबटूर	32	0	5
7	कोच्चि	10	13	6
8	दिल्ली	5	0	37
9	इंदौर	56	0	25
10	भोपाल	11	0	4
11	हैदराबाद	9	0	290
12	विशाखापत्तनम	26	18	6
13	कटक	23	0	10
14	कोलकाता	2	25	48
15	गुवाहाटी	14	2	0
16	कानपुर	6	3	4
17	वाराणसी	15	3	9
18	पटना	21	2	0
19	मुंबई	3	111	270
20	पुणे	31	33	37
कुल			**220**	**792**

अनुलग्नक 2 : एए जारी करते समय वित्तीय शक्तियों का पालन न करना (पैरा 2.7.1/ अध्याय II)					
क्र सं	आरए का नाम	आरए कोड	एए तिथि	एफओबी (₹करोड़ में)	सीआईएफ (₹करोड़ में)
1	बेंगलुरु	7	12.05.15	631.482	622.15
2	बेंगलुरु	7	12.05.15	1014.421	999.43
3	बेंगलुरु	7	16.09.15	961.615	947.404
4	बेंगलुरु	7	16.09.15	963.362	949.125
5	बेंगलुरु	7	16.09.15	965.811	951.538
6	बेंगलुरु	7	13.10.16	959.52	945.34
7	बेंगलुरु	7	13.10.16	956.033	941.905
8	बेंगलुरु	7	20.10.16	952.553	938.476
9	बेंगलुरु	7	20.10.16	949.078	935.052
10	बेंगलुरु	7	08.12.16	1013.985	999
11	बेंगलुरु	7	08.12.16	1014.926	999.927

अनुलग्नक 3: प्राधिकार की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद अनाधिकृत आयात (पैरा 3.1.1/ अध्याय III)				
क्र सं	साइट आईडी	शुल्क (₹करोड़ में)	सीआईएफ मूल्य (₹करोड़ में)	मामलों की संख्या
1	आईएनएपीएल6	0.09	0.53	1
2	आईएनबीओएम 4	0.70	6.27	126
3	आईएनसीसीयू 1	0.02	3.64	13
4	आईएनसीसीयू 4	0.25	2.24	51
5	आईएनसीओके 1	0.07	0.88	1
6	आईएनसीपीआर6	0.00	1.22	5
7	आईएनडीईएल 4	3.82	32.37	304
8	आईएनएफबीडी6	0.10	0.91	4
9	आईएनजीएचआर6	0.11	1.99	5
10	आईएनएचवाईडी 4	0.07	0.41	16
11	आईएनएचजेडए 1	0.00	3.16	16
12	आईएनआईएक्सवाई 1	0.15	42.74	20
13	आईएनएलओएन6	0.00	0.69	3
14	आईएनएमएए1	0.02	0.38	18
15	आईएनएमएए4	0.09	0.60	6
16	आईएनएमयूएन 1	0.03	2.28	10
17	आईएनएनएमएल1	0.00	0.66	3
18	आईएनएनएसए 1	19.48	43.25	129
19	आईएनपीपीजी6	0.06	0.71	2
20	आईएनपीटीएल 6	0.01	0.15	1
21	आईएनएसजीएफ6	0.00	0.07	1
22	आईएनएसएनएफ6	0.15	1.78	2
23	आईएनटीकेडी 6	0.22	4.47	49
	कुल	**25.42**	**151.39**	**786**

अनुलग्नक 4: ईओपी का अनुचित विस्तार
(पैरा 3.2.1.4/ अध्याय III)

क्र सं	आरए का नाम	लाइसेंस तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹करोड़ में)	एफओबी मूल्य (₹करोड़ में)	आयात की तिथि	पुनर्वैधिकरन के लिए प्राप्त आवेदन की तिथि	पुनर्वैधिकरन निर्गम की तिथी
1	वाराणसी	26.04.2017	2.90	3.75	26.04.2018	22.05.2018	27.09.2018
2	वाराणसी	15.06.2017	2.30	3.17	15.06.2018	25.06.2018	02.07.2018
3	वाराणसी	01.03.2018	4.47	5.28	01.03.2019	26.03.2019	05.04.2019
4	वाराणसी	31.08.2017	4.52	5.33	31.08.2018	05.10.2018	12.10.2018
5	वाराणसी	30.01.2017	2.74	3.75	30.01.2018	15.02.2018	08.03.2018
6	वाराणसी	01.10.2015	1.06	1.48	01.10.2016	04.01.2017	18.01.2017
7	वाराणसी	07.10.2016	1.75	2.08	07.10.2017	21.11.2017	12.01.2018

अनुलग्नक 5: एएच द्वारा वास्तविक आयात की घोषणा न करना
(पैरा 3.2.3.2/ अध्याय III)

क्र सं	आरए का नाम	आरए कोड	लाइसेंस तिथि	एफओबी में कमी (करोड़ में)	कंपोजीशन फीस 1 प्रतिशत देय	ईओडीसी तिथि
1	चेन्नई	4	20.06.16	0.23	22631	23.06.17
2	चेन्नई	4	08.02.17	0.18	18335	11.07.17
3	चेन्नई	4	08.08.17	0.15	14917	04.06.18
4	चेन्नई	4	14.09.17	0.69	68881	20.07.18
5	चेन्नई	4	21.06.17	0.18	17577	04.06.18
6	चेन्नई	4	14.08.17	0.73	73480	29.07.19
7	चेन्नई	4	08.12.16	0.91	90821	03.01.19
8	चेन्नई	4	19.07.17	0.78	78224	20.06.19
9	चेन्नई	4	18.07.17	0.40	39833	18.07.18
10	चेन्नई	4	12.05.17	0.53	53079	04.06.18
11	कोयंबटूर	32	26.09.16	-3.49	0	22.06.18
12	कोयंबटूर	32	07.04.16	-3.75	0	03.01.18
13	कोयंबटूर	32	10.02.16	0.02	0	09.11.17
					477778	

अनुलग्नक 6: एएच द्वारा ईओडीसी आवेदन जमा करने में देरी (पैरा 3.2.5.2/ अध्याय III)				
क्र सं	**आरए का नाम**	**आरए कोड**	**मामलों की संख्या**	**से लेकर देरी (दिनों में)**
1	चेन्नई	4	19	6 से 546
2	कोच्चि	10	24	14 से 702
3	इंदौर	56	11	46 से 408
4	हैदराबाद	9	100	5 से 749
5	विशाखापत्तनम	26	4	203 से 792
6	कटक	23	3	36 से 69
7	बेंगलुरु	7	1	929
8	जयपुर	13	21	46 से 709
9	लुधियाना	30	3	203 से 432
10	पानीपत	33	4	एक मामले में 473 दिन की देरी और तीन मामलों में ईओडीसी ने आवेदन नहीं किया
11	चंडीगढ़	22	3	ईओडीसी लागू नहीं
		कुल	**193**	

अनुलग्नक 7: ई-बीआरसी के साथ निर्यात शिपिंग बिल/चालान को न जोड़ना (पैरा 3.2.7.2/ अध्याय III)				
क्र सं	आरए का नाम	लाइसेंस तिथि	सीआईएफ (₹करोड़ में)	एफओबी (₹करोड़ में)
1	कानपुर	30.10.2015	31.00	56.91
2	कानपुर	13.04.2015	3.08	4.73
3	कानपुर	23.10.2017	3.05	4.49
4	कानपुर	08.05.2015	2.99	4.73
5	कानपुर	19.08.2015	2.88	4.55
6	कानपुर	26.12.2016	17.09	20.55
7	कानपुर	08.07.2016	14.22	32.94
8	कानपुर	22.09.2015	13.74	31.82
9	कानपुर	19.05.2015	12.96	30.01
10	कानपुर	17.03.2017	32.23	37.07
11	कानपुर	22.03.2016	26.92	30.95
12	कानपुर	05.05.2015	21.33	24.55
13	कानपुर	14.12.2016	19.89	22.90
14	कानपुर	26.04.2016	19.37	22.28
15	कानपुर	12.02.2016	17.43	20.05
16	कानपुर	12.02.2016	17.43	20.05
17	कानपुर	14.05.2015	15.20	17.63
18	कानपुर	22.07.2015	14.52	16.71
19	कानपुर	17.02.2016	14.30	16.45
20	कानपुर	07.01.2016	5.35	6.15
21	कानपुर	28.11.2017	4.20	4.83
22	कानपुर	13.01.2016	4.05	4.66

अनुलग्नक 7: ई-बीआरसी के साथ निर्यात शिपिंग बिल/चालान को न जोड़ना (पैरा 3.2.7.2/ अध्याय III)				
क्र सं	आरए का नाम	लाइसेंस तिथि	सीआईएफ (₹करोड़ में)	एफओबी (₹करोड़ में)
23	कानपुर	05.04.2016	3.07	3.53
24	कानपुर	05.04.2016	3.07	3.53
25	कानपुर	05.04.2016	3.07	3.53
26	कानपुर	09.11.2015	4.51	5.54
27	कानपुर	20.07.2016	4.50	5.40
28	कानपुर	09.02.2017	4.22	4.88
29	कानपुर	22.07.2016	3.89	4.70
30	कानपुर	20.02.2017	3.89	4.70
31	कानपुर	09.11.2015	3.87	4.62
32	कानपुर	18.11.2015	3.75	4.31
33	कानपुर	16.02.2017	3.50	4.03
34	कानपुर	18.08.2017	3.16	3.87
35	कानपुर	22.06.2016	3.04	4.08
36	कानपुर	20.04.2015	2.71	3.26
37	कानपुर	18.02.2016	2.54	3.40
38	कानपुर	05.04.2017	2.50	3.06
39	कानपुर	05.05.2017	2.50	3.06
40	कानपुर	01.01.2016	2.47	2.94
41	कानपुर	29.04.2016	2.47	2.94
42	पटना	13.10.2015	3.35	4.14

2021 की प्रतिवेदन संख्या 10 – संघ सरकार (राजस्व विभाग – अप्रत्यक्ष कर – सीमा शुल्क)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in